चिंतन

चीन के नियम '50' से सीख ले भारत

सुरक्षा रणनीति
डॉ. एन.के. सोमानी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) में यूरोप की सांस्कृतिक चुनौतियों और चीन से मिल रही प्रतिस्पर्धा पर सख्त रुख अपनाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगभग एक साल के कार्यकाल के अंतिम चरण में जारी रणनीति में पश्चिमी गोलार्ध और इंडो-पैसिफिक का जिक्र किया गया है। ड्राफ्ट का स्वरूप बहुत संक्षिप्त होने के बावजूद इसमें भारत को प्राथमिकता देते हुए भारत के साथ संबंधों पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि भारत के साथ बात कर ट्रंप प्रशासन कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश तो नहीं कर रहा है।

अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन अब लगातार अपने देश में बने सामान को ही बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए ड्रैगन 50 फीसदी का नया नियम लेकर आया है। यह नियम सभी चिप कंपनियों पर लागू होगा। इसके तहत अब चीन में लगने वाली नई या पुरानी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए कम से कम 50% उपकरण चीन में ही बने हुए इस्तेमाल करने होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार चाहती है कि देश में ही चिप बनाने का पूरा सामान तैयार हो जाए, ताकि उसे दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। इस नियम का उद्देश्य खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मजबूत करना है। इससे चीन में चिप बनाने वाली कंपनियों को अपने उपकरणों के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना होगा, जिससे चीनी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इस नए नियम का अमेरिकी कंपनियों पर भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें नॉथ्रॉप ग्रुम्मन, एल3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज और बोइंग जैसी बड़ी रक्षा कंपनियां शामिल हैं। वहीं, चीन के नियम-50 से भारत को भी सीख लेनी चाहिए, ताकि भारत का वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मिशन सफल हो सके। बता दें कि यह एक बहुत बड़ा कदम है जो चीन ने उठाया है। चीन अब विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करता जा रहा है। यह कोशिश तब और तेज हो गई, जब साल वर्ष 2023 में अमेरिका ने एक्सपोर्ट पर और सख्त नियम बना दिए थे। अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स और चिप बनाने वाले उपकरण बेचने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अमेरिका के इन नियमों ने कुछ सबसे एडवांस्ड मशीनों की बिक्री रोक दी, लेकिन 50% वाले इस नियम की वजह से चीनी कंपनियां अब उन जगहों पर भी अपने देश के सप्लायर्स को चुन रही हैं, जहां अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के विदेशी उपकरण उपलब्ध हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग लगातार यह कहते रहे हैं कि देश को चिप बनाने के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'पूरे देश' को मिलकर प्रयास करना होगा। भारत भी चीन से इस मामले में कुछ सबक ले सकता है। चिप निर्माण में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अभी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनें, केमिकल और वेफर्स जैसे सामान दूसरे देशों से खरीदता है। ये सामान ताइवान, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आते हैं, लेकिन अब भारत सरकार 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (आईएसएम) के तहत खुद सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है। भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। भारत को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन जैसे नियम को अपनाना चाहिए। भारत को अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। अपने व्यापारिक संबंधों को विविध बनाने और चीन के अलावा अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। भारत को अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और वैश्विक व्यापारिक संगठनों में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा, भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके और देश का आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके।

भारत का साथ जरूरी या केवल दिखावा

चीन और यूरोप के साथ संबंधों में तनातनी के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) में यूरोप की सांस्कृतिक चुनौतियों और चीन से मिल रही प्रतिस्पर्धा पर सख्त रुख अपनाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगभग एक साल के कार्यकाल के अंतिम चरण में जारी रणनीति में पश्चिमी गोलार्ध और इंडो-पैसिफिक का जिक्र किया गया है। ड्राफ्ट का स्वरूप बहुत संक्षिप्त (20 पेज) होने के बावजूद इसमें भारत को प्राथमिकता देते हुए भारत के साथ संबंधों पर विशेष जोर दिया गया है।

ड्राफ्ट में अमेरिका को भारत के साथ वाणिज्यिक, रणनीतिक और अन्य द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि भारत के साथ मजबूत सहयोग से न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी बल्कि भारत को क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। ड्राफ्ट की दिलचस्प बात यह है कि एक तो ट्रंप प्रशासन इसमें रूस के साथ कदम-ताल करते दिख रहा है और दूसरा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान को लगभग गायब कर दिया गया है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है खासतौर से फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए।राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अमेरिका की कार्यकारी शाखा द्वार समय-समय पर तैयार किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें देश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और प्रशासन द्वारा उनसे निपटने की योजनाओं का विवरण दिया जाता है।

गोल्डवाटर-निकोलस अधिनियम के आधार पर निर्मित सुरक्षा रणनीति का कार्यन्वयन राष्ट्रीय सैन्य रणनीति जैसे सहायक दस्तावेज में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार व्हाइट हाउस में आए उस वक्त उन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासनाध्यक्षों द्वारा निर्मित विदेश नीति के सिद्धांतों से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। नई सुरक्षा रणनीति में वह एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2025 की रणनीति में मुख्य फोकस अमेरिकी पहचान तथा संस्कृति को स्थापित करने के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) के आदर्श पर रखा गया है। अमेरिका ने हाल के वर्षों में असाधारण प्रगति हासिल की है और आने वाले समय में वह अपनी राष्ट्रीय-शक्ति के सभी पहलुओं को और सुदृढ करेगा। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि नई रणनीति सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका विश्व इतिहास का सबसे महान और सबसे सफल राष्ट्र रहे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नई सुरक्षा रणनीति का दस्तावेज 'अमेरिका फर्स्ट' की भावना से भरा हुआ हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि न्यू सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भारत के उल्लेख का निहितार्थ क्या है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक जरूरतों को छोड़ कर शेष वैश्विक संदर्भ में अमेरिका भारत को किस नजरिए देखता है, खासकर पाकिस्तान और भारत-रूस मैत्री संबंधों के संदर्भ में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दरअसल जिस तरह से ट्रंप ने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में यूरोप के प्रति खीज का प्रदर्शन किया है और भारत को 'जरूरत के साथी' के तौर पर दिखाया है, उससे साफ है कि पूरा दस्तावेज भ्रम और उलझन का गड़बड़ झाला बन गया है। दस्तावेज कुछ

निश्चित और कुछ अनिश्चित तत्वों की ओर भी संकेत कर रहा है। जहां तक अनिश्चितंता का सवाल है तो यह उनकी स्वभावगत विशेषता है और इसकी नींव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन रख दी गई थी। ग्यारह माह की अपनी राजनीतिक यात्रा में वह इससे इंच भी इधर-उधर नहीं हुए। हां, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत को महत्पूर्ण रणनीतिक साझेदार मानना उनके प्रशासन में कुछ हद तक निश्चिता का संकेत है।

सुरक्षा रणनीति किसी देश या संगठन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा, खतरों का सामना करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक व्यापक योजना होती है। चूंकी सुरक्षा रणनीति में चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। इसलिए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भारत-अमेरिका सहयोग को प्रमुख क्षेत्र बताया गया है। अमेरिका मानता है कि तकनीक के मोर्चे पर भारत के साथ जुड़ाव क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सहयोग न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा बल्कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी मददगार होगा। इसके अलावा साउथ चाइना सी (दक्षिण चीन सागर) में चीन द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के साथ तालमेल को महत्वपूर्ण बताया गया है। नई सुरक्षा रणनीति के दस्तावेज में इस बात का दावा भी किया गया है कि अमेरिका एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य रहेगा। अमेरिका का दायित्व अपने नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। इसमें मजबूत सीमाएं, आव्रजन पर नियंत्रण और देशों के बीच सहयोग से अवैध जनसंख्या प्रवाह रोकने की बात शामिल है। समुद्री मार्गों के स्वतंत्र परिचालन के मामले में भारत और अमेरिका का समान दृष्टिकोण रहा है।

दोनों देश एक मुक्त एवं खुले और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की वकालत करते है। कोई दो राय नहीं कि इंडो-पैसिफिक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी और लगभग आधी जीडीपी का स्रोत होने के कारण वैश्विक रणनीति, आर्थिक शक्ति-संतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अहम घटक बन चुका है। चीन इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। सैन्य शक्ति और आर्थिक बल के जरिए चीन इसकी क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इंडो-पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत को एक जरूरी पक्षकार मानता है। हो सकता है यह चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में भारत के साथ के लिए लालायित दिखने की अमेरिकी इच्छा भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को तो मजबूत बनाती ही है। दूसरी ओर, सिक्योरटी ड्राफ्ट की शब्दावली से साफ है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब ट्रंप प्रशासन भारत को अहम रणनीतिक सहयोगी के तौर पर साथ लेकर चलने के बजाए उसे केवल लेन-देन वाले राष्ट्र के तौर पर देखने लगा है। कहना गलत नहीं होगा कि सिक्योरटी ड्राफ्ट की शब्दावली में अमेरिकी आदर्शवाद को रेखांकित करने के लिए सुंदर शब्दों का तो भरपूर इस्तेमाल किया गया है लेकिन यह यथार्थ के कितने करीब है, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है।

ऐसे में आशंका इस बात की है कि भारत के साथ बात कर ट्रंप प्रशासन कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि भारत का मौजूदा नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक समीकरणों को साधकर भारत-अमेरिकी संबंधों को पुनः बाइडेन युग की ओर लौटा पाने में कितना सफल रहता है।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मुद्दा
सुनील कुमार महला

सतत विकास : समृद्धि और संरक्षण का साझा मार्ग !

अरावली पहाड़ियों की जिस परिभाषा को पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, उसी पर अब रोक लगाकर नई उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश देना स्वागत योग्य कदम है। वास्तव में, यह संकेत देता है कि पहले की रिपोर्ट को लेकर जो आम लोगों द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, वे निराधार नहीं थीं। अरावली को केवल पहाड़ियों की एक भौगोलिक श्रृंखला मानना भूल होगी, क्योंकि यह उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली एक जीवन रेखा है। सरकारी समिति की सिफारिश पर तय की गई परिभाषा से यह आशंका पैदा हुई थी कि अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे खनन और निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता। केवल यह कह देने से कि रिपोर्ट को गलत समझा जा रहा है, आम लोगों की चिंताएं दूर नहीं होतीं। आज जब देश गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब नीति निर्धारण में स्पष्टता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेना यह दर्शाता है कि उसने जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से समझा है। जानकारी के अनुसार अब विशेषज्ञों की समिति अलग-अलग समय की जानकारियों का अध्ययन करेगी। यानी पुरानी तस्वीरें, पुराने नक्शे और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की आपसी तुलना की जाएगी। इससे यह साफ होगा कि पिछले कुछ दशकों में अरावली पहाड़ियों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। उम्मीद है कि इस जांच से यह सच्चाई सामने आएगी कि अवैध खनन, बिना योजना के निर्माण और पेड़ों की कटाई ने इस बहुमूल्य प्राकृतिक धरोहर को कितना नुकसान पहुंचाया है। विवाद केवल 100 मीटर ऊंचाई तय करने को लेकर नहीं है। असल बात यह है कि पर्यावरण में छोटी-सी बात भी बहुत असर डालती है। किसी पहाड़ी को उसके आसपास के जंगल, पानी, मिट्टी और जीव-जंतुओं से अलग करके नहीं समझा जा सकता। अरावली को लेकर आम लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया इसलिए आई, क्योंकि अब वहां पर्यावरण का बिगड़ना साफ दिखाई देने लगा है और उसका नुकसान सीधे लोगों को महसूस हो रहा है। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में देश के पहाड़ी राज्यों में आई विनाशकारी आपदाएं, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे महानगरों में लगातार जहरीली होती हवा कोई अचानक घटित घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह वर्षों से पर्यावरण के प्रति बरती गई लापरवाही और अदूरदर्शी नीतियों का सीधा परिणाम हैं।

वास्तव में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी गंभीर चेतावनियों के बाद भी शासन और समाज के स्तर पर पर्यावरण को लेकर अपेक्षित संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। एक ओर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जनआंदोलन और विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में हजारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें राज्य में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य सरकार वन भूमि की रक्षा करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। कोर्ट के समक्ष आए तथ्यों के अनुसार हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र पर अवैध निर्माण और कब्जे हो चुके हैं, जो पर्यावरण, जैव विविधता और हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा हैं। अदालत ने राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने, नई गतिविधियों पर रोक लगाने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और मामले की आगे भी निगरानी की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर वास्तव में यह साफ व स्पष्ट संकेत दिया है कि इस विषय में गहन तथ्यान्वेषण जरूरी है। वहीं पर सरकार ने भी पूर्व आदेश की कमियों को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार की ओर से यह सहमति जताई गई है कि अब अरावली क्षेत्र में खनन या नियमों में कोई भी बदलाव सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से ही होगा। यहां तक कि यह भी माना गया है कि नवंबर के फैसले को लेकर कई गलतफहमियां थीं। माननीय न्यायालय का उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। यह बात ठीक है कि आज के समय में खनन को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, फिर भी यह सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है कि इससे प्रकृति और मानव जीवन को खतरा न हो। अंततः, अरावली की रक्षा केवल न्यायालय या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित लूट को रोका जा सके।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कुसंगति त्यागे, धर्मबुद्धि जागे

संकलित
दर्शन

आम और नीम दोनों की मूल जमीन में एकत्रित होने से नीम के संसर्ग में आम भी नीमपन को प्राप्त करता है। अर्थात दुर्जन की संगत से प्रायः सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। इस बात पर यदि थोड़ा विचार किया जाए तो प्रश्न यह उठता है कि दुर्जन का प्रभाव ही क्यों पड़ता है? सज्जन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। आम भी कड़वा क्यों होता है? नीम मीठा क्यों होता नहीं ? इसके पीछे यही कारण है कि सज्जन का हृदय बहुत कोमल होता है, जबकि दुर्जन कठोर हृदय का होता है। सज्जन तो खरबूजे की भांति होता है और दुर्जन चाकू की भांति। चाकू चाहे खरबूजे पर पड़े या खरबूजा चाकू के ऊपर, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता है इसलिए सज्जन को सदैव सजग होकर रहना चाहिए। मनुष्य का अहित जितना दुश्मन नहीं करता उतना उसका अविवेक कर बैठता है। महान उपन्यासकार बाबू बंकिमचन्द्र ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य का विशेष अहित उनके स्नेहीजन ही कर सकते है। विवेकहीन माता-पिता धर्म भावना वाली संतान को धर्म से विमुख करके उसे विषय वासना के गर्त में डाल सकते हैं। वर्तमान युग में देखा जा रहा है कि माता पिता अपनी संतान को धनवान बनाने की भावना रखते हैं मगर धर्मवान बनाने की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। वे अपनी संतान को सुसंस्कारित करने की ओर और ध्यान नहीं दे पाते। जिसमें स्वयं संस्कारो का अभाव होता है ,वे भला दूसरों को संस्कारित कैसे कर सकते हैं।

कभी भी अपने धन और पद का घमंड न करें

संकलित
प्रेरणा

देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के पास बहुत धन-संपत्ति थी। कुबेर को अपनी धन-दौलत पर घमंड हो गया। एक दिन कुबेर घमंड के साथ ही शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी से कहा कि मैं आपको अपने महल में खाने के लिए आमंत्रण देने आया हूं। शिव जी ने सोचा कि कुबेर देव का घमंड दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप गणेश को ले जाइए और ध्यान रखना गणेश खाने में जल्दी तृप्त नहीं होते हैं। कुबेर देव को अहंकार तो था ही, उन्होंने कह दिया कि मैं तो सभी को भोजन करा सकता हूं तो गणेश जी को भी तृप्त कर सकता हूं। शिव जी गणेश जी को कुबेर देव के यहां भोजन करने भेज दिया। गणेश जी कुबेर देव के महल पहुंच गए। कुबेर देव ने गणेश जी के लिए बहुत सारा खाना बनवाया और गणेश जी को खाना परोसना शुरू कर दिया। गणेश जी लगातार खाते ही जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। गणेश जी तृप्त नहीं हुए, लेकिन कुबेर देव के यहां का अन्न का भंडार खाली हो गया। गणेश जी को और भूख लग रही थी। कुबेर देव निराश होकर तुरंत ही शिव जी के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। कुछ ही देर में गणेश जी भी शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से गणेश जी के खाने के लिए कुछ लाने को कहा। पार्वती जी तुरंत ही खाना ले आईं। देवी पार्वती के हाथ का बना खाना खाकर गणेश जी शांत हो गए। ये देखकर कुबेर देव को अपनी गलती समझ आ गई। कुबेर ने शिव जी से क्षमा मांगी और घमंड न करने का संकल्प लिया।

वैकुंठ एकादशी

हैदराबाद में मंगलवार को चारमीनार के पास वैकुंठ एकादशी त्योहार के दौरान भक्त एक धार्मिक जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं।

आज की पाती

अदालत का सही फैसला

भारत में आस्था अक्सर तर्क से बड़ी हो जाती है। यही कारण है कि यहां मंदिर के बाहर घंटियों की आवाज से ज्यादा तेज कभी-कभी सांसों की घुटन होती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। मुंबई की एक अदालत का हालिया फैसला, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर कबूतरों को दाना डालने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, इसी टकराव की एक स्पष्ट और साहसी मिसाल है। यह फैसला कबूतरों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो भावुकता के नाम पर विज्ञान, कानून और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कुचल देती है। हमारे समाज में कबूतरों को दाना डालना पुण्य माना जाता है। लेकिन कबूतर बीमारियां भी फैलाते हैं, इस दृष्टि से यह फैसला सही लगता है। - *विवेक शर्मा, दुर्ग*

ट्रेंड

सुधारों की रफ्तार

भारत ने सुधारों की रफ्तार पकड़ ली है! 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति प्रदान की है। ये सुधार एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को भी बल देंगे।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मूल भावना के विपरीत

यह आश्चर्य है कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और उसके एजेंडे में संसद द्वारा पारित 'विकसित भारत-जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात शामिल है। संसद में बने कानून के खिलाफ विस में प्रस्ताव पारित करना संसदीय मूल भावना के विपरीत है।

-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

गरीब परिवारों को फ्लैट

हमारी सरकार 2026 में 6000 से ज्यादा गरीब परिवारों को दिल्ली में अपना फ्लैट देने जा रही है। पहले चरण में सावदा घेवरा में बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं के साथ 2,500 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी जाएगी।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

हार्दिक संवेदनाएं

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश की जनता के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ।

- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

चीन की सेना का ताइवान के पास सैन्य अभ्यास जारी

चीन की सेना ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान द्वीप के आसपास संयुक्त अभ्यास किया। बीजिंग ने इसे अलगाववादी और 'बाहरी हस्तक्षेप' वाली ताकतों के खिलाफ 'कड़ी चेतावनी' बताया वहीं ताइवान ने कहा कि उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। ताइवान ने चीन की सरकार को 'शांति का सबसे बड़ा दुश्मन' करार दिया। दो दिनों तक जारी रहने वाले इन सैन्य अभ्यासों को 'जस्टिस मिशन 2025' नाम दिया गया है। चीन के ये अभ्यास ताइवान को संभावित रूप से अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी हथियार बिक्री पर आक्रोश व्यक्त करने और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस बयान के बाद किए जा रहे हैं कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनकी सेना हस्तक्षेप कर सकती है। चीन का कहना है कि ताइवान को उसके शासन के अधीन आना होगा। चीन की सेना ने सोमवार को अपने बयान में अमेरिका और जापान का नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी पर अमेरिका से समर्थन मांगकर स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह, आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से कहा कि इस दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का 'निष्फल होना तय है'।

ऑफ बीट

रात में अच्छी नींद कैसी होनी चाहिए?

बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे तकिये पर सिर रखेंगे तो उन्हें गहरी और आरामदेह नींद आनी चाहिए और लगभग आठ घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए उठना चाहिए। वास्तव में, पूरी रात स्वस्थ नींद चक्रीय होती है क्योंकि आप नींद के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और अक्सर कई बार जागते हैं। कुछ लोगों को इनमें से एक या अधिक बार जागना याद रहता है लेकिन कई लोगों को यह भी याद नहीं रहता कि वे रात में कितनी बार नींद से जागे। एक वयस्क के रूप में, हमारी नींद अलग-अलग चक्रों से गुजरती है और रात के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर के लिए नींद टूटती है। प्रत्येक नींद का चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। गहरी नींद में जाने से पहले और सपनों की दुनिया (रैपिड आई मूवमेंट-आरईएम) में खोने से पहले हम रात में हल्की नींद से शुरुआत करते हैं। यदि हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हम अपनी अधिकांश गहरी नींद रात के पहले भाग में पूरी कर लेते है और रात के दूसरे भाग में हमें सपने आने लगते हैं। वयस्क आमतौर पर रात में पांच या छह नींद के चक्रों से गुजरते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए जागना पूरी तरह सामान्य है। इसका मतलब है कि हम रात में पांच बार जाग सकते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री नड्डा की मौजूदगी में हुई हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा बैठक

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से उनके नई दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा में संचालित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में टीबी मुक्त भारत/टीबी मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रदर्शन को सराहा गया। केंद्रीय मंत्री ने निक्षय पोषण योजना को और मजबूत करने, निक्षय मित्रों की भागीदारी बढ़ाने तथा एक्स-रे जांच कवरेज का विस्तार करने की सलाह दी। फरवरी माह में 100-दिवसीय टीबी अभियान को पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें सांसदों, विधायकों, जिला समितियों और उपायुक्तों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दवाइयों और जांच सेवाओं में बेहतर उपलब्धता हरियाणा की आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) में राष्ट्रीय सूची की तुलना में अधिक दवाइयाँ शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता 90 प्रतिशत से अधिक तथा कुल अणु (मॉलिक्यूल) उपलब्धता 80 प्रतिशत से ऊपर पाई गई, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सराहनीय बताया। जांच सेवाओं की बात करें तो उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 13 प्रकार की जांच, जबकि जिला अस्पतालों में सूचीबद्ध 134 में से 108 जांचें उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भी बड़ी संख्या में जांच सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से और मजबूत करने का सुझाव दिया गया।

चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता पर दिया जोर

बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने और उनकी तैनाती को सुव्यवस्थित करने पर बल दिया गया। वर्तमान में हरियाणा अपने स्वास्थ्य बजट का लगभग 70 प्रतिशत वेतन पर खर्च करता है। इसे अन्य राज्यों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से 50 प्रतिशत तक लाने के लिए युक्तिसंगत भर्ती और योजना बनाने की सलाह दी गई। ड्रग सप्लाई पोर्टल और एफडीए सुधार राज्य को सलाह दी गई कि दवा उपलब्धता पोर्टल को उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मिल सके। लंबित मैपिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तहत प्रमुख पदों पर प्रतिनियुक्ति आधारित नियुक्तियां की गई हैं तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा और पीपीपी पर फोकस भिवानी में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के संचालन शुरू होने की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में यूजी और पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीपीपी सेल के साथ समन्वय कर डायग्नोस्टिक एवं अन्य सेवाओं में साझेदारी के अवसर तलाशने को कहा गया।

खबर संक्षेप

लुलु मॉल पर कार्रवाई टैक्स न देने पर खाता फ्रीज

लखनऊ। आयकर विभाग ने लुलु मॉल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है। 27 करोड़ के आयकर का भुगतान न किए जाने पर यह कदम उठाया गया। देनदारी और लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेजों की समीक्षा की गई, जिसमें कर चोरी के संकेत मिले। विभाग का कहना है कि बकाया कर राशि को लेकर कंपनी को पहले नोटिस जारी किए गए थे।

आप का जनरल सेक्रेटरी जोशी गिरफ्तार

सूरत। सूरत में आप के नेता श्रवण जोशी को गिरफ्तार किया गया है। सूरत एसओजी की टीम जोशी को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सूरत शहर के लिंबायत इलाके में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सस्ती अनाज की दुकान के मालिक ने आप से जुड़े महामंत्री और कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शाह का 'मिशन बंगाल' : बंगाल में आगामी चुनाव की गरमाहट बढ़ी, सियासत पर बोले गृहमंत्री शाह

गृह मंत्री शाह ने कोलकाता में की प्रेस वार्ता

चुनावी लाभ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही ममता सरकार, इसी मुद्दे पर होगा आगामी चुनाव

एजेंसी ▶▶ कोलकाता

- राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी
- राज्य की ममता सरकार को लिया आड़े हाथ
- टीएमसी के शासन में यहां भय और भ्रष्टाचार बढ़ा

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्यभर में सियासी गरमाहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। इसी के कारण आरोप-प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस वार्ता की।

उन्होंने राज्य की टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, प्रशासन समेत कई मुद्दों को लेकर शाह ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। शाह ने कहा कि ममता चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। बंगाल सरकार द्वारा हमें जमीन न दिए जाने के कारण हम बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी पूरी नहीं कर पाए हैं। 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को बाहर निकालने इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएंगे।

बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही राज्य सरकार

अमित शाह ने बंगाल सरकार पर बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, जिसकी वजह से घुसपैठ की समस्या बनी हुई है। त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों रुक गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बंगाल में राज्य सरकार की जानकारी में घुसपैठ हो रही है और इसका मकसद जनसंख्या में बदलाव कर वोट बैंक मजबूत करना है। शाह ने साफ कहा कि बंगाल सीमा से हो रही घुसपैठ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

बंगाल की पहचान डर और भ्रष्टाचार से हो रही

शाह ने कहा कि बंगाल के लिए आज से अप्रैल तक का समय बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में टीएमसी सरकार के शासन में राज्य में भय, भ्रष्टाचार और गलत प्रशासन फैला है, जिसके कारण बंगाल में आम नागरिकों में चिंता का माहौल बन गया है। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुक गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याण योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट की भेंट चढ़ गई हैं। बंगाल की पहचान डर और भ्रष्टाचार बन गई है।

मैंने सीएम ममता को 7 बार किया आगाह, पत्र भी लिखा

शाह ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए उन्होंने खुद ममता को सात पत्र लिखे हैं, लेकिन राज्य सरकार अब तक जमीन नहीं दे रही है। अमित शाह ने बताया कि पिछले छह साल में गृह सचिव तीन बार बंगाल गए और राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठकें भी हुईं, इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि टीएमसी सरकार को जमीन देने में किस बात का डर है और क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार घुसपैठियों के दस्तावेज बना रही है, जिससे घुसपैठ लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार घुसपैठ रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है और इससे बंगाल की जनसंख्या संरचना तेजी से बदल रही है, जो बेहद चिंताजनक है।

अगले साल बंगाल में भाजपा बनाएगी सरकार, आंकड़े भी किए पेश

शाह ने जोर दिया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजापा बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। शाह ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17% वोट और तीन सीटें मिलीं। 2019 लोकसभा चुनाव में वोट बढ़कर 41% और सीटें 18 हो गईं। 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 21% वोट और 77 सीटें मिलीं और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 39% वोट और 12 सीटें मिलीं। जो पार्टी 2016 में सिर्फ 3 सीटों पर थी, वह 5साल में 77 सीटों तक पहुंच गई। कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई और वाम दलों को एक भी सीट नहीं मिली।

ममता का शाह पर बड़ा हमला

शकुनि का चेला दुःशासन...

केंद्रीय गृह मंत्री शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी चीफ ममता बेनर्जी करारा हमला बोला है। ममता ने कहा कि शकुनि का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है, तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था?

इस बार खेला का नाम फाटाफटी होगा

ममता ने कहा कि हम बंगाल जीतेंगे और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से देश से बाहर निकाल देंगे। चुनाव आयोग भाजपा का बड़ा दलाल है। भाजपा हमेशा नहीं रहेगी। एसआईआर की वजह से 57 लोगों की मौत हुई है, उनके नाम पर स्मृति बेदी बनाई जाएगी। मुझे गोली मार के हत्या कर दो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वह भी नहीं कर पाओगे। इस बार के खेला का नाम फाटाफटी होगा।

अधीर रंजन ने पीएम से की कई मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस समय में यह बैठक खास अहमियत रखती है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने हैं। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें बंगाल में एसआईआर को लेकर चिंताएं शामिल थीं। इसके अलावा कई राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा की अलग-अलग घटनाओं पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद ने देश के अलग-अलग हिस्सों, खासकर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। चौधरी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि वे इस मामले में तुरंत दखल दें, क्योंकि ऐसे हमलों से पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैल सकती है।

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के दखल से उत्साहित जयराम की तीन अन्य मामलों में भी संज्ञान लेने की गुजारिश

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पर्यावरण से जुड़े अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही पूर्व फैसले को स्वतः संज्ञान लेते हुए वापस लेने को अत्यंत आवश्यक और स्वागतयोग्य कदम बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा में बदलाव से जुड़ा फैसला दिया था, जिसे मोदी सरकार ने पूरे उत्साह के साथ अपनाया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को स्वयं संज्ञान लेते हुए वापस ले लिया है। उनके अनुसार, यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

पहला मुद्दा सरिस्का टाइगर रिज़र्व से जुड़ा

उन्होंने बताया कि 6 अगस्तको सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। इस प्रस्ताव के जरिए लगभग 57 बंद खदानों को दोबारा खोलने का रास्ता तैयार किया जा रहा था। रमेश ने कहा कि इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए।

पूर्व प्रभाव से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरी

उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 16 मई के उस फैसले की समीक्षा का दरवाजा खोल दिया, जिसमें पूर्व प्रभाव से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरियों पर रोक लगाई गई थी। ऐसी मंजूरियां न्यायशास्त्र की मूल भावना के खिलाफ हैं और शासन व्यवस्था का मजाक बनाती हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले की समीक्षा अनावश्यक थी और किसी भी परिस्थिति में पूर्व प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। अक्सर कानूनों और नियमों को जानबूझकर इस भरोसे के साथ नजरअंदाज किया जाता है कि परियोजना शुरू हो जाने के बाद निर्णय प्रक्रिया को 'मैनेज' कर लिया जाएगा, जो बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है॥

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित: जयराम ने याद दिलाया कि एनजीटी की स्थापना अक्टूबर 2010 में कानून, सुप्रीम कोर्ट के समर्थन के साथ की गई थी। लेकिन पिछले एक दशक में इसकी शक्तियों को लगातार कमजोर किया गया है। अब समय आ गया है जब कोर्ट को हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनजीटी बिना किसी भय या पक्षपात के, कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

अठावले ने भाजपा पर लगाया विश्वासघात का आरोप, बीएमसी में अकेले लड़ेगी आरपीआई

रिपब्लिकन पार्टी मुंबई में एक बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन भाजपा ने हमें नजरअंदाज कर दिया

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के प्रमुख रामदास अठावले ने मंगलवार को भाजपा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में अपने दम पर ताल ठोंकने का ऐलान किया है। आरपीआई को सीट बंटवारे की चर्चाओं में शामिल तक नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को बहुत देर से सूचित किया गया कि उसे केवल छह सीटें आवंटित की गई हैं।

अठावले ने कहा कि आरपीआई ने भाजपा को 26 सीटों की सूची सौंपी थी और उसे 14-15 सीटों के आवंटन की उम्मीद थी। उन्होंने इसे धोखा करार दिया और घोषणा की कि आरपीआई मुंबई में 38 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेगी। अठावले के गठबंधन से किनारा करने से भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने भाजपा पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। अठावले ने कहा कि लगातार नजरअंदाज किए जाने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन ने आरपीआई को टिकट देने में समस्या पैदा कर दी है। रिपब्लिकन मुंबई में एक बहुत मजबूत पार्टी है लेकिन भाजपा ने हमें नजरअंदाज कर दिया है, चर्चाओं के दौरान हमें एक बार भी नहीं बुलाया गया। अगर आरपीआई को भाजपा-शिवसेना की चर्चाओं में बुलाया गया होता, तो हमें कुछ सीटें आवंटित की जा सकती थीं, सोमवार रात 2 बजे हमें बताया गया कि हमें छह सीटें दी गई हैं। अठावले ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे संपर्क कर आरपीआई को 6सीटें आवंटित किए जाने की जानकारी दी थी। हालांकि, अठावले ने कहा कि ये सीटें उनकी पार्टी द्वारा अनुरोधित सीटों में शामिल नहीं थीं और आरपीआई के इन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई उम्मीदवार नहीं थे। अठावले ने कहा, नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद जैसे कई शहरों में हमें सीटें नहीं दी गईं। नालासोपारा में हमें एक भी सीट नहीं मिली। भिवंडी में एक सीट मिली। कल्याण-डोम्बिवली में एक भी सीट नहीं दी गई। भाजपा ने कई जगहों पर आरपीआई को नजरअंदाज किया।

बिना स्पष्ट लिखित दिशा निर्देश और प्रशिक्षण जल्दी में लागू किया

एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, पारदर्शिता की मांग

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना स्पष्ट लिखित दिशानिर्देश, पर्याप्त प्रशिक्षण और ठोस कारण बताए एसआईआर को जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है, जिससे आम मतदाताओं, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को नुकसान हो रहा है।

इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग पर इतनी जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करने के लिए आखिर किसका दबाव है। उन्होंने कहा कि आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया, डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नए ऐप और इसके लागू होने व रोके जाने की समय-सीमा को लेकर एक स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। सेंथिल ने कहा कि एसआईआर के तहत घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है और मतदाता सूची को लगभग नए सिरे से तैयार करना होता है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।

रोजगार के कारण लोगों के स्थान परिवर्तन की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को धरातल पर जाकर सूझबूझ से निर्णय लेना होता है। यह लंबी और जटिल प्रक्रिया पहले दो साल में पूरी होती थी, लेकिन अब इसे मात्र एक महीने में पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण कई बीएलओ पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

सेंथिल ने कहा कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिनके अलग-अलग नियम हैं। एक वोटर का फॉर्म आने के बाद बीएलओ द्वारा जानकारी अपडेट की जाती है और दोबारा जांच के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग रोज नए निर्देश ऐप के जरिये जारी कर रहा है, जिससे बीएलओ असमंजस में हैं। केवल एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर निर्णय लेने से गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। पारिवारिक रिकॉर्ड और 2002 की मतदाता सूची से मिलान जैसे नियमों का सबसे अधिक असर गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज या डिजिटल मैपिंग नहीं है।

सेंथिल ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया ने देशभर में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और इनमें 10 से 15 प्रतिशत तक वास्तविक मतदाताओं के नाम कटने की आशंका है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कुछ वर्गों के मतदाताओं के नाम चुनिंदा रूप से हटाए जाने का भी उल्लेख किया।

सेंथिल ने बिहार में एसआईआर के दौरान हुई गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिये डुप्लीकेट नामों की पहचान की जाती थी, लेकिन बिहार में इसे खामी का हवाला देकर बंद कर दिया गया, जबकि अब 12 राज्यों में इसे फिर लागू किया गया है। उन्होंने इसे चुनाव आयोग का स्पष्ट यू-टर्न बताते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची में अब भी करीब 14.5 लाख डुप्लीकेट नाम मौजूद हैं।

सेंथिल ने मांग की कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट करे कि डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कब शुरू किया गया और कब बंद किया गया तथा मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करने के लिए किस नए ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

सीबीआई अदालत ने 5.75 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में निजी कंपनी और उसके निदेशकों को दोषी ठहराया

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

सीबीआई की विशेष अदालत ने 5.75 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक निजी कंपनी और उसके चार निदेशकों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने कंपनी के सभी निदेशकों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है। सीबीआई के अधिकारिक प्रवक्ता खबर की पुष्टि करते हुए बताया, एस डी.एन. इंटरनेशनल लिमिटेड तथा उसके निदेशकों केतन ए. शाह, मुकेश ए. शाह, अश्विन एच. शाह और रश्मिकांत शाह को सीबीआई अदालत ने दोषी पाया। सभी निदेशकों को पांच वर्ष का कठोर कारावास और चार-चार लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, आरोपी कंपनी पर भी चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वर्ष 1999-2000 का है मामला

सीबीआई के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999-2000 का है। उस दौरान आंध्र बैंक की चेन्नई स्थित माउंटेव्स रोड शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों ने आरोपी कंपनी के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए बैंक के नियमों की अनदेखी की। कंपनी को ऋण सुविधाएं अनुचित तरीके से मंजूर की गईं।

ऋण राशि का दुरुपयोग

जांच में सामने आया कि हीरा निर्माण, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी यह कंपनी स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग तय उद्देश्यों के लिए नहीं कर रही थी। आरोपियों ने बैंक से प्राप्त धनराशि को अन्यत्र डायवर्ट कर दिया, जिससे आंध्र बैंक को 5.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

2002 में मामला दर्ज

सीबीआई ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर 19 फरवरी 2002 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। विस्तृत जांच के बाद 7 मई 2004 को सीबीआई ने चेन्नई स्थित विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

अदालत का फैसला

अदालत ने सुनवाई के बाद पांच आरोपियों को दोषी ठहराया। वहीं, तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि तीन आरोपियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

सीबीआई की सख्ती का संदेश

यह फैसला बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में सीबीआई की सख्त कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय बैंक धोखाधड़ी में शामिल लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है।

संपादकीय जागरण

बुधवार, 31 दिसंबर, 2025 : पौष शुक्ल - 12 वि. 2082

आत्ममंथन भविष्य में सुधार का आधार प्रदान करता है

सुधारों की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में रेखांकित करते हुए यह जो कहा कि भारत रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और इससे 2047 तक देश को विकसित बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी, उसकी सार्थकता तभी है, जब वास्तव में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। इससे इन्कार नहीं कि इस वर्ष कई बड़े सुधार हुए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रहा जीएसटी में व्यापक बदलाव। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी देने और श्रम सुधारों के तहत 29 कानूनों को चार आधुनिक कोड में समेटकर लागू करने को भी बड़े कदम की संज्ञा भी दी जा सकती है, लेकिन अभी तो इन सुधारों का प्रभाव सामने आना शेष है। ठीक वैसे ही, जैसे इसका पता भविष्य में ही चलेगा कि मनरेगा में बुनियादी बदलाव कर वीबी-जीरामजी नामक जो नया कानून लाया गया, उसके कितने सकारात्मक नतीजे कब तक आएंगे। यही बात शिक्षा, कारोबारी सुगमता और परमाणु ऊर्जा से जुड़े कुछ उन सुधारों पर भी लागू होती है, जो इस वर्ष देखने को मिले। सुधार के इन कदमों को जिन उद्देश्यों के साथ लागू किया गया है, उनकी पूर्ति हर हाल में हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुधारों के सकारात्मक परिणाम केवल दिखने ही नहीं चाहिए, बल्कि वे आम आदमी को महसूस भी होने चाहिए।

विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि नौकरशाही के प्रत्येक स्तर पर सुधार हो। यह ठीक है कि केंद्रीय सत्ता से जुड़ी उच्च स्तर की नौकरशाही के तौर-तरीकों में कुछ बदलाव आया है, लेकिन निचले स्तर पर उसका रवैया जस का जस है। सबसे खराब बात यह है कि नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कारण भी आम आदमी सुधारों के समुचित लाभ का अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसे अब भी कदम-कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समझा जाए तो अच्छा कि हर क्षेत्र में सुधारों को सही तरह लागू करने के मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसका संकेत कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने यह कह कर दिया था कि राज्यों को मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ कारोबारी सुगमता में सुधार और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने शासन, सेवा और विनिर्माण, हर क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता बनाने पर भी जोर दिया था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का पर्याय नहीं बनाया जा सका है। इसी तरह शासन व्यवस्था में एक नई कार्यसंस्कृति विकसित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने के बाद भी अभी बात नहीं बन सकी है।

सख्ती जरूरी

दिल्ली में नववर्ष की पूर्व संध्या पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाना बेहद आवश्यक है। राजधानी में कनाट प्लेस, खान मार्केट व इस जैसे कई अन्य इलाके हैं, जहां नए साल का जश्न मनाने वालों की भीड़ उमड़ती है। दिल्ली की यातायात पुलिस ने ऐसे कुछ इलाकों में यातायात प्रतिबंधित करने को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पूरी सख्ती बरतने की भी तैयारी है। यह उचित है कि यातायात पुलिस ने किसी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था कर दी है। वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती का भी पूरा इंतजाम है, लेकिन यह दिल्लीवासियों का भी दायित्व है कि वे सभ्य नागरिक की तरह नए साल का जश्न मनाएं और यातायात पुलिस के नियम तोड़ने व शराब पीकर वाहन चलाने से बचें।

यह लोगों का भी दायित्व है कि सभ्य नागरिक की तरह नए साल का जश्न मनाएं और नियम तोड़ने व शराब पीकर वाहन चलाने से बचें

दिल्ली पुलिस को शेष इलाकों में भी पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं, जब 31 दिसंबर की रात दुष्कर्म व हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं। इन्हें देखते हुए ये आवश्यक है कि दिल्ली पुलिस न सिर्फ उन इलाकों, जहां नए साल का जश्न मनाया जाएगा, बल्कि सभी इलाकों में सतर्कता उच्च स्तर पर रखे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हुड़दंग मचाने वाले एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

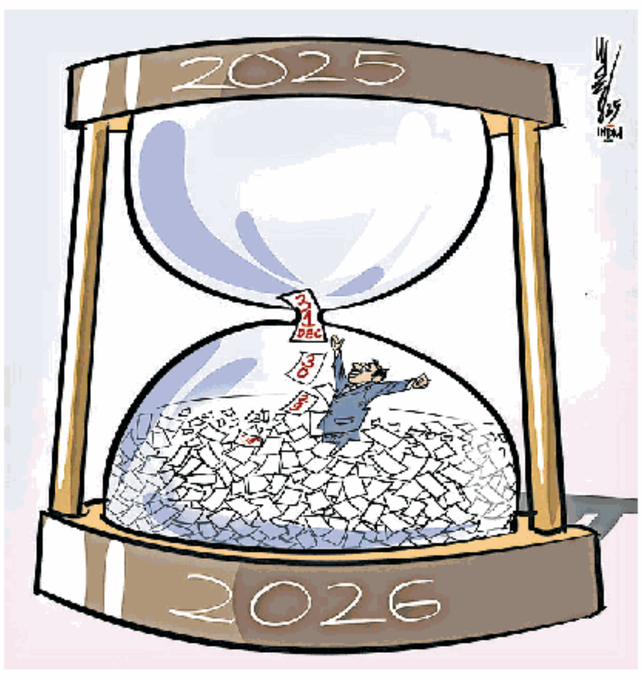

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होगा?

आज का सवाल

क्या ओपेनएआइ के मुखिया सैम आल्टमैन का यह कहना सही है कि एआइ तकनीक एक खतरा भी बन सकती है?

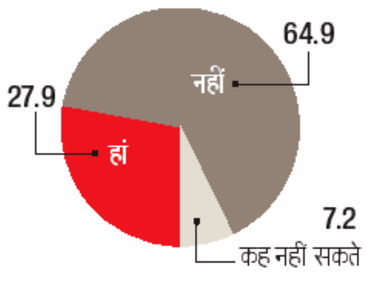

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कई सवालों के जवाब देगा नया साल

राहुल वर्मा

भाजपा, कांग्रेस और वामदलों से लेकर कई क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए 2026 में राजनीतिक मोर्चे पर काफी कुछ दांव पर लगा है

देश के राजनीतिक परिदृश्य को निर्धारित करने के दृष्टिकोण से अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगले वर्ष बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें सभी दलों का कुछ न कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे धनाढ्य नगर निकाय बृहनमुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव भी होने हैं। कुछ राज्यसभा की रिक्त हो रही सीटों पर चुनाव की स्थिति में भी दलों के बीच खींचतान होती हुई दिख सकती है। अगला साल कई राजनीतिक पहेलियां भी सुलझाएगा। जैसे कि क्या देश भर में बड़े पैमाने पर विस्तार कर चुकी भाजपा अपने लिए राजनीतिक रूप से अनुर्वर साबित हो रहे प्रदेशों में भी अनुकूल स्थितियां बनाकर पैठ बढ़ा पाएगी या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद पटरी पर आई कांग्रेस की जो गाड़ी फिर से बेपटरी हुई, क्या वह वापस पटरी पर आ पाएगी या नहीं? क्या अस्तित्व के संकट से जूझ रहे वामदल अपनी सत्ता के आखिरी दुर्ग को बचा पाएंगे या नहीं? क्षेत्रीय दल किस नियति को प्राप्त होंगे?

भाजपा की चर्चा की जाए तो विधानसभा चुनाव इसकी पुष्टि करेंगे कि नए क्षेत्रों में पैठ बनाने के उसके प्रयासों को कितनी सफलता मिलेगी? जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहां केवल असम में ही उसकी सरकार है और पुडुचेरी में उसके समर्थन वाली सरकार सत्तारूढ़ है। दस साल से असम की सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए फिर से सत्ता में वापसी की ठीकठाक संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन यह तय है कि उसे इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। अगर कांग्रेस ने राजनीतिक कौशल दिखाया तो भाजपा के समीकरण गड़बड़ा भी सकते हैं। बंगाल में तमाम प्रयासों के बावजूद पार्टी दूसरे क्रम पर ही अटकी हुई है। ममता बनर्जी ने राज्य की सत्ता पर जिस मजबूती के साथ पकड़ बनाई हुई है, उससे भाजपा के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। हालांकि बिहार की जीत से उत्साहित भाजपा नई ऊर्जा के साथ बंगाल के रण में उतरने की तैयारी कर रही है। एक रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उसने जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है।

दक्षिण में केरल और तमिलनाडु भाजपा के लिए दूर की कौड़ी बने हुए हैं। लोकसभा की 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भरसक कोशिशों के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में वह यहां गठबंधन सहयोगियों के ही भरोसे है। केरल की दो ध्रुवीय राजनीति में भाजपा फिलहाल

अवधेश राजपूत

तीसरा ध्रुव बनने पर ही ध्यान टिकाए हुए है। तिरुअनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत से उसे थोड़ी ही सही, लेकिन ताकत और हौसला जरूर मिला है। ऐसे में देखना यही होगा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी कितनी मजबूती से अपनी चुनौती पेश करती है?

कांग्रेस के लिए अगला साल कम चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला। असम में वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस बंगाल में तो लगभग हाशिए पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में वह द्रमुक की पिछलग्गू बनकर रह गई है। पार्टी की वास्तविक उम्मीदें केरल से जुड़ी हुई हैं, जहां वह वाम दलों के मोर्चे से सत्ता झटकने की व्यूह रचना बनाने में जुटी है। उसके लिए अनुकूल संकेत हैं कि हाल के निकाय चुनाव में पार्टी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि अतीत के कई चुनावों में जीती हुई बाजी हारने के लिए जानी-जाने वाली कांग्रेस के लिए केरल में भी समस्याएं कम नहीं हैं। पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचतान की स्थिति है। स्थानीय इकाई में गुटबाजी के अलावा प्रदेश नेतृत्व को ताकतवर महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर भी आशंकाएं कम नहीं हैं कि सत्ता मिलने पर वह मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। एक समय राज्य में पार्टी नेतृत्व को लेकर स्पष्टता का रुख रहा है, लेकिन एके एंटनी के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद से प्रदेश में नेतृत्व को लेकर स्वीकार्यता की स्थिति बनाने में संघर्ष ही करती रही है। इसे यदि समय से नहीं सुलझाया गया तो केरल की सत्ता का सिंहासन उससे दूर ही रह जाएगा।

वामदलों के लिए भी अगला साल अस्तित्व के सवाल से जुड़ा है। लंबे समय से बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता पर काबिज रहे वामदल अब इन दोनों राज्यों में राजनीतिक वनवास भोग रहे हैं। अगर केरल की सत्ता से भी उनकी विदाई होती है तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक ऐसे समय में जब यह विचारधारा भारत में अपने आगमन के सौ वर्षों का सफर पूरा कर चुकी है तो सत्ताशून्यता की ऐसी संभावित स्थिति उसकी वैचारिक प्रासंगिकता पर प्रश्न ही उठाएगी। कुछ अन्य क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए भी अगला साल बहुत कुछ निर्धारित करेगा। बंगाल में तृणमूल जिस जज्बे के साथ जुटी हुई है, उससे लगता नहीं कि वह प्रतिद्वंद्वी भाजपा को आसानी से राजनीतिक बढ़त बनाने की गुंजाइश देगी। हालांकि भाजपा जिस रणनीति और संसाधनों के साथ चुनाव लड़ती है उसे देखते हुए ममता बनर्जी के लिए भी राह आसान नहीं होगी। तमिलनाडु में द्रमुक का गढ़ कुछ अभेद्य लगता है, क्योंकि जयललिता के निधन के बाद राज्य में जो राजनीतिक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हुई, उसकी अभी तक भरपाई नहीं हो सकी। अन्नाद्रमुक में आंतरिक खींचतान ने भी मुख्यमंत्री स्टालिन का काम आसान ही किया है। हालांकि इतने वर्षों के सत्ता विरोधी रुझान और भाजपा के समन्वित प्रयासों से विपक्षी गठबंधन में नई ऊर्जा स्टालिन के लिए चुनौती बढ़ाने का काम जरूर करेगी। अभिनेता से नेता के रूप में स्थापित होने के प्रयासों में जुटे विजय की पार्टी भी कुछ सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। एक लंबे समय के बाद साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ मिलकर भी सफलता हासिल नहीं कर पाए तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य अधर में अटक जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी चुनाव से पहले मेल-मिलाप जारी है, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? अगला साल ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर आएगा।

(लेखक चेन्नई स्थित शिव नादर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली में फेलो हैं)
response@jagran.com

लापरवाही बढ़ा रही सड़क हादसों को

यशपाल सिंह

सड़क सुरक्षा भविष्य में बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या होने वाली है। इसका समय से सही समाधान अनिवार्य है

देश में हर दिन कोई न कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती है। कभी-कभी तो एक ही दिन कई जानलेवा हादसे होते हैं, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं। इधर घने कोहरे के कारण मार्ग दुर्घटनाओं का जोखिम और बढ़ गया है। पिछले दिनों घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कई मार्ग दुर्घटनाएं हुईं। इनमे सबसे भंयकर रही आगरा से नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर। यहां एक कार और बस की टक्कर होने के बाद एक के बाद एक कुल 11 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिनमें छह स्लीपर कोच और दो रोडवेज बसें भी थीं। टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिसमें दर्जन भर लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनकी पहचान मुश्किल हो गई। एंबुलेंस, पुलिस, फायर सर्विस अथवा परिवहन से संबंधित कोई इकाई उनकी मदद नहीं कर सकी। डीएनए टेस्ट द्वारा उनके संबंधियों से मिलान कर शवों की पहचान की गई। उन परिवारों की पीड़ा का बयान शब्दों में संभव नहीं। ऐसी हर दुर्घटना के पीछे लापरवाही होती है।

जब रात्रि के घने कोहरे में पैदल यात्रियों को भी चलना दूभर हो जाता है, तब पूरी रफ्तार से बिना आवश्यक सावधानी के स्लीपर या रोडवेज बसों का चलना गंभीर अपराध कहा जाएगा। यदि चालक अत्यधिक ड्यूटी के कारण नींद की झपकी ले रहे थे या वाहनों में आवश्यक फाग लाइटें नहीं थीं, अथवा कोई अन्य तकनीकी कमी थी तो यह बस मालिकों की भी गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। पूरा देश जानता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रतिवर्ष पूरे उत्तर भारत में कोहरा पड़ता है, जो अचानक किसी दिन घने, किसी दिन बहुत घने और कभी बहुत हल्का होता है। आगरा-नोएडा एक्सप्रेसवे पर जिस दिन दुर्घटना हुई, उसके दो दिन पूर्व घने कोहरे के कारण लखनऊ इकाना स्टेडियम में होने वाला क्रिकेट मैच खिलाड़ियों के मैदान में उतर जाने के बाद भी स्थगित करना पड़ा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी कोहरे को लेकर थी, परंतु इन गाड़ियों की रफ्तार नियंत्रण और चेकिंग इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कम से कम कुछ चेकपोस्टों पर लाउडस्पीकरों से घोषणा कर वाहन चालकों को आगाह किया जा सकता था,

चिंतित करती सड़क हादसों की संख्या ● फाइल

लेकिन किसी को चिंता नहीं थी। प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका मूल कारण किसी उच्चतम अधिकारी की स्पष्ट जिम्मेदारी का न होना है। इसका कारण यह है कि किसी की जवाबदेही नहीं होती और न ही कोई चिंता करता है। परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस पर और ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग पर दोष डालकर शांत हो जाते हैं और कुछ दिन बाद घटना भुला दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी अब चौराहों तक सीमित है, ताकि यातायात अबाध रूप से चलता रहे।

आगरा-एक्सप्रेसवे पर भयंकर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रुख अपनाते ही दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया। आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 50 पायलट गाड़ियां तैनात कर दी गईं और 75 संवेदनशील स्थान भी चुन लिए गए, जहां से गाड़ियां काफिले में नियंत्रित गति से चलाना प्रारंभ की गईं। चिह्नित स्थानों पर ब्लिंकर्स लगाए गए। जगह-जगह लाउडस्पीकर लगाकर सतर्क करने की व्यवस्था की गई। इन चारों एक्सप्रेसवे पर हर 50 किमी की दूरी पर विशेष वाहनों की तैनाती की गई, जिसमें गश्ती वाहन, एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन लगाए गए। गाड़ियों को प्रवेश बिंदुओं पर रोककर रिफ्लेक्टर और फाग लाइटें लगाई गईं। अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई। वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर उसे लागू किया गया और न मानने वालों के चालान काटे गए। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यह सब पहले नहीं किया जा सका। पुलिस और प्रशासन दुर्घटना होने के बाद चेतता है। इसका एक कारण यह है कि देश भर में आम तौर पर यातायात पुलिस को शहर के चौराहों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में पुलिस से अधिक प्रभावशाली योगदान किसी और विभाग का हो ही नहीं सकता।

सभी प्रदेशों में थानों-चौकियों के जरिये हर कहीं यातायात पुलिस की पहुंच है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी को उपलब्ध रहती है और किसी भी घटना स्थल पर सबसे पहले वही पहुंचती है। पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 दुर्घटनाएं होती हैं। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उनके प्रति अफसोस प्रकट कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। कभी-कभी लगता है कि वाहन चालकों को कानून का कोई भय ही नहीं है। इस व्यवस्था में सुधार तब तक संभव नहीं है, जब तक कि एक विभाग विशेष की जवाबदेही तय नहीं कर दी जाती। जिम्मेदारी जवाबदेही से आती है। यही विभाग अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर पूरे वर्ष बदलते मौसम, त्योहारों, विशेष यात्राओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हो।

अपने देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो देश के विकास के साथ-साथ भविष्य में दोगुनी गति से बढ़ेगी। लिहाजा यातायात पर विशेष ध्यान देते हुए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए और शानदार हाईवे भी बनाए जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा भविष्य में बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या होने वाली है। इसका समय से सही समाधान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

कृतज्ञता का संस्कार

प्रकृति ने मनुष्य को जितना आवश्यक था, वह सब उदारता से प्रदान किया है। पर्याप्त भोजन और सिर छुपाने के लिए आश्रय। यह सब बिना किसी शर्त, बिना हिसाब-किताब मिला। विडंबना यही है कि मनुष्य की आवश्यकता पूरी होने पर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। उसने प्रकृति से आवश्यकता से अधिक लिया, फिर भी उसके मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित नहीं हुआ। उसे जो मिला है, उसका मूल्यांकन करने का समय उसके पास नहीं है। उसकी दृष्टि सदा उसी पर टिकी रहती है, जो अभी तक नहीं मिला।

यदि मनुष्य उन वस्तुओं को गिने जो उसे सहजता से उपलब्ध हैं, जैसे स्वच्छ वायु, पेयजल और स्वस्थ देह तो पाएगा कि ये सभी वरदान हैं। हालांकि उनकी स्वाभाविक सुलभता से हम इन्हें अधिकार समझ बैठते हैं। इनके अतिरिक्त आर्थिक अभाव न होना, स्नेहमयी परिवार, अच्छे सहकर्मी, बुरे समय में मिला कोई मददगार, ये सब ईश्वरप्रदत्त आशीर्वाद का ही हिस्सा है, परंतु इन सभी को भूलकर हम मात्र उस एक अभाव के लिए विलाप करते हैं जो जीवन में प्रतिकूलता दे रहा है। सारी अनुकूलताओं पर एक प्रतिकूलता भारी पड़ जा रही है। धन्यवाद-ज्ञापन शिकायतों की पोटली के नीचे दब जाता है।

कृतज्ञ होना परिष्कृत आत्मा का एक संस्कार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद कहना सीख लेता है, वह अभाव में भी संपन्न रहता है। जबकि, जो सब पाकर भी असंतुष्ट है, वह संपन्नता में भी दरिद्र रहता है। मनुष्य प्रकृति को एक भंडारगृह समझ बैठा है, जहां से जितना चाहे, उतना लिया जा सकता है। आध्यात्मिक सत्य यही है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध उपभोग का नहीं, सहभाग का है। कृतज्ञ होने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम अकेले उपभोग के अधिकारी नहीं हैं और हमने पहले से ही आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर रखा है, इसलिए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए।

त्रिवंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

जाति को लेकर एक नई दृष्टि

'जाति निर्धारण पर नई दृष्टि' शीर्षक से प्रकाशित डा. ऋतु सारस्वत का आलेख भारतीय समाज की जटिल वास्तविकताओं और न्यायिक दृष्टि को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि जाति की पहचान केवल जन्म प्रमाण या पितृवंशीय आधार तक सीमित नहीं की जा सकती, बल्कि व्यक्ति ने जिस सामाजिक परिवेश में जीवन जिया है, जैसा भेदभाव या सामाजिक बाधाएं झेली हैं, वे भी उतनी ही निर्णायक हैं। विशेष रूप से अंतरजातीय विवाह के मामलों में, जहां बच्चे की परवरिश और अनुभव उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, वहां यांत्रिक नियमों के बजाय तथ्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जरूरी है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि जाति-आधारित आरक्षण का उद्देश्य मात्र कानूनी श्रेणी प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की भरपाई भी है। न्यायालय का निर्णय न केवल प्रशासनिक निर्णयों में अधिक संवेदनशीलता लाने की अपेक्षा करता है, बल्कि भविष्य की नीति-निर्धारण प्रक्रिया को भी वास्तविक सामाजिक प्रभावों के आधार पर अधिक न्यायसंगत बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देता है।

आयुष्मान पाण्डेय, सीतापुर

स्मृतियों में दर्ज रहेगा 2025

जाने वाला वर्ष 2025 भारत के इतिहास में केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि स्मृतियों में दर्ज वे जख्म छोड़ गया है, जो समय के साथ भी आसानी से भरने वाले नहीं हैं। यह साल एक ओर विज्ञान, कूटनीति, खेल और अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत का साक्षी बना, तो दूसरी ओर आतंक, तकनीकी विफलताओं, भीड़ प्रबंधन की चूक और सुरक्षा में सेंध ने पूरे राष्ट्र को भीतर तक झकझोर दिया। कश्मीर की शांत वादियों में पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने मानवता को शर्मसार किया और यह एहसास कराया कि आतंकवाद का जहर अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि 'आपरेशन सिंदूर' के जरिए भारत ने यह संदेश भी दिया कि वह चुप बैठने वाला नहीं है। राजधानी दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुआ कार ब्लास्ट यह बताने के लिए काफी था कि खतरे केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि समाज के भीतर छिपे षड्यंत्रों से भी पैदा होते हैं, जहां पढ़े-लिखे और प्रतिष्ठित चेहरे भी हिंसा के सूत्रधार बन सकते हैं। बेंगलुरु में आइपीएल जीत का उत्सव जिस तरह मातम में बदला, उसने साबित कर दिया कि खुशियों के क्षण भी अव्यवस्था और लापरवाही के कारण त्रासदी बन सकते हैं, वहीं अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा तकनीकी उत्कृष्टता के दौर में भी मानवीय और प्रणालीगत चूक की भयावह कीमत को सामने ले आया। प्रयागराज महाकुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ों ने यह कड़वा सच उजागर किया कि आस्था, यात्रा और उत्सव के आयोजनों में योजनाओं का अभाव सीधे जानलेवा बन जाता है। कुल मिलकर इस वर्ष ने हमें कई सौगात दी तो कई ऐसे दुखद अनुभव भी दिए हैं जिन से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है। जिससे जीवन सुगम हो सके।

विभूति बुपक्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली

क्या हम एक हैं

जब भी हमारे देश पर कोई संकट आता है, तब हम सब एक हो जाते हैं, चाहे किसी भी प्रांत के हों, किसी भी धर्म या भाषा के लोग हों , लेकिन सामान्य हालात में हम प्रांत, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर बंटे हुए हैं। कभी उत्तर-पूर्व के राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट होती है। कभी जम्मू-कश्मीर में हिंदी क्षेत्र के मजदूरों की चुन-चुन कर हत्याएं होती हैं तो कभी महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने वाले दूसरे प्रांत के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन हम सब इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेते और चुप रहते हैं, ऐसी ही घटनाएं जब विदेशों में भारतीयों के साथ होती हैं तो हम अपना विरोध जताते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक छात्र की नस्लीय टिप्पणी के बाद हुई हत्या परेशान कर देने वाली है। जब एक भारतीय छात्र की हत्या अपने ही देश में हो सकती है तो विदेशों में क्या स्थिति रहती होगी, केवल कल्पना ही की जा सकती है। अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए या पढ़ाई के लिए जाने पर भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही देश में हम शांति से अपने त्योहार भी नहीं मना सकते। हम ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि हम एक हैं। चाहे वह त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला हो चाहे क्रिसमस पर घटी घटनाओं का मामला हो, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी हैरान और परेशान करने वाली है। समाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी गर्व से कह सकेंगे कि हम सब एक हैं।

चरनजीत, नरेला दिल्ली

पोस्ट

बेनजीर भुट्टो की बरसी पर एक कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो ने भाषण में सेना के भारत विरोधी एजेंडे को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने उसी सेना का महिमामंडन किया, जिसके बारे में आशंका जताई जाती है कि उसकी शह पर ही बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई। पतन की मिसाल बने बिलावल। ताहा सिद्दीकी@TahaSSiddiqui

बांग्लादेश की राजनीति दशकों तक जिन दो महिलाओं के इर्दगिर्द घूमती रही, उनमें से एक खालिदा जिया का निधन हो गया और शेख हसीना देश छोड़कर विदेश में रहने पर विवश हैं। एक पड़ोसी होने के नाते हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश नाकाम पाकिस्तान की राह पर न जाए और चुनाव के वक्त कटुता के बजाय विकास को प्राथमिकता दे। प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

त्रिपुरा के छात्र के साथ उत्तराखंड में जो हुआ, उसकी कोई माफी संभव नहीं। हमारे यहां तो अतिथि का मान-सम्मान, प्यार और मिल-जुलकर रहना नसों में दौड़ता है, लेकिन एंजेल पर हमले ने शर्मसार कर दिया है। इसमें अपराधियों को ऐसी सजा मिले, जो मिसाल बने।

मीनाक्षी कंडवाल@MinakshiKandwal

जनपथ

हम अपने ही बंधु को ना पाते पहचान,
पूर्वोत्तर के पूत की गई इसी में जान।
गई इसी में जान आज हम हैं शर्मिंदा,
मृत सा दिखे समाज न है मानवता जिंदा।
'कुटुंबकम वसुधैव' मंत्र आता है जपने,
लेकिन भाई-बंधु मारते हैं हम अपने!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 166

****

भारत को आशा और विश्वास की नजरों से देख रही दुनिया : पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वर्ष 2025 की विदायी बेला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया है कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया। इसके साथ ही पीएम ने भविष्य का संकेत भी दिया। कहा कि हम आने वाले वर्षों में भी सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने देशवासियों सहित अन्य देशों से आग्रह किया कि भारत की विकास यात्रा से अपना जुड़ाव और मजबूत करें। भारत पर भरोसा बनाए रखें और निवेश करते रहें। दो महीने बाद आने वाले आम बजट से पहले प्रधानमंत्री का यह संकेत खास महत्व रखता है।

इंटरनेट मीडिया लिंक्डइन पर मंगलवार को किए पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अगली पीढ़ी के सुधारों के माध्यम से प्रगति की गति बढ़ाने के लिए विश्व द्वारा सराहा जा रहा है। भारत अपने लोगों के नवाचार के उत्साह के कारण वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है। अब विश्व भारत को आशा और विश्वास के साथ देखता है। जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हाल ही में मुख्य सचिवों के साथ बैठक में विचार-विमर्श कर चुके पीएम ने कहा कि वह कई लोगों से कहते रहे हैं कि भारत 'सुधार एक्सप्रेस' पर सवार हो चुका है। इस 'सुधार एक्सप्रेस' का प्राथमिक इंजन भारत की जनसंख्या, युवा पीढ़ी और देश के लोगों का अदम्य साहस है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी, बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति सहित सुधारों के कुछ उदाहरण भी दिए। कहा कि जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब लागू किए गए हैं। इससे आम लोगों पर बोझ कम हुआ है। पीएम ने याद दिलाया कि मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी गई है। पहली बार 12 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह 1961 के आयकर अधिनियम के स्थान पर आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम, 2025 लाया गया है।

नई दिल्ली में मंगलवार को नीति आयोग में बजट-पूर्व बैठक में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● प्रेट्र

दीर्घकालिक वृद्धि कायम रखने के लिए मिशन रूप में सुधारों की जरूरत : पीएम

नई दिल्ली, प्रेट्र: दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में मिशन रूप में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के संदर्भ में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत में यह बात कही। संवाद का विषय 'आत्मनिर्भरता एवं संरचनात्मक रूपांतरण: विकसित भारत के लिए एजेंडा' था। उन्होंने कहा कि भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया और बजट निर्धारण में 2047 के लिए संकल्प को केंद्रीय रूप से रखा जाना चाहिए। देश को वैश्विक श्रम शक्ति व अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाए रखना जरूरी है।

तृणमूल विधायक ने दूसरे दिन बंद करवाई एसआइआर की सुनवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस विधायक असित मजूमदार ने एसआइआर सुनवाई केंद्रों में अपनी पार्टी के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की नियुक्ति की मांग करते हुए लगातार दूसरे दिन सुनवाई बंद करा दी। मजूमदार ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ हुगली जिले के चुंचुड़ा-मगरा प्रखंड कार्यालय में जाकर वहां सुनवाई बंद कराई थी, वहीं मंगलवार को वे पोलबा के प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और वहां सुनवाई रुकवा दी। विधायक ने सुनवाई के लिए वहां पहुंचे लोगों से कहा-'आप लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्या आप इसे सहना चाहते हैं?' इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) से सुनवाई की प्रक्रिया रोकने को कहा।

संभल में बवाल, चले धारदार हथियार

जासं, संभल : उप्र में संभल जिले के गांव बिलालपत में फर्जी मतदाता प्रकरण की जांच करने गईं डिप्टी कलक्टर नीतू रानी व नायब तहसीलदार के सामने शिकायतकर्ता व आरोपित पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने मारपीट शुरू कर दी। धारदार हथियार से हमला कर दिया। अधिकारियों ने कमरे में बंदकर अपनी जान बचाई। इस प्रकरण में पुलिस ने प्रधान पति सहित पांच आरोपितों को नामजद करते हुए नौ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

एक नजर में

नीतीश से मिल मंत्री ने रखी मांग, भूमिहीनों को उपलब्ध कराएं जमीन

पटना : बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने मंगलवार को एक, अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पांच मांगों को लेकर एक अनुरोध पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिलों में भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अभियान चलाकर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दें। (राब्यू)

एसआइआर सुनवाई से पहले बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

कोलकाता : बंगाल में एसआइआर की सुनवाई के लिए सोमवार को पेश होने से कुछ घंटे पहले पुरुलिया जिले में 82 वर्षीय बुजुर्ग ने कथित तौर पर चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मृतक की पहचान दुर्जन माझी के रूप में हुई है। मृतक के बेटे कनाई ने दावा किया कि उनके पिता एसआइआर सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद से चिंतित थे क्योंकि उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं था। (राब्यू)

इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। पीठ ने कहा कि लेन-देन के करीब एक दशक बाद कार्रवाई शुरू हुई और ऐसे हालात में आरोपित को जेल में रखना उचित नहीं है। कहा मामले में लंबी देरी और परिस्थितियों को देखते हुए हिरासत जारी रखना न्यायसंगत नहीं। (जासं)

एसआइआर पर सवाल, पर दावे व आपत्तियों पर विपक्षी दल सुस्त

मसौदा सूची में लगभग साढ़े तीन करोड़ पूर्व मतदाता हटाए गए

- बंगाल में अब तक साढ़े तीन करोड़ हटे हुए नामों के अनुपात में करीब 1800 आवेदन
- एसआइआर पर सबसे मुखर तृणमूल ने बंगाल में नाम जोड़ने के लिए किए सिर्फ तीन आवेदन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर भले भी विपक्षी दल चुनाव आयोग पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटाने का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन जारी की गई मसौदा सूची पर मांगे गए दावे-आपत्तियों पर उनका रवैया पूरी तरह से सुस्त है। बंगाल सहित 11 राज्यों में जारी मसौदा सूची में लगभग साढ़े तीन करोड़ पूर्व मतदाताओं को हटाया गया है। इन सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दलों की ओर से करीब 18 सौ आवेदन ही आए हैं। इनमें अधिकांश आवेदन नाम जोड़ने वाले हैं। कटे हुए नाम को लेकर आपत्तियां बहुत कम हैं।

एसआइआर के मुद्दे को बंगाल में खूब तूल दिया जा रहा है, वहां अब तक मसौदा सूची को लेकर सिर्फ आठ दावे-आपत्तियां ही आई हैं। यह सभी नाम जोड़ने के लिए की गई है। इनमें तृणमूल कांग्रेस ने तीन, सीपीआइ (एम) ने दो, भाजपा और इंडिया फारवर्ड ब्लाक की ओर से एक-एक आवेदन किए गए हैं। बंगाल की मसौदा सूची 16 दिसंबर को जारी हुई थी। बंगाल में राजनीतिक दलों ने अपने दो लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की तैनाती की है। इनमें तृणमूल कांग्रेस ने 77 हजार से अधिक बीएलए तैनात किए हैं। इसके साथ ही केरल में अब तक एक भी दावे-आपत्तियां नहीं आई हैं। वहीं तमिलनाडु में अब तक कुल 112 आवेदन आए हैं। इनमें 64 नाम हटाने के लिए, जबकि 48 जोड़ने वाले हैं। ये आवेदन डीएमके ने सिर्फ 24 आवेदन नाम जोड़ने के लिए ही किए हैं। गुजरात में अब तक कुल 132 आवेदन मिले हैं, इनमें 129 भाजपा ने और नौ आप ने किए हैं। राजस्थान में भी सिर्फ 373 दावे-आपत्तियां मिली हैं। इनमें भाजपा ने 193 व कांग्रेस ने 178 आवेदन किए हैं। जिन 11 राज्यों की मसौदा सूची जारी हो चुकी है, उनमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 1123 दावे-आपत्तियां मिली हैं। इनमें 820 भाजपा ने की है। इनमें भी 798 नाम जोड़ने के लिए है।

कांग्रेस नेता अधीर ने एसआइआर पर पीएम मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एसआइआर के मुद्दे पर मुलाकात की है। उन्होंने विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों पर हो रहे "हमलों" और बंगाल में पिछड़े मातुआ समुदाय को सामना कर रहे समस्याओं का मुद्दा उठाया।

बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे हमले रोकने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, जो उनके अनुसार राज्य में सांप्रदायिक तनाव और संभवतः हिंसा का कारण बन सकते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रवासी श्रमिकों और मातुआ समुदाय की समस्याओं का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा, "उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्थिति पर नजर रख रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए।" बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले इस बैठक के राजनीतिक महत्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली आया था; संयोगवश, मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। चौधरी ने मोदी को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को देश के कुछ हिस्सों में "घुसपैठिए" के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ● फाइल फोटो

शाह के प्रहार पर ममता का 'दुर्योधन-दु:शासन' पलटवार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठ और बाढ़ के लिए जमीन नहीं देने समेत कई मुद्दे पर बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'दुर्योधन-दु:शासन' कहकर पलटवार किया। अमित शाह ने राज्य सरकार पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन न देने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, ममता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्र पर एसआइआर के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

शाह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने बांकुड़ा के बड़जोरा की रैली में भाजपा नेताओं की तुलना महाभारत के पात्रों 'दुर्योधन' और 'दु:शासन' से कर दी। उन्होंने शाह को 'शकुनि का शिष्य' बताते हुए कहा कि चुनाव आते ही ये लोग बंगाल में घूमने लगते हैं। जमीन के मुद्दे पर ममता ने जवाब दिया कि उनकी सरकार ने पहले ही पेट्रापोल जैसे क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई है। कहा कि अगर राज्य ने जमीन नहीं दिया तो रेलवे और कोयला परियोजनाएं कैसे पूरी हुईं? उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए पूछा कि यदि घुसपैठ केवल बंगाल से हो रही है तो दिल्ली में विस्फोट और पहलगाम हमले कैसे हुए? ममता ने चुनाव के लिए 'फाटाफाटी खेला' का नया नारा दिया।

ममता-अभिषेक में दरार की जुगत में हुमायूं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक और जेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा कि यदि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उनके इस बयान को राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग ममता-अभिषेक के बीच दरार पैदा करने का प्रयास बता रहा है। मंगलवार को कोलकाता में पत्रकारों से कबीर ने कहा कि आगामी चुनाव में कोई भी दल बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा और सरकार बनाने की चाबी उनके पास होगी।

बंगाल में समय से पहले चुनाव के संकेत व चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में क्या आगामी विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले पूरी हो जाएगी? गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इस चर्चा को हवा दे दी है। मंगलवार को कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन के दौरान शाह ने दो बार स्पष्ट रूप से कहा कि बंगाल का चुनाव अप्रैल में ही संपन्न हो जाएगा। दावा किया कि अगले साल 15 अप्रैल के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बन जाएगी और बंगाल के गौरव की पुनः स्थापना का काम शुरू होगा। शाह के इस बयान के बाद बंगाल भाजपा में चुनावी तारीखों और चरणों को लेकर मंथन शुरू हो गया है।

350 विशेषज्ञों ने की मनरेगा को खत्म न करने की अपील

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार को कई शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं ने मंगलवार को खुला पत्र लिखकर मनरेगा को खत्म नहीं करने की मांग की। कहा कि इस योजना को खत्म करने के बजाय इसके कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। इस पत्र पर लगभग 350 शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

इसमें कहा गया है कि मनरेगा को खत्म करने और उसकी जगह वीबी-जी राम जी अधिनियम लाने के लिए दिए गए तर्कों में कई खामियां हैं। पत्र में कहा गया है कि मनरेगा की मांग-आधारित व्यवस्था क्रांतिकारी अवधारणा थी, जो अधिकार-आधारित रोजगार गारंटी के सिद्धांत से जुड़ी थी।

खुले पत्र में कहा- मनरेगा रद करने के बजाय इसकी कमियां सुधारें, वीबी-जी राम जी लाने के लिए दिए तर्कों में बताईं खामियां

विशेषज्ञों का कहना है कि नई योजना इस पूरी प्रक्रिया को कमजोर कर देगी। इस तर्क को भी गलत बताया गया कि मनरेगा के कारण खेती के सीजन में मजदूरों की कमी होती है। पत्र में कहा गया है कि मनरेगा की मजदूरी दर कृषि मजदूरी से 40 से 50 प्रतिशत तक कम है। बजट को केंद्र और राज्य के बीच साझा करने को लेकर पत्र में कहा गया है कि खर्च का बोझ राज्यों पर डालने से राजनीतिक भेदभाव बढ़ सकता है।

पंजाब विस में वीबी जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास

जागरण टीम, नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर लाए गए विकसित भारत जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाकर उसे बहुमत से खारिज कर दिया। इस प्रकार पंजाब विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाकर विरोध करने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं, भोपाल में मौजूद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार के बहुत मामले हैं लेकिन राज्य सरकार का ध्यान उधर नहीं है। सिर्फ विरोध की राजनीति की जा रही है। पंजाब में सोशल आडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में मात्र 5,915 में हुई। गबन के 10,653 मामले सामने आए, पर कार्रवाई नहीं की गई। इससे पूर्व, विधानसभा में जब प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, तब भाजपा के एकमात्र सदस्य अश्विनी शर्मा सदन में नहीं थे। हालांकि, उन्होंने बहस में भाग लिया।

मुख्यमंत्री विधान सभा में निंदा प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए ● जागरण

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने अवीवा बेग के साथ की सगाई

- इस समय राजस्थान के रणथंभौर में है जोड़ा
- हाल ही में रेहान ने अवीवा को किया था प्रपोज

<< सगाई के मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा के पुत्र रेहान और अवीवा बेग ● इंटरनेट मीडिया

जागरण न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व राबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी प्रेमिका अवीवा बेग के साथ एक निजी समारोह में सगाई कर ली है। रेहान और अवीवा बचपन के दोस्त हैं। हाल ही में रेहान ने अवीवा को प्रपोज किया था। इस समय यह जोड़ा परिवार और दोस्तों के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में है।

प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी, पति राबर्ट वाड्रा और परिवार के सदस्यों के साथ मंगलवार को रणथंभौर पहुंची हैं। चर्चा है कि रणथंभौर प्रवास के दौरान नए साल का स्वागत करेंगे। रेहान की अवीवा के साथ रिंग सेरेमनी का भी कार्यक्रम है। जयपुर संवाददाता के अनुसार रेहान और अवीवा ने मंगलवार को रणथंभौर की टाइगर-सफारी का भी आनंद लिया। दोनों सफारी के दौरान कैप पहने नजर आए और बाघिन टी-107 तथा उसके शावकों को देखा। रणथंभौर गांधी परिवार का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। इस साल राहुल का यह दूसरा दौरा है, प्रियंका तीसरी बार यहां पहुंची हैं। इस दौरान अवीवा के परिवार के साथ पांच सितारा होटल 'शेर बाग' में ठहरेंगे। रणथंभौर में सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ गई है। शेर बाग होटल में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। अवीवा दिल्ली के प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से हैं। उनके पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं। मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं। प्रियंका गांधी और नंदिता पुरानी दोस्त हैं। नंदिता ने कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' का इंटीरियर डिजाइन किया था, जिससे दोनों परिवारों का संबंध और गहरा हुआ। 25 साल के रेहान के इंटरनेट मीडिया हैंडल पर उन्हें "कलाकार" और फोटोग्राफर बताया गया है, वहीं जानकारी के मुताबिक अवीवा पेशे से प्रोड्यूसर और फोटोग्राफर हैं। वह फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी एटेलियर 11 की सह संस्थापक हैं।

अल्मोड़ा में 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस, सात की मौत

जासं, अल्मोड़ा : उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्टेयरिंग फेल होने से मंगलवार सुबह द्वाराहाट से रामनगर (नैनीताल) जा रही बस शिलापानी बैंड के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में बुजुर्ग दंपती समेत सात यात्रियों की मौत हो गई। 12 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

कुमाऊं मोटर आनर्स यूनियन (केमू) की बस सुबह करीब छह बजे 19 यात्रियों को लेकर द्वाराहाट के नोबाड़ा से रामनगर के लिए रवाना हुई। लगभग आठ बजे शिलापानी बैंड पर दो साल पूर्व केबिल बिछाने के लिए खोदी गई सड़क पर बने गड्ढे में बस का टायर चला गया। तभी स्टेयरिंग फेल होने से चालक नियंत्रण नहीं रख पाया। हादसे में छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिकियासैंण में भर्ती कराया गया। बाद में गंभीर रूप से घायल नंदा बल्लभ और हंसी देवी को एयर लिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। नंदी देवी, राकेश कुमार सहित चार घायलों को 108 एंबुलेंस से रामनगर और प्रकाश नैनवाल को अल्मोड़ा बेस अस्पताल भेजा गया।

- उत्तराखंड में शिलापानी के पास स्टेयरिंग फेल होने से हुआ हादसा
- गंभीर रूप से दो घायलों को ऋषिकेश एम्स किया गया एयर लिफ्ट

<< अल्मोड़ा के शिलापानी के पास दुर्घटनाग्रस्त बस ● जागरण

दो साल पुरानी लापरवाही बनी जानलेवा

दुर्घटनाग्रस्त 28 सीटर बस 2019 माडल की थी। परिवहन विभाग की जांच में सभी दस्तावेज भी ठीक मिले। हादसे के पीछे लोक निर्माण विभाग की लापरवाही बड़ी वजह बनकर सामने आई है। दरअसल, शिलापानी पुल के पास दो वर्ष पूर्व मोबाइल केबल बिछाने के दौरान सड़क को खोदा गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद आज तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। बड़े-बड़े गड्ढे जस के तस छोड़ दिए गए और औपचारिकता निभाने के लिए केवल मिट्टी डालकर उन्हें ढक दिया गया।

महायुति को झटका, आरपीआइ अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव

राज्य ब्यूरो, मुंबई : भाजपा-शिवसेना गठबंधन को एक बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आठवले) मुंबई महानगरपालिका का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर महायुति गठबंधन पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए आठवले ने नामांकन की अवधि समाप्त होने से कुछ घंटे पहले 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इससे भाजपानीत महायुति को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस इस बार प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन कर चुनाव में उतरी है। मंगलवार 15 जनवरी को होने वाले 227 सदस्यीय बीएमसी चुनावों के लिए नामांकन का अंतिम दिन था।

- नामांकन की अवधि समाप्त होने से कुछ घंटे पहले जारी की 39 उम्मीदवारों की सूची
- आठवले का आरोप, महायुति गठबंधन अपने वादों को पूरा करने में रहा विफल

पार्टी ने उत्तरी, उत्तर-मध्य, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी मुंबई की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आठवले का कहना है कि कई बार हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के बावजूद आरपीआइ (आठवले) को कथित तौर पर सीट वार्ता के अंतिम चरण तक अधर में लटकाए रखा गया। महायुति गठबंधन अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा।

दिग्विजय ने दिखाया जो आईना, वही देशभर में कांग्रेस की तस्वीर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कार्यसमिति की बैठक में संगठन की कमजोरी का मुद्दा खुलकर उठाया। हाईकमान सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने इसे अपने-अपने दृष्टिकोण से देखा-समझा। कुछ क्रिया-प्रतिक्रिया हुई और बात खत्म। मगर, कांग्रेस नेतृत्व यह देखने के लिए कतई तैयार नहीं हुआ कि दिग्विजय ने जो आईना दिखाने का प्रयास किया है, वही देशभर में कांग्रेस की वास्तविक तस्वीर है। राहुल गांधी सहित पार्टी के रणनीतिकार इस राजनीतिक-रणनीतिक विफलता से पूरी तरह नजरें फेरे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में उनके प्रदेश अध्यक्ष बिना सेना के सेनापति के रूप में खड़े हुए हैं। यह हाल तब है, जब कांग्रेस ने वर्ष 2025 को संगठन सृजन वर्ष का नाम दिया था।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर बसपा से आए बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन लगभग एक वर्ष तक प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन सकी। वर्ष 2023 में पूर्व विधायक अजय राय को राज्य संगठन की कमान सौंप दी गई। बताया कि सबसे पहले उनकी सहमति या विमर्श के बिना पदाधिकारी बना दिए गए। लोकसभा चुनाव उसी टीम के साथ हुए और दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदेश की सभी इकाइयां भंग कर दीं। तब से यूपी में प्रदेश अध्यक्ष अकेले खड़े हैं। अब यदि कोई तर्क दे कि 2027 के चुनाव से पहले संगठन तैयार हो जाएगा, तो उस बिहार पर भी दृष्टि डाल लें, जहां चुनाव हो चुका है। बिहार में संगठन की वास्तविकता यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन पहले मार्च में राजेश राम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। जिस समय राजेश राम ने संगठन की बागडोर संभाली, तब चुनाव सिर पर था और पार्टी के पास न तो प्रदेश कार्यकारिणी थी, न ही जिलों में मजबूत नेतृत्व का ढांचा। चुनाव में पार्टी छह सीटों पर सिमट गई। राजेश राम को नियुक्त हुए नौ माह से अधिक समय हो चुका, लेकिन प्रदेश की टीम अब तक नहीं बन सकी है।

हिमाचल-पंजाब का भी यही हाल: कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में पार्टी हाईकमान ने छह नवंबर, 2024 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला व ब्लाक कार्यकारिणियों को भंग किया था, अभी तक इनका गठन नहीं हो पाया है। कार्यकारिणी गठित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो रिपोर्ट छह महीने पहले दे चुके हैं। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अप्रैल 2022 में कार्यभार संभाला। उस समय उनके साथ आठ पदाधिकारी बनाए गए थे, जिसमें एक कार्यकारी प्रधान, एक महासचिव, एक खजांची और पांच उप प्रधान। वर्तमान स्थिति यह है कि कुल नौ में से प्रदेश प्रधान समेत पांच सदस्य काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के करीब 10 महीने बाद अक्टूबर 2024 में प्रदेश कमेटी गठित हो सकी थी।

- यूपी, बिहार और हिमाचल प्रमुख उदाहरण, प्रदेश अध्यक्षों के पास संगठन की टीम तक नहीं
- 2015 के बाद से बिहार कांग्रेस बिना विधिवत प्रदेश कार्यकारिणी के ही चल रही है

गलत राष्ट्रगान गाने पर कांग्रेस पर प्रहार

नई दिल्ली, आइएनएस : भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आइएनसी) पर तीखा हमला करते हुए इसे 'इस्लामाबाद राष्ट्रीय कांग्रेस' करार दिया। यह टिप्पणी केरल में एक कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के गलत गायन के बाद आई है।

शहजाद ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करती है और इसलिए भारत का राष्ट्रगान सही तरीके से गाने में असफल रहती है। बताया कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

****

अर्थ जागरण

सेंसेक्स 84,675.08	सराफा दिल्ली के भाव	सोना ₹ 1,39,000 10 ग्राम	चांदी ₹ 2,41,000 1 किलो	डालर($) ₹ 89.75
↓ 20.46		↓ ₹2,800	↑ ₹1,000	↓ ₹0.23

एक नजर में

वीई कमर्शियल व्हीकल्स से 192 करोड़ जीएसटी मांगा

नई दिल्ली: आयशर मोटर्स लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसकी सब्सिडियरी वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड को 192.36 करोड़ रुपये का जीएसटी मांगा गया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान क्रेडिट नोट्स की जानकारी देरी से देने के कारण यह जीएसटी मांगा गया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि तय समय सीमा के अंदर सही फोरम में अपील दायर की जाएगी। उधर, कृषि एवं कंस्ट्रक्शन उपकरण बनाने वाली कंपनी एस्कार्ट कुबोटा ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के कर प्राधिकरणों ने उससे 3.4 करोड़ रुपये का टैक्स मांगा है। (प्रेट्र)

हुंडई मोटर ने वाणिज्यिक मोबिलिटी में रखा कदम

नई दिल्ली: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को 'प्राइम टैक्सी' रेंज के तहत अपनी खास टैक्सी लांच करके वाणिज्यिक मोबिलिटी सेगमेंट में कदम रखने की घोषणा की। कंपनी के प्रबंध निदेशक तरुण गर्ग ने कहा कि फ्लीट आपरेटरों और टैक्सी मालिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई प्राइम रेंज विश्वसनीयता, कम ओनरशिप लागत और बेहतर आराम के साथ अच्छी कमाई का मौका देती है। (प्रेट्र)

स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड ने की दिसंबर सेल की घोषणा

नई दिल्ली: रसोई और खाना पकाने से जुड़े उत्पाद बनाने वाली दिग्गज कंपनी स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड ने अपनी दिसंबर सेल के 16वें संस्करण की घोषणा की है। इसमें यूनिक काम्बो आफर दिए जा रहे हैं, जिनकी कीमतें आने वाले नए साल 2026 के नंबर के बराबर हैं। सेल में प्रेशर कुकर व इंडक्शन कुकटाप काम्बो, ब्रेकफास्ट काम्बो (केटल, वाटर बोतल, पाप-अप टेस्टर) और एलपीजी गैस स्टोव व कुकवेयर काम्बो प्रमुख हैं। सेल में ऐसे ही दूसरे काम्बो ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी पीजन और गिलमा ब्रांड नाम से अपने उत्पादों की बिक्री करती है। (वि.)

अब साप्ताहिक आधार पर बदलेगा क्रेडिट स्कोर

एक जनवरी 2026 से बदलने जा रहे कई वित्तीय-गैर वित्तीय नियम, वाहन खरीदना भी होगा महंगा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: प्रत्येक महीने की एक तारीख से कई प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय नियमों में बदलाव होता है। इस बार भी एक जनवरी 2026 से कई नियम बदल रहे हैं, जिसका आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें क्रेडिट स्कोर, यूपीआइ केवाईसी पर सख्ती जैसे वित्तीय नियमों के साथ पीएम किसान से जुड़े गैर-वित्तीय नियम भी शामिल हैं।

अभी तक क्रेडिट स्कोर की जानकारी देने वाली कंपनियां या एजेंसी आमतौर पर मासिक आधार पर डाटा अपडेट करती हैं। एक जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इससे लोन की मासिक किस्त (ईएमआइ) या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में होने वाली एक दिन की देरी भी आपके क्रेडिट स्कोर पर तुरंत दिखाई देगी। दूसरी ओर, समय पर भुगतान करने वालों के क्रेडिट स्कोर में तेजी से सुधार होगा और उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।

वाहनों के मूल्य में होगी बढ़ोतरी

एक जनवरी 2026 यानी नव वर्ष के पहले दिन से वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। इसका कारण यह है कि लक्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, निसान समेत जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनो और इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता एथर एनर्जी अपने वाहनों के मूल्य में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी हैं। कई अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के मूल्य में बढ़ोतरी के संकेत दे रही हैं। बता दें कि सितंबर में जीएसटी दरों में कटौती के बाद वाहनों के मूल्य में 8-10 प्रतिशत की कमी आई थी।

सख्त होगी यूपीआइ केवाईसी

डिजिटल और बैंकिंग धोखाधड़ी को देखते हुए एक जनवरी से डिजिटल लेनदेन के नियम सख्त होने जा रहे हैं। सरकार और आरबीआइ के निर्देशानुसार, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) प्लेटफार्म्स (गूगलपे, फोनपे, पेटीएम और वाट्सएप) को अब ज्यादा सख्त केवाईसी (अपना ग्राहक जानों) प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियमों के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा रही है ताकि फर्जी खातों पर लगाम लगाई जा सके।

पीएम-किसान योजना के लिए नई प्रणाली

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत नई किसान आइडी प्रणाली पेश की है। एक जनवरी 2026 से पीएम किसान योजना से जुड़ने वाले किसानों के लिए यह आइडी अनिवार्य होगी। इस डिजिटल आइडी से किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक की जानकारी जुड़ी होगी। इससे किसानों को सरकारी लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी। योजना के मौजूदा लाभार्थी इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे।

2-3 रुपये सस्ती होगी सीएनजी और पीएनजी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से घोषित टैरिफ समायोजन एक जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इससे वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में प्रयोग होने वाली पीएनजी की कीमतों में प्रति यूनिट 2-3 रुपये की कमी आएगी। इस कमी से पूरे देश के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। निजी क्षेत्र की कंपनी थिंक गैस उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में सीएनजी के मूल्य में 2.50 रुपये प्रति किलो और पीएनजी के मूल्य में करीब तीन रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की घोषणा कर चुकी है।

चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद: इक्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र: चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित 6.5% विकास दर से बेहतर है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक वृद्धि दर लगभग आठ प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, दूसरी छमाही में विकास दर के सात प्रतिशत से नीचे रहने की संभावना है, क्योंकि अच्छा आधार प्रभाव कम हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी चुनौतियां खासकर कमजोर निर्यात साल के आखिर में आर्थिक गतिविधियों पर असर डाल सकती है और इसका असर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पूरा होने तक दिखाई दे सकता है। इक्रा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियां अच्छी रहीं और इसे जीएसटी दरों में कटौती के बाद त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने से सहारा मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में और

एजेंसी ने कहा- बाहरी चुनौतियां खासकर कमजोर निर्यात साल के आखिर में आर्थिक गतिविधियों पर डालेगा प्रभाव

मंदी आने की उम्मीद है और इसका असर विकास दर पर दिखाई देगा। आर्थिक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि मजबूत नीतिगत मदद की वजह से 2025 में विकास दर के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। उन्होंने कहा कि आयकर में राहत, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और रेपो रेट में 125 आधार अंकों की कटौती और नकदी उपायों ने मांग बढ़ाने में मदद की। उन्होंने आगे कहा, 'कम महंगाई ने घरेलू बजट पर दबाव कम किया, जबकि सामान्य से बेहतर मानसून ने खेती के उत्पादन को सहारा दिया।' हालांकि, बाहरी मोर्चे पर चिंताएं बनी हुई हैं और अगर अमेरिका के साथ जल्द ही व्यापार समझौता नहीं होता है तो यह छोटी अवधि में विकास दर पर असर डालर सकता है।

2025 में आवासीय संपत्तियों का पंजीकरण पांच प्रतिशत घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स ने मंगलवार को बताया कि देश के नौ प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों का पंजीकरण इस वर्ष 25 दिसंबर तक पांच प्रतिशत घटकर 5.45 लाख इकाई रहा है। हालांकि, इस दौरान मूल्य 11 प्रतिशत बढ़कर 4.46 लाख करोड़ रुपये रहा है।

रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने पुणे, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पंजीकृत संपत्तियों के डाटा के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक (रीसेल) बाजारों से जुड़े लेनदेन शामिल हैं। 2024 के दौरान, पंजीकरण की संख्या 5.77 लाख इकाई थी, जिनका मूल्य 4.03 लाख करोड़ रुपये था। स्क्वायर याड्र्स के सीईओ तनुज शोरी ने कहा कि 2026 में आवासीय संपत्ति बाजार का परिदृश्य सकारात्मक है।

बीते तीन सालों के दौरान करीब चार गुना बढ़ा गोल्ड लोन

नई दिल्ली, एएनआइ: सोने की बढ़ती कीमतों और अर्ध शहरी व ग्रामीण भारत से आ रही लगातार मांग के चलते पिछले तीन सालों में गोल्ड लोन लगभग चार गुना बढ़ गए हैं।

एंटीक स्टाक ब्रोकिंग के बीएफएसआइ कांफ्रेंस 2025 में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार, 60 प्रतिशत से ज्यादा नए खुदरा कर्ज की मांग अब अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत से आ रही है। देश के इन इलाकों में सोना परंपरागत रूप से ना केवल स्वीकार्य बल्कि कोलैटरल के तौर पर स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि इन क्षेत्रों में डिफाल्ट भी ज्यादा है। गोल्ड लोन पर कुल बकाया अक्टूबर, 2025 के अंत तक साल-दर-साल 128.5% बढ़कर 3.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत से आ रही 60 प्रतिशत से ज्यादा नए खुदरा कर्ज की मांग, सोने की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका

रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गोल्ड लोन को असुरक्षित ऋण की बजाय तेजी से वितरण, लचीला पुर्नभुगतान विकल्प और कम ब्याज दर के कारण पसंद किया जाता है।

विशेषज्ञों ने बताया कि गोल्ड लोन ऐसे समय में विकास का एक अच्छा जरिया बन गया है जब पूरे सिस्टम में फंसे हुए कर्जों को बट्टे खाते में डालने को लेकर नियम कड़े हो गए हैं। कई बैंकों ने अगले दो सालों में गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्रांच नेटवर्क को और बढ़ाने की योजना का संकेत दिया है।

दिसंबर में घट सकता है भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिसंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से घट सकता है, लेकिन यह गिरावट आपूर्ति स्रोतों में किसी संरचनात्मक बदलाव के बजाय अल्पकालिक बाधाओं को दर्शाती है।

ताजा आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी केप्लर के अनुसार दिसंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) रहने का अनुमान है, जो नवंबर में 18.4 लाख बीपीडी था। यह स्तर दिसंबर 2022 के बाद सबसे निचला होगा। भारतीय रिफाइनरी गैर-प्रतिबंधित इकाइयों से रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। विश्लेषकों ने अक्टूबर में ही इस गिरावट की ओर इशारा किया था। ऐसा रूस के शीर्ष निर्यातकों पर अमेरिकी कार्रवाई तथा यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के चलते हुआ है।

सस्ते हो सकते हैं एयर व वाटर प्यूरीफायर

नई दिल्ली, आइएएनएस: जीएसटी कांउसिल एयर और वाटर प्यूरीफायर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। इतना ही नहीं, इन दोनों उत्पादों को कंज्यूमर गुड्स के बजाय जरूरी चीजों की श्रेणी में डाल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इन दोनों उत्पादों की खुदरा कीमतों में 10-15 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इससे कम आय वाले परिवार भी इसका उपयोग कर सकेंगे।

अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख अभी तय नहीं है। काउंसिल की पिछली बैठक सितंबर में हुई थी और उस समय प्यूरीफायर पर कर की दरों को कम करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया था। उस समय अधिकारियों ने कहा था कि किसी भी उत्पाद पर जीएसटी रेट को घटाने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के बीच आम सहमति होना जरूरी है। दरअसल,

18 से घटाकर पांच प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है काउंसिल दोनों उत्पादों पर जीएसटी को

- **अगर ऐसा होता है तो इन दोनों उत्पादों की खुदरा कीमतों में आ सकती है 10 से 15 प्रतिशत की कमी**

कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि अगर जरूरी हो तो दिल्ली-एनसीआर में खराब होती हवा की गुणवत्ता के बीच एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को कम करने या खत्म करने पर विचार करने के लिए वर्चुअल मीटिंग बुलाई जाए। इसके बाद कीमतों में कटौती का काउंसिल पर दबाव बढ़ गया है।

कोर्ट को दिए जवाब में एडिशनल सालिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा था कि यह एक प्रक्रियागत मामला है और हम यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक फिजिकली होनी चाहिए। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में लाने की मांग की गई थी और केंद्र से कहा गया था कि वह अस्थायी तौर पर जीएसटी छूट देने के लिए तुरंत निर्देश दे। जनहित याचिका के मुताबिक, हाई-एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर (एचईपीए) फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर पीएम2.5, पीएम10 और सांस और दिल की बीमारियों को बढ़ाने वाले दूसरे खतरनाक प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

रेलवन एप से टिकट खरीदने पर मिलेगी तीन प्रतिशत छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र: रेलवन एप के जरिये अनारक्षित टिकटों की डिजिटल खरीद पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेलवे मंत्रालय 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक रेलवन एप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट देगा। फिलहाल रेलवन एप पर आर-वालेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत 'कैशबैक' मिलता है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) को भेजे गए पत्र में साफ्टवेयर प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है।

पत्र में कहा गया, डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रेलवन एप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक मिलेगी। पत्र में स्पष्ट है कि रेलवन एप पर 'आर-वालेट' से बुकिंग पर मौजूदा तीन प्रतिशत 'कैशबैक' जारी रहेगा। एक अधिकारी ने कहा, अभी रेलवन पर अनारक्षित टिकट खरीदने व आर-वालेट से भुगतान पर तीन प्रतिशत 'कैशबैक' दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट में वकील तय समय सीमा में करेंगे बहस

माला दीक्षित ● जागरण

नई दिल्ली: नए वर्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील तय समय सीमा के भीतर अपनी मौखिक दलीलें रखेंगे। उन्हें समय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वकीलों की मौखिक बहस के लिए समय सीमा का नियम लागू किया है। कोर्ट ने त्वरित न्याय और प्रभावी कोर्ट प्रबंधन के उद्देश्य से वकीलों की मौखिक बहस के बारे में समय सीमा पालन करने का नियम लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक किसी भी मामले में कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद नियमित सुनवाइयों में मौखिक दलीलों के लिए तय समय सीमा का यह नियम और एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को शीघ्र न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे मौखिक दलीलों में लगने वाले समय की अनिश्चितता समाप्त होगी और केस का जल्दी निस्तारण होगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मौखिक बहस के लिए टाइमलाइन की एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करने का उद्देश्य प्रभावी कोर्ट प्रबंधन, न्यायालय के कार्य घंटों का समान वितरण और न्याय का त्वरित एवं उचित प्रशासन सुनिश्चित करना है। एसओपी के अनुसार, किसी मामले में नोटिस जारी होने के बाद होने वाली नियमित सुनवाई में वरिष्ठ वकील, बहस करने वाले वकील या एडवोकेट आन रिकार्ड (एओआर), सुनवाई शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले मौखिक बहस की टाइमलाइन कोर्ट में दाखिल कर देंगे। यह समय सीमा वकीलों को मामले में पेश होने की पर्ची (एपियरेंस स्लिप) देने वाले आनलाइन पोर्टल पर देनी होगी।

- **शीर्ष अदालत ने त्वरित न्याय और प्रभावी कोर्ट प्रबंधन के लिए जारी की एसओपी**
- **सुनवाई से एक दिन पहले मौखिक बहस की टाइमलाइन कोर्ट में दाखिल करनी होगी**

केशवानंद भारती मामले में चली थी सबसे लंबी बहस

अभी तक केशवानंद भारती का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। यानी वकीलों ने मौखिक दलीलें 68 दिनों तक रखी थीं। दूसरे नंबर पर राम जन्मभूमि का केस आता है, जिसकी सुनवाई 40 दिनों तक चली थी। लेकिन शायद अब कभी ये रिकार्ड न टूटे, क्योंकि कोर्ट ने वकीलों की मौखिक दलीलों के लिए जो टाइमलाइन के पालन का नियम लागू किया है, उसमें भविष्य में कभी ऐसी नौबत आने की संभावना नहीं दिखती।

बहस करने वाले वकील या वरिष्ठ वकील अपने एओआर के जरिये या कोर्ट द्वारा नामित नोडल वकील के जरिए सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले संक्षिप्त नोट या लिखित दलीलें दाखिल करेंगे, ताकि समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सके। लिखित दलीलें भी पांच पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और लिखित दलीलों की प्रति दूसरे पक्ष को दी जाएगी। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी वकील मौखिक बहस समाप्त करने में तय सीमा का कड़ाई से पालन करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पद संभालते ही कहा था कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने संविधान पीठों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे की बात भी कही थी, ताकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि संविधान पीठों मे लंबित कानूनी मुद्दों के सैकड़ों मामले निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आने के बाद जल्दी ही निस्तारित हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पद संभालते समय कहा था कि वह विभिन्न उच्च न्यायालयों से ऐसे केसों की सूची मंगाएंगे, जिनके मामलों में कानूनी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों में लंबित केस में विचाराधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार केस लंबित: सुप्रीम कोर्ट में इस समय 92,010 केस लंबित हैं। इनमें से 72,658 दीवानी और 19,352 क्रिमनल केस हैं। इनमें 219 केसों की सुनवाई तीन जजों की पीठ, 27 मामलों की सुनवाई पांच जजों की पीठ, छह मामलों की सुनवाई सात जजों और चार केसों की सुनवाई नौ जजों की पीठ में होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ष मुकदमों के निस्तारण की दर 87 प्रतिशत रही।

एसआइटी करेगी एंजेल चकमा हत्याकांड की जांच

जासं, देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून के सेलाकुई में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या की जांच के लिए एसपी देहात की देखरेख में एसआइटी गठित की गई है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सीओ स्तर के अधिकारी को पूरे प्रकरण की विवेचना सौंप दी है।

एसएसपी ने कहा कि पीड़ित के स्वजन व किसी अन्य व्यक्ति को यदि प्रकरण से संबंधित कोई भी साक्ष्य व तथ्य उपलब्ध कराने हों तो वह विवेचक को उपलब्ध करा सकते हैं। उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि नाबालिग आरोपित ने एंजेल चकमा के सिर पर लोहे के कड़े से वार किया था, जबकि फरार चल रहे नेपाल निवासी आरोपित यज्ञराज अवस्थी ने चाकू से हमला किया। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण एंजेल की मौत हुई है। ग्राफिक एरा अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द किया गया। सघटना में शामिल फरार चल रहे यज्ञराज अवस्थी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

एनएचआरसी ने हत्याकांड में देहरादून के जिलाधिकारी-एसएसपी को भेजा नोटिस

जाब्यू, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नस्ली भेदभाव के चलते देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने छात्र की हत्या से संबंधित शिकायत पर देहरादून के जिलाधिकारी और एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए आरोपों की जांच कर सात दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने के साथ ही आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण कानून की धारा 12 के तहत शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्र एंजल पर नौ दिसंबर को कुछ युवकों ने चाकू और ब्रेसलेट से कथित तौर पर हमला कर दिया था।

ज्योतिर्लिंग का क्षरण रोकने को महाकाल को भारी माला चढ़ाने पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल को फूलों की बड़ी व भारी माला (अजगर माला) पहनाने पर एक जनवरी से स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग क्षरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने फूलों की छोटी माला तथा सीमित मात्रा में फूल अर्पित करने का सुझाव दिया है। इसके परिपालन में मंदिर प्रशासन ने छह अप्रैल 2019 को आदेश जारी कर भगवान को भारी माला पहनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं कराया जा सका।

इस बाबत दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मंदिर प्रशासन ने पूर्व में जारी अपने आदेश पर अमल करते हुए पुनः आदेश जारी किया। मौजूदा आदेश में 2019 के आदेश का हवाला भी दिया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अश्लील और गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करें, नहीं तो परिणाम भुगतें

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने आनलाइन प्लेटफार्मों खासकर इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आगाह किया है कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी व अन्य गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 दिसंबर को जारी परामर्श में इंटरनेट मीडिया कंपनियों से कहा कि वे तत्काल अपने अनुपालन ढांचे की समीक्षा करें और अपने प्लेटफार्म पर अश्लील एवं गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

परामर्श में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों समेत तमाम आनलाइन प्लेटफार्मों को याद दिलाया जाता है कि वे अपने मंचों पर अपलोड, प्रकाशित या साझा की गई तीसरे पक्ष की जानकारी के संबंध में उत्तरदायित्व से छूट प्राप्त करने के लिए उचित सावधानी बरतें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत वे इसके लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

- **सरकार ने आनलाइन प्लेटफार्मों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों को दी सख्त चेतावनी**
- **आइटी कानून के तहत शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री हटाना अनिवार्य**

यह परामर्श यह देखने के बाद जारी किया गया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म अश्लील, अनुचित और गैरकानूनी सामग्री पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आइटी नियम, 2021 के तहत किसी व्यक्ति की ओर से अश्लीलता की शिकायत किए जाने पर इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए 24 घंटे में ऐसी सामग्री को हटाना या उस तक पहुंच निष्क्रिय करना अनिवार्य है।

जागरण विशेष

वैज्ञानिक सोच का साथ तो 'खुशबू' से महक उठे हजारों परिवार

सीएसआइआर की मदद से जम्मू-कश्मीर में छाई बैंगनी क्रांति, ग्रामीण आजीविका को मिली उड़ान

रोहित जंडियाल ● जागरण

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में किसानों के पसीने के साथ वैज्ञानिक सोच के मेल का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। इसकी खुशबू से यहां के हजारों परिवार महक रहे हैं।
लैवेंडर पुदीना परिवार की एक वनस्पति है। जिसका फूल बैंगनी कलर का होता है। इसमें सूजनरोधी और एंटी आक्सीडेंट के गुण होते हैं। इससे दवाईयां बनती हैं।
यहां एरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती किसानों के जीवन में ऐसी क्रांति लाई है कि इसकी महक पूरे देश में महसूस की जा रही है। भद्रवाह आज बैंगनी क्रांति के लिए देश की प्रेरणा बन गया है। इस क्रांति ने प्रदेश के चार हजार से अधिक किसान परिवारों का जीवन बदला है, साथ ही ग्राम विकास की नई राह भी खोली है।

किसानों के उत्साह, हौसले और मेहनत का परिणाम यह है कि औद्योगिक प्रशिक्षण के बाद वह केवल लैवेंडर के फूल ही नहीं उगा रहे पर उससे बने उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचा रहे हैं। यह किसान अब प्रति एकड़ तीन से 20 लाख रुपये सालाना कमा रहे हैं। अकेले लैवेंडर के तेल की बिक्री से भद्रवाह के किसानों ने पांच वर्ष में दस करोड़ से अधिक की आय अर्जित की है। इसके अलावा साबुन, खुशबू, अगरबत्ती और अन्य उत्पाद बना दर्जनों युवा आजीविका चला रहे हैं। लैवेंडर की खुशबू पर्यटकों को भी लुभा रही है।

सीएसआइआर के विज्ञानियों के अनुसार दस वर्ष पूर्व तक यह किसान केवल मक्का और अन्य परंपरागत फसल तक ही सीमित थे। यह क्षेत्र लैवेंडर की खेती के लिए उपयुक्त है और सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' के तहत एरोमा मिशन के लिए चुना तो संस्थान के समक्ष बड़ा कार्य था।

किसानों को खेती के लिए राजी करना, उनका प्रशिक्षण और उसके बाद अगले चरण में उन्हें स्टार्टअप की राह तक ले जाने के लिए लंबी मेहनत लगी। प्रशिक्षण के साथ किसानों को लैवेंडर के पौधे उपलब्ध कराए गए। खेती के तरीके बताकर गांव के युवाओं को मशीनें उपलब्ध कराई गईं।

खेतों में लैवेंडर के फूल चुनती महिलाएं ● जागरण

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला

सीएसआइआर के नेतृत्व वाले अरोमा मिशन को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (टीम पुरस्कार) प्रदान किया गया। यह सम्मान कृषि, ग्रामीण विकास और देश की अरोमा अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं तकनीकी योगदान के लिए दिया गया।

लैवेंडर के जरिए पर्यटन को भी मिल रहा बढ़ावा

लैवेंडर की महक से पर्यटकों को लुभाने के लिए लैवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत की गई। भद्रवाह में प्रतिवर्ष लैवेंडर महोत्सव हो रहा है और यहां काफी पर्यटकों की भागेदारी रहती है। एरोमा मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सराहना मिली है।

> एरोमा मिशन से जम्मू-कश्मीर के हजारों किसान जुड़े हैं। हमारे विज्ञानियों की टीम ने इस मिशन को किसानों की सहायता से धरातल पर सफल बनाया है। अभी तीन चरणों में इसे लागू किया गया है। इसके चौथे चरण का भी प्रस्ताव है। किसानों को एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो उन्हें और लाभ होगा।
>
> **डा. जबीर अहमद**, डायरेक्टर, सीएसआइआर-आइआइआइएम जम्मू

2015 में हुई शुरुआत: जम्मू-कश्मीर में एरोमा मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। अब इसका दायरा बढ़ा अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुल 1,625 हेक्टेयर क्षेत्र में लैवेंडर की खेती हो रही है। पहले चरण में भद्रवाह के 600 किसानों को शामिल कर 164.92 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती विकसित की गई।

दूसरे चरण में 910.71 हेक्टेयर में लैवेंडर खेती का विस्तार हुआ और करीब 2,100 नए किसान जुड़े। वर्तमान में चल रहे तीसरे चरण में 549.38 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 1,500 से अधिक किसानों को लाभ मिला है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

****

एआई सुरक्षा को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यह उत्तरी कोरिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है। -एलन मस्क

तिजोरी में अर्थव्यवस्था

यह तथ्य कि भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने का मूल्य पहली बार 450 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से भी ज्यादा है, चौंकाने वाला तो खैर है ही, यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी नीतिगत चुनौती भी पेश करता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मॉर्गन स्टेनली के एक अनुमान के अनुसार, भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है। इस आधार पर देखें, तो वैश्विक स्तर पर हाल ही में सोने की कीमतें 4,500 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंचने के साथ ही भारतीय घरों में मौजूद सोने का मूल्य देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आकार से भी बड़ा हो जाता है। ये आंकड़े, सोने के प्रति भारतीयों के सदियों पुराने सांस्कृतिक लगाव को तो दिखाते ही हैं, इसके साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं में इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देखने की प्रवृत्ति को भी उजागर करते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकारी सोने के भंडार के मामले में भारत भले ही दुनिया के शीर्ष पांच देशों में भी न आता हो, लेकिन यह भी सच है कि निजी सोने के भंडार में दुनिया का कोई भी देश भारत के आगे नहीं टिकता। लेकिन यही सफलता एक विरोधाभास भी रचती है। सोने का यह विशाल भंडार ज्यादातर निष्क्रिय है, जो उत्पादक गतिविधियों में नहीं लगा है। बैंक जमा, शेयर बाजार या उद्योगों में निवेशित धन अर्थव्यवस्था को गति देता है, नौकरियां पैदा करता है और विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन घर के लॉकरों में पड़ा सोना बेशक व्यक्ति को निजी तौर पर समृद्ध बनाता है, लेकिन इससे आयात पर निर्भरता बढ़ती है, चालू खाते का घाटा प्रभावित होता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। इन चुनौतियों के मद्देनजर ही स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को भौतिक सोने के बजाय वित्तीय सोने की ओर आकर्षित करना है। इन प्रयासों में कुछ सफलताएं मिलीं, तो सरकार को भी कुछ सीखें मिलीं। समग्र तौर पर देखें, तो सोने के कुल निजी भंडारों के अनुपात में ये प्रयास सीमित ही रहे हैं। दरअसल, नीतिगत समाधानों का रास्ता एकतरफा हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली जरूरत वित्तीय साक्षरता को गहरा बनाने की है, ताकि लोग सोने से लगाव और इसे अर्थव्यवस्था में उत्पादक रूप से उपयोग में लाने के बीच संतुलन बनाना सीख सकें। यह इसलिए भी जरूरी है, ताकि निष्क्रिय सोना देश की विकास गाथा में सक्रिय भूमिका निभा सके, अन्यथा इसकी चमक सिर्फ तिजोरियों तक सीमित रह जाएगी।

जो दिख रहा और जो नहीं दिख रहा

2026 का भारत अब सिर्फ छोटे वीडियो का बहुत बड़ा उपभोक्ता नहीं है; यह दुनिया का सबसे बड़ा रील्स, मीम्स, वॉइस नोट्स बनाने और फॉरवर्ड करने वाला देश है। जिस देश में अवसरों से अधिक प्रतिभाएं हों, वहां इस तरह की स्थिति के खतरे भी हो सकते हैं। इसलिए, एआई के दौर में सतर्कता पूर्वशर्त है।

यह सोचना मुश्किल है कि दो दशक पहले सोशल मीडिया, फेसबुक, पेटीएम या ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हम चाहे गांव में रहते हों या शहर में, इन बदलावों को अपना रहे हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी ने अभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है, जैसे हम सोशल मीडिया के आदी हुए, अब हम खुद को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में पाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक डिनर पार्टी में चालीस की उम्र के कुछ लोगों से बात कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे चैटजीपीटी या अन्य एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि वे इसके खिलाफ थे। एक महिला कलाकार ने बताया कि वह एआई का उपयोग नहीं करती है। उसे डर था कि यह सोचने को आसान बना देगा, जबकि दिमागी तौर पर सक्रिय एवं सजग रहने के लिए बौद्धिक मेहनत जरूरी है। मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या हम सब दिमागी तौर पर आलसी होने के कगार पर हैं।

अद्वैता काला
पत्रकार, फिल्म कथा लेखक एवं चर्चित उपन्यासकार

दरअसल, एआई ने पूरा खेल ही बदल दिया है। शिक्षक बताते हैं कि अब उन्हें असाइनमेंट में एआई से तैयार सामग्री को स्कैन करना पड़ता है, चोरी, नकल वगैरह पिछली सदी की बातें हो गई हैं। जैसे ही हम 2026 में कदम रखेंगे, एआई एक ऐसी चीज लगेगा, जो चुपचाप चीजों को बनाने, बात करने, अभियान चलाने, इस्तेमाल करने और यहां तक कि आरोप लगाने के तरीके को ऊर्जा देगा। वर्ष 2024 व 2025 में भारतीयों ने वायरल डीपफेक, क्लोन की हुई आवाजों, सिंथेटिक रील्स और चैटबॉट असिस्टेंट के जरिये एआई का एहसास किया था, लेकिन 2026 में एआई सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब सवाल यह नहीं होगा कि सामग्री एआई-जनरेटेड है या नहीं, बल्कि यह होगा कि 1.4 अरब लोगों, सैकड़ों भाषाओं और दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल जुड़ाव वाले देश में क्या प्रामाणिकता का अब भी महत्व है। भारत अब सिर्फ छोटे वीडियो का बड़ा उपभोक्ता नहीं है; यह दुनिया का सबसे बड़ा रील्स, मीम्स, वॉइस नोट्स बनाने और फॉरवर्ड करने वाला देश है। सिर्फ 2025 में ही, जेनरेटिव एआई टूल्स रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गए, जिनका इस्तेमाल इन्फ्लुएंसर्स ने रील्स बनाने, राजनेताओं ने ज्यादा असरदार बनने, धोखाधड़ी करने वालों ने अधिकारियों की नकल करने और आम लोगों ने ऐसी सामग्री बनाने के लिए किया, जिसे बनाने के लिए पहले उनके पास हुनर या पैसे नहीं थे।

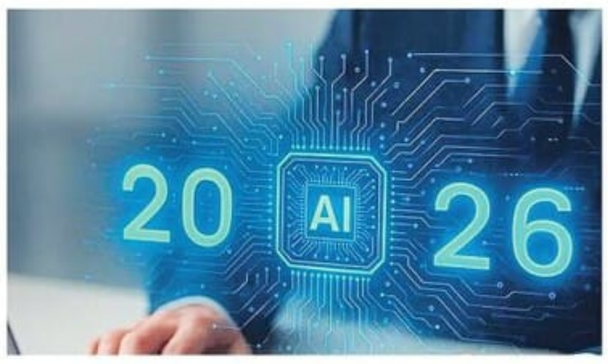

2026 तक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और नए क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली रील्स का एक बड़ा हिस्सा आंशिक या पूरी तरह से एआई की मदद से बनाया जाएगा। एआई इंदौर के एक बेडरूम क्रिएटर और मुंबई के एक स्टूडियो के बीच के अंतर को खत्म कर देगा। जैसे सोशल मीडिया ने विचारों को सबके लिए सुलभ बनाया, वैसे ही एआई रचनात्मकता के लिए भी ऐसा ही करेगा। वर्ष 2026 में, एआई भारतीय क्रिएटर्स, शिक्षकों, इतिहासकारों, फिटनेस कोच, आध्यात्मिक कहानीकारों और आंत्रप्रेन्योर्स को बड़ी टीम के बिना पेशेवर तरीके से अपने आइडिया को प्रस्तुत करने में मदद करेगा। क्षेत्रीय ज्ञान, लोक कथाएं, मंदिरों का इतिहास, खाने की स्थानीय परंपराएं, भूली-बिसरी राजनीतिक हस्तियां एआई की मदद से आख्यान और दृश्यों के माध्यम से नई जिंदगी पाएंगे। छोटे व्यवसायी स्थानीय भाषाओं में सिनेमाई अंदाज में विज्ञापन देने के लिए एआई रील्स का इस्तेमाल करेंगे। जिस देश में प्रतिभा हमेशा से अवसरों से ज्यादा रही हो, वहां यह लोकतंत्रीकरण आजादी जैसा लगेगा। लेकिन वही मशीनरी, जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, भरोसे को भी खत्म कर सकती है। भारत ने यह सबक 2025 में अच्छी तरह से सीखा, जब डीपफेक पहले परेशानी और फिर खतरा बन गया। मशहूर हस्तियों, खासकर महिलाओं को कृत्रिम सामग्री बनाकर निशाना बनाया गया। आवाज व वीडियो की नकल करके वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। वर्ष 2026 में यह सब और बढ़ सकता है। डीपफेक का मकसद हमेशा वायरल होना नहीं होगा। कई ऐसे डीपफेक होंगे, जिन्हें निजी तौर पर निशाना बनाकर और जबर्दस्ती तैयार करके उनका इस्तेमाल जबरन वसूली, उत्पीड़न, राजनीतिक धमकी या इज्जत खराब करने के लिए किया जाएगा।

भारत के संदर्भ में खतरा सिर्फ पैमाने का नहीं, बल्कि असमानता का भी है। एआई टूल्स तक पहुंच रखने वाला कोई भी गलत इरादे वाला व्यक्ति अब ऐसे किसी इन्सान को परेशान कर सकता है, जिसके पास कानूनी जानकारी, डिजिटल जागरूकता या सामाजिक ताकत नहीं है। महिलाओं, नाबालिगों और हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए यह असमानता खास तौर पर गंभीर होगी। राजनीतिक तौर पर एआई का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए पूरे चुनाव को पलटने की जरूरत नहीं है। जिस देश में राजनीतिक संदेश उसके सत्यापन से ज्यादा तेजी से फैलते हैं, वहां एआई से बने ऑडियो और वीडियो झूठे लोगों के फायदे को और बढ़ा देंगे। लोकतंत्र सिर्फ बोलने की आजादी पर ही नहीं, बल्कि भरोसे और अच्छी नीयत पर भी निर्भर करता है।

2026 तक, हो सकता है कि डीपफेक, फर्जी जानकारी और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर नियम 2025 की तुलना में ज्यादा स्पष्ट रूप में हों। हालांकि, यह सब पर एक तरह से लागू नहीं हो पाएगा। भारत की चुनौती कानून की कमी नहीं है, बल्कि इसे लागू करने का पैमाना, रोजाना लाखों अपलोड, कई ज्यूरिस्डिक्शन और विभिन्न प्लेटफॉर्म का देश के बाहर मुख्यालय हैं। ज्यादा टेकडाउन मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग टूल और पहचान की चोरी और सिंथेटिक नुकसान के बारे में कानूनी भाषा की उम्मीद करें, पर यह भी स्वीकार करें कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। नागरिकों को सतर्क रहना होगा और जो हम देखते हैं, उस पर सवाल उठाना होगा। इस बात की पूरी आशंका है कि समुदाय ऐसे क्लिप्स के आधार पर एकजुट हो जाएंगे, जो बाद में फर्जी पाए जाएंगे। जब तक सुधार होंगे, तब तक भावनात्मक नुकसान ज्यादा हो चुका होगा।

फिर भी, भारत सांस्कृतिक रूप से बदलाव को अपनाने वाले अग्रणी समाजों में से एक हो सकता है। समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा और यह पूछना शुरू करना होगा कि कोई खास क्लिप कहां से आई है, यह पूछने से पहले कि क्या वह सच है। इस लिहाज से, 2026 'देखना ही विश्वास करना है' के अंत और 'पता लगाना ही विश्वास करना है' की शुरुआत का साल हो सकता है। और, हमें वहां तक तेजी से पहुंचना होगा।

edit@amarujala.com

मुद्दा

यह आगे बढ़ने का समय है

पीछे मुड़कर देखें, तो युद्धों व अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक व्यापार में कुछ अनिश्चितता जरूर पैदा हुई है, पर यह आगे बढ़ने का समय है और दुनिया के देश यह समझ भी रहे हैं।

वैश्विक व्यापार में बदलाव आ रहा है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के दौर में अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए जो मॉडल बना था, वह अनिश्चित नीति, अविश्वसनीय आधारभूत ढांचे और दुर्लभ मृदा खनिजों जैसी संवेदनशील चीजों की बढ़ती मांग से बदल रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद से मजदूरों की कमी, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीति ने भी दुनिया भर में वस्तुओं की आवाजाही पर असर डाला है। इसने बंदरगाहों के कामकाज, शिपिंग कंटेनरों की स्थिति और व्यापार विस्तार की योजनाओं को भी प्रभावित किया है। कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से पैदा हुए व्यापार युद्ध के मौजूदा दौर को प्रबंधित करने के तरीके ढूंढ रही हैं, तो क्या वैश्विक आपूर्ति शृंखला हमेशा के लिए टूट गई है?

येल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एलेह त्सिविंस्की कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार, मूल्य के हिसाब से दुनिया का लगभग 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, और इसका लगभग दो-तिहाई हिस्सा कंटेनरों में होता है। कंटेनरों को समझना मतलब वैश्विक व्यापार की संरचना को समझना है। त्सिविंस्की कहते हैं कि मैंने अन्य प्रोफेसरों के साथ मिलकर आपूर्ति शृंखला में बाधा का सूचकांक तैयार किया, जो उत्पाद, कंपनी और क्षेत्रीय स्तर पर बाधाओं का पता लगाता है। नतीजों से पता चला कि कोविड के दौरान आपूर्ति में रुकावटें अपने चरम पर थीं, लेकिन तब से कुल मिलाकर कम हो गई हैं, हालांकि वे महामारी से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। जब हम जरूरी सामान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो तस्वीर और भी खराब हो जाती है। दुर्लभ धातुओं जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके, हमने महत्वपूर्ण आपूर्ति बाधाओं का ब्लू सेंटर इंडेक्स बनाया। यह इंडेक्स दिखाता है कि जहां आम आपूर्ति शृंखला झटकों से जल्दी ठीक हो जाती हैं, वहीं जरूरी आपूर्ति शृंखला पर ज्यादा गंभीर असर पड़ता है और उन्हें स्थिर होने में काफी समय लगता है। आज वैश्वीकरण की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने पाया कि अमेरिका की मनमानी टैरिफ नीति के चलते वैश्वीकरण का स्वरूप बदल रहा है। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें खासकर बड़े झटकों के समय, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला आर्थिक सुरक्षा को परिभाषित करेंगी, न कि उपभोक्ता वस्तुएं। सरकारों और व्यवसायों के लिए चुनौती अब आपूर्ति शृंखला को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय जरूरी वस्तुओं के प्रवाह को सुरक्षित रखने की होगी।

रिचर्ड बोर्गे

ग्लोबल शिपिंग एसोसिएशन बीआईएमसीओ की पूर्व अध्यक्ष सबरीना चाओ कहती हैं कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, इस साल टैरिफ और व्यापार नीति में बढ़ती अनिश्चितता के कारण दुनिया भर के निर्यात में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप में अब भी युद्ध जारी है और लाल सागर इलाके में व्यावसायिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं। जब अमेरिका जैसा देश वैश्विक व्यापार सिद्धांतों को चुनौती देता है और ब्रेटन वुड्स सिस्टम जैसे समझौतों व डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों के इरादे कमजोर होते हैं, तो वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। पर कभी-कभी आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़कर देखना भी लाभप्रद होता है। इस संदर्भ में, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के बीच 2025 में हुए क्षेत्रीय समझौते महत्वपूर्ण हैं, जो दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने के साथ वैश्विक व्यापार को भी एक नया रूप दे रहे हैं। ऐसे में, वैश्विक व्यापार जिस अनिश्चितता से जूझ रहा है, वह ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं।

©The New York Times 2025

नया साल एक नई और साफ शुरुआत की तरह है। यह बिल्कुल ऐसा है, जैसे ड्राइंग बनाने के लिए एक बड़ी सफेद कागज की शीट मिल गई हो। -बिल वॉटर्सन

अंत ही शुरुआत है

जीवन धारा

हर सूर्योदय आपके लिए नया अध्याय लिखने का निमंत्रण है। इस जोश के साथ शुरुआत करें कि गलतियां, अफसोस और बाधाएं नए अवसरों को रोक न पाएं।

जीवन कई बार हमें ऊंच-नीच, विफलता, कठिनाइयां और मानो अंत-सा अनुभव कराता है। ऐसे में अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या असफलताओं के बाद जीवन फिर से शुरू हो सकता है? दरअसल, जिसे हम शुरुआत कहते हैं, वह अक्सर अंत होता है, और अंत करना ही एक नई शुरुआत करना है। यही अंत वह स्थान है, जहां से हम फिर शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अनुभव-चाहे वह कठिनाई, विफलता या दिल टूटने का क्षण हो-आखिरकार एक अंत की तरह प्रतीत होता है, लेकिन असल में वह नई सीख और आगे बढ़ने का अवसर भी है। अंत तब तक पूरा नहीं होता, जब तक हम सीखना और उसे अपनाना नहीं सीख लेते। इसलिए डरने के बजाय अंत को ही शुरुआत बनाएं।

टी एस एलियट

हर सूर्योदय आपके लिए नया अध्याय लिखने का निमंत्रण है। इस जोश से शुरुआत करें कि पुरानी गलतियां, अफसोस और बाधाएं नए अवसरों को रोक न पाएं। नई शुरुआत पुरानी जड़ों से जुड़कर ही सार्थक होती है। हर चुनौती के बाद आने वाला अगला क्षण आपके हाथ में एक नई शुरुआत की चाबी देता है। जब आप स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हैं कि हर पल आपको नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है, तो जीवन की निराशा कम होती है और उत्साह बढ़ता है। आप हर सुबह अपने भीतर के डर को हराकर आगे बढ़ सकते हैं। पिछले साल के शब्द पिछले साल की भाषा का हिस्सा हैं, और अगले साल के शब्द किसी नई आवाज का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भूतकाल को उसी में रहने दें, और भविष्य के लिए अपनी आवाज खुद बनाएं। नई आवाज, नई सोच और नई आशा ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है।

नई शुरुआत आपको आत्मविश्वास देती है। यह याद दिलाती है कि गलतियां स्थायी नहीं हैं। यह आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, यह समझाती है कि अंत भी एक शुरुआत है, बस उसे पहचानने का नजरिया चाहिए।

वह जो नए साल में भी नहीं बदलेगा

नए साल में ट्रेंड बदलेंगे, तकनीक बदलेगी, पर ग्राहकों की सस्ते और भरोसेमंद अनुभव की चाह कभी नहीं बदलेगी।

नए साल में तो हम वादों की झड़ी लगा देते हैं और फिर कुछ भूलते, कुछ याद करते, कुछ दोहराते, फिर अपनी कुछ और आदतें बदलने की आशा रखते हुए दिनों को बिताते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई यह प्रश्न करे कि आने वाले दस वर्षों में ऐसा क्या है, जो नहीं बदलेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? यह प्रश्न थोड़ा अटपटा तो जरूर है, क्योंकि हम जिस अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और संदिग्ध, यानी वूका वाली दुनिया में रहते हैं, वहां तो सिर्फ बदलाव और उसको अपनाने की ही बातें होती रहती हैं। लेकिन यह सोचना कि आने वाले कई वर्षों तक क्या नहीं बदलेगा, अपने आप में कुछ सजग और सचेत करने वाला सवाल जरूर है।

नन्दितेश निलय
एल्युमनस आईआईटी, दिल्ली
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

कुछ ऐसी ही चर्चा जेफ बेजोस ने की, जब वह अमेजन की एक कॉन्फ्रेंस में बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते समय भविष्य के ट्रेंड्स के बजाय ग्राहकों की स्थायी इच्छाओं पर ध्यान देने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, 'मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अगले दस वर्षों में क्या बदलने वाला है? यह बहुत ही दिलचस्प, लेकिन आम सवाल है। लेकिन मुझसे कभी यह नहीं पूछा जाता कि अगले दस वर्षों में क्या नहीं बदलने वाला है? दूसरा सवाल असल में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उन चीजों के आसपास बिजनेस स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जो समय के साथ बनी रहती हैं...खुदरा व्यवसाय में, ग्राहक कम कीमतें चाहेंगे, उन्हें तेज डिलीवरी और बहुत सारे उत्पादों के प्रकार चाहिए होंगे। आज से दस साल बाद भी यही सच रहेगा।' फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न बदलने वाली बुनियादी चीजों में वस्तुओं की कम कीमतें, तेज डिलीवरी, और ग्राहक को चुनाव के अवसर देने होंगे और ये कभी नहीं बदलेंगे। इस दृष्टिकोण ने अमेजन की प्राथमिकता को दिशा दी और लॉजिस्टिक्स इनोवेशन से लेकर प्राइसिंग एल्गोरिदम तक, और एआई एवं ई-कॉमर्स में तकनीकी हस्तक्षेप के बावजूद यह सही साबित हुआ। बेजोस का कहना है कि इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है और यों ही बदलावों के पीछे भागना जोखिमपूर्ण भी है। उनका तरीका अपनी दीर्घकालीन व्यवसाय रणनीति में एक जैसे नैतिक ढांचे को शामिल करना है, जो उन चीजों पर फोकस करने के सिद्धांत पर आधारित हो और जो अगले दस साल में नहीं बदलेंगी। अमेजन के लिए, इसका मतलब ग्राहकों पर ध्यान देना है, जिसे जेफ व्यवसाय का सबसे बड़ा, टिकाऊ नैतिक आधार मानते हैं।

क्या आपने कभी सोचा था कि समाज में कमजोर पड़ते भरोसे के मूल्य की रक्षा बाजार करने आएगा और यह वर्क एथिक्स आने वाले कई साल तक यथावत रहेगा? जिस समाज में सब कुछ 'रिवैलिडेट' किया जाता है, वहां बाजार ग्राहक के व्यवहार और फैसले को 'रिवैलिडेट' नहीं करेगा और सिर्फ उसको समान लौटाने की ही सुविधा नहीं देगा, बल्कि इस पर भी यकीन करेगा कि उस सामान को प्रयोग में नहीं लाया गया है। यही भरोसा बाजार व ग्राहक के बीच सेतु बनेगा, जो जेफ बेजोस के अनुसार, आने वाले वर्षों में कभी नहीं बदलेगा। और नहीं बदलेंगे उन असंख्य लोगों के सपने, जो अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद कुछ खरीदना चाहेंगे, जो किफायती होने के साथ टिकाऊ भी हों। यह भाव, यह अभिलाषा, एक न खत्म होने वाली आकांक्षा की तरह कभी नहीं बदलेगी। बाजार अपने ग्राहकों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के फोन की एक क्लिक पर यकीन दिलाएगा कि वह ग्राहक कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वही साधन है और साध्य भी। जो भी वस्तु ग्राहक खरीदना चाहता है, बाजार बगैर गुणवत्ता में कोई समझौता किए, उसे सस्ते में ही बेचेगा। यह भी नहीं बदलेगा। सामाजिक भरोसे के धागों को उलझाते-सुलझाते बाजार में मुस्तैद अमेजन की तरह तमाम कंपनियां उस भरोसे को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाना चाहेंगी।

जेफ बेजोस ने यह भी माना कि यह सोचना असंभव होगा कि सबसे बड़ी जनसंख्या महंगी चीजें खरीदेगी। उनकी कंपनी या बाजार की तमाम कंपनियों को ग्राहक को उसकी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार ही सामान बेचना होगा। सभी को सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे जल्दी व सबसे सस्ता। और ग्राहक को यकीन भी है कि लगातार खरीदी गई वस्तुएं लौटाने के बावजूद कंपनी का भरोसा यथावत बना रहेगा। आज से दस साल बाद, बेजोस शायद एथिक्स की जरूरत को पहले से कहीं ज्यादा जरूरी मानेंगे। कंपनी की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह अपनी रणनीति में स्थिर एथिकल सिद्धांतों को कितने असरदार तरीके से शामिल करती है। चुनौती एथिक्स के महत्व में बदलाव की नहीं होगी, बल्कि तेजी से बदलते तकनीकी माहौल में, आगे की सोच वाले नैतिक नवाचारों की होगी।

आखिर यह समय उत्पाद का नहीं, बल्कि उससे जुड़े ग्राहकों के अनुभव का है, वस्तु की कीमत का नहीं, बल्कि उससे जुड़े मूल्य का है। नहीं तो बाजार मनुष्य के उन धार्मिक सद्भावों को भला कैसे समझ पाता और कैसे 'स्पिरिचुअल कॉमर्स' का एक नया प्लेटफॉर्म बनकर खड़ा हो जाता, जहां त्योहार के मौसम, या नए साल में पूजा की सामग्री या प्रसाद घर पहुंच जाता है, जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। बाजार उस पल्स को समझता है और उसे मालूम है कि 'स्पिरिचुअल कॉमर्स' सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि वह जुड़ाव है, जो बाजार और ग्राहक के बीच एक आत्मिक संबंध बनाता है, जो कभी नहीं बदलेगा। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों के लिए बाजार सिर्फ सस्ता, तेज डिलीवरी, और भरोसे का ही प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ग्राहक के उस स्पिरिचुअल मन का संवेदनशील श्रोता भी है, जो 'कस्टमर इज गॉड' को पुनः परिभाषित करना चाह रहा है।

और अंत में, क्या जेफ मनुष्य को बाजार से इतर कर यह भी कहना चाहेंगे कि आने वाले दस साल में नहीं बदलेगा, उस एम्पैथी की मानवीय चाह, वह त्योहारी मौसम में बाजार से अपने शहर, अपने घर लौटने की उद्विग्नता, और वह भरोसा, जो वर्चुअल से ज्यादा रियल होगा, और वह मन, जो प्यार या डांट से दी हुई सलाह को लौटाएगा नहीं, सुनेगा, समझेगा और साथ रहने की संभावनाएं तलाशेगा।

क्या 2026 में अपने सेपियंस के उस बुद्धिमान मनुष्य को हर व्यक्ति बचाना चाहेगा? अगर ऐसा है, तो फिर अपनी नैतिकता, मूल्यों और गुणों को बचा कर रखना भी उस बदलाव का ही हिस्सा होगा, जो बदलाव से ज्यादा विकसित होने की कहानी लिखेगा।

मेरी आवाज सुनो...

फुटपाथ बना शौचालय

पूर्वी दिल्ली स्थित शास्त्री पार्क रेलवे पुल के पास बना फुटपाथ शौचालय बन गया है। आसपास शौचालय नहीं होने की वजह से राहगीर यहीं फुटपाथ पर पेशाब कर देते हैं, जिसकी वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां से गुजरने पर दुर्गंध आती है। फुटपाथ पर पेशाब का कतरा होने की वजह से राहगीर इस पर चल नहीं पाते हैं।

- सलीम, शास्त्री पार्क निवासी।

आप भी भेज सकते हैं अपने क्षेत्र की ऐसी किसी समस्या की जानकारी जो लोकहित से जुड़ी हो और जिसकी सुनवाई न हो रही हो।

जानकारी साझा करें

del-cityincharge@del.amarujala.com

न्यूज डायरी

कैंसर स्क्रीनिंग के लिए लगा शिविर

नई दिल्ली। खेड़ा डाबर स्थित चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में एक दिवसीय निशुल्क कैंसर जागरूकता एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के सहयोग से लगा। 80 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुमेर सिंह ने कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संवाद

कुत्तों की गिनती कराने पर किया कटाक्ष

नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लावारिश कुत्तों की गिनती और निगरानी में लगाए जाने के कथित आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि यह आदेश शिक्षा के प्रति भाजपा सरकार की सोच और प्राथमिकताओं को उजागर करता है और इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे। भाजपा की दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। संवाद

बजट में सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास पर होगा जोर

नई दिल्ली। एमसीडी के आगामी 2026-27 बजट की रूपरेखा अब जमीनी जरूरतों के अनुरूप तय होगी। स्थायी समिति की विशेष बैठक में छह प्रमुख समितियों के अध्यक्षों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बजट सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया गया है।

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि सभी समितियों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए एक समग्र, संतुलित और जनहितकारी बजट तैयार होगा, जिसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरियाली और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देंगे। पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए हर वार्ड में जेसीबी और स्वीपिंग मशीन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

सत्या शर्मा ने कहा समितियों के सुझावों से तय की जाएंगी प्राथमिकताएं

उन्होंने प्रत्येक निगम पार्षद को अलग से 10 सफाई कर्मचारी देने, डलावघरों और सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए अलग बजट का प्रस्ताव रखा। ब्यूरो

यूईआर-2 एक्सटेंशन से राजधानी में जाम, प्रदूषण से राहत

पांच माह बाद शुरू होगा राजधानी के बाहरी इलाके को नई रफ्तार देने का काम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को कम करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाने की तैयारी है। अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) के एक्सटेंशन की परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग तैयार हो चुकी है। दिल्ली के हिस्से का रूट भी तय कर लिया गया है।

महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर और कई अन्य

सांकेतिक

राज्यों के वाहन चालकों को सीधा लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में यूईआर-2 को सितंबर में अलीपुर से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) तक शुरू किया गया था। अब इसके विस्तार के तहत इसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) लगभग 17 किलोमीटर लंबा नया मार्ग तैयार करेगा।

इस मार्ग के बन जाने से न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम, एयरपोर्ट, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आवाजाही करने वाले वाहनों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली देहात विकास मंच के चेयरमैन भूपेंद्र बाजाड़ ने कहा कि यूईआर-2 के एक्स्टेंशन का काम एनएचएआई की तरफ से तेजी से शुरू करने का काम किया रहा है। पांच माह बाद निर्माण संबंधी गतिविधियां भी शुरू होंगी।

बता दें कि यूईआर-2 को दो बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इस योजना के तहत 20 किलोमीटर और 17 किलोमीटर लंबी दो सड़कों का निर्माण होगा। इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर जाने वाले वाहन चालकों को दिल्ली के बीचोंबीच घुसने की आवश्यकता नहीं होगी।

- यूईआर-दो को अलीपुर के पास सेसे शुरू होकर 17 किलोमीटर लंबी सड़क बाहरी दिल्ली के हिरनकी होते हुए गाजियाबाद के मंडोला और ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।
- इसके बनने से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम और हरियाणा-राजस्थान से आने-जाने वाले वाहनों को सीधा फायदा होगा।
- राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के वाहनों देहरादून या उत्तराखंड जाने के लिए दिल्ली के अंदर होकर नहीं जाना पड़ेगा।

कानून को सरल बनाने वाला बड़ा कदम, छोटे उल्लंघन अपराध नहीं

प्रदेश सरकार ने जन विश्वास विधेयक को दी मंजूरी, अदालतों पर बोझ होगा कम

अमर उजाला ब्यूरो

विधेयक दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा

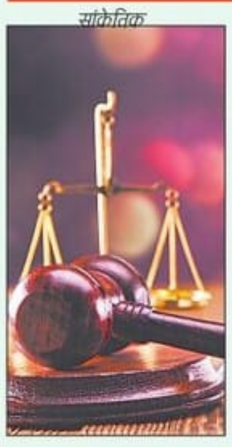

सांकेतिक

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिन अधिनियमों को इस विधेयक के दायरे में लाया गया है, वे निम्नलिखित हैं:-

- दिल्ली औद्योगिक विकास, संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम, 2010
- दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 'इन्क्रेडिबल इंडिया' बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007
- दिल्ली कृषि उपज विपणन (नियमन) अधिनियम, 1998
- दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998
- दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय/संस्थान अधिनियम, 2007
- दिल्ली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2007
- इन सभी अधिनियमों में छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर नागरिक दंड में बदलने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने छोटे अपराधों और तकनीकी उल्लंघनों से मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कानून को सरल बनाना, अनुपालन प्रक्रियाओं को सहज करना और आम नागरिकों व कारोबारियों के जीवन को आसान बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक लागू होने से छोटे उल्लंघन अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और प्रशासनिक प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विश्वास पहल से प्रेरित है। केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2023/2025 के तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराधों को अपराधमुक्त किया था। इसी तर्ज पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को भी अपने कानूनों की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी। दिल्ली सरकार ने व्यापक समीक्षा के बाद पाया कि कई मामलों में आपराधिक सजा के बजाय नागरिक दंड अधिक व्यावहारिक और प्रभावी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। इससे छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में आपराधिक मुकदमों की जगह नागरिक दंड, प्रशासनिक जुर्माना और अपील की व्यवस्था लागू होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन से जुड़े मामलों में कठोर प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।

इस विधेयक के तहत दिल्ली औद्योगिक विकास, संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम, 2010, दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954, दिल्ली कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1998, दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 सहित कुल सात अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। इन कानूनों में छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर नागरिक दंड में बदला जाएगा।

जुर्माने की राशि में हर तीन साल स्वतः 10 प्रतिशत होगी वृद्धि : विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की राशि में हर तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि होगी ताकि मुद्रास्फीति के अनुरूप दंड प्रभावी बना रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और इसे मौजूदा संसाधनों से ही लागू किया जाएगा। यह विधेयक दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

सड़क निर्माण और मिस्ट स्प्रे से प्रदूषण पर लगाम की तैयारी

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, वायु प्रदूषण से निपटने को कदम उठा रही सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

हॉटस्पॉट्स पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री के अनुसार मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उपयोग उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों और चिन्हित हॉटस्पॉट्स में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। यह व्यवस्था मानसून को छोड़कर पूरे वर्ष संचालित रहेगी। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह उपाय व्यावहारिक, किफायती और प्रभावी साबित हो रहा है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर ठोस और दीर्घकालीन कदम उठा रही है। जर्जर सड़कों और उड़ती धूल पर अब निर्णायक प्रहार किया जाएगा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) हटते ही लगभग 400 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण को भी नई गति मिलेगी।

सीएम ने बताया कि इन सड़कों का निर्माण वॉल-टू-वॉल तकनीक से होगा, ताकि सड़क किनारों से धूल उड़ने की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण टूटी-फूटी सड़कों से उठने वाली धूल है, जिसे बेहतर और मजबूत सड़कों के जरिए काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

केंद्र और दिल्ली सरकार की साझा पहल : दिल्ली सरकार के अनुसार प्रस्तावित 400 किलोमीटर सड़कों में से 300 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पहले ही बजट जारी कर चुकी है, जबकि शेष 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से करेगी।

ग्रेप हटते ही युद्धस्तर पर होगा काम : मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सड़क निर्माण से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया और अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। ग्रेप हटते ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ काम शुरू करेगा।

जिन सड़कों का निर्माण पांच वर्ष पूर्व हुआ था या जिनकी स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्मित किया जाएगा।

मिस्ट स्प्रे सिस्टम से धूल पर नियंत्रण : सड़क निर्माण के साथ-साथ दिल्ली सरकार मिस्ट स्प्रे सिस्टम के विस्तार पर भी जोर दे रही है। सीएम ने कहा कि धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह प्रणाली बेहद प्रभावी है। पर्यावरण विभाग के निर्देशों के तहत सड़कों के सेंट्रल वर्ज (मध्य विभाजक) पर स्थित बिजली के खंभों या अन्य उपयुक्त संरचनाओं पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इन प्रणालियों के जरिए सूक्ष्म जल कणों का छिड़काव कर सड़क की धूल को दबाया जाता है, जिससे पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे खतरनाक प्रदूषकों में कमी आती है।

दीर्घकालीन समाधान पर सरकार का जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटना केवल मौसमी या तात्कालिक कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए बेहतर सड़कें, नियमित रखरखाव और आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर जीवन वातावरण उपलब्ध कराना है।

केंद्रीय मंत्री ने 'जल सेवा आकलन' का ई-लॉन्च किया

जल जीवन मिशन का उद्देश्य अब केवल नए संसाधन बनाने तक सीमित नहीं

संवाद न्यूज एजेंसी

जल सेवा आंकलन उपकरण पर प्रशिक्षण सत्र

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक केके मीना ने कहा कि जल सेवा आंकलन एक संरचित, समुदाय-नेतृत्व वाली स्व-समीक्षा प्रक्रिया है। इसके तहत गांव अपनी पाइपलाइन और जल आपूर्ति प्रणाली की कार्यक्षमता का आंकलन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक कमल किशोर सोआन ने बताया कि मूल्यांकन की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। कार्यक्रम का समापन संयुक्त सचिव स्वाति मीना नाइक के धन्यवाद ज्ञापन और उप सचिव अंकिता चक्रवर्ती द्वारा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जल सेवा आंकलन उपकरण पर प्रशिक्षण सत्र के साथ हुआ।

नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को जल जीवन मिशन (जेजेएम) पोर्टल पर डिजिटल पेयजल सेवा मूल्यांकन उपकरण जल सेवा आंकलन का ई-लॉन्च किया। यह टूल ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में संचालित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थिरता का आकलन करेगा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य अब केवल नए संसाधन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर को विश्वसनीय और सुरक्षित पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराना भी है।

'जल सेवा आकलन' के माध्यम से ग्राम पंचायतों और ग्रामीण संस्थानों को अपनी जल आपूर्ति प्रणालियों का स्व-मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पाटिल ने बताया कि नया टूल गांवों को अपनी जल आपूर्ति प्रणाली का संरक्षक बनने का अधिकार देता है और ग्राम सभाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है।

कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और संस्थानों के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, सरपंच और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य शामिल थे। लगभग 10,000 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और झूठ की राजनीति पर प्रहार : दिल्ली सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट व प्रदूषण पर होगी खुली बहस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद व कपिल मिश्रा ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप झूठ की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। मंत्रियों ने साफ किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद ने दिल्ली विधानसभा का सत्र पांच जनवरी से चार दिनों के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। इस सत्र में सरकार कई प्रस्ताव लेकर आएगी।

कपिल मिश्रा ने कहा कि विधानसभा सत्र में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा होगी। सरकार स्वयं पर्यावरण और प्रदूषण पर प्रस्ताव लाएगी, जिसमें पिछले 20 वर्षों की स्थिति, वैज्ञानिक रिपोर्टें, अब तक की कमियां और भविष्य की कार्ययोजना सदन के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चर्चा में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके साथ ही शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा व विश्वविद्यालयों के संचालन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी कैग रिपोर्टें भी विधानसभा सत्र में पेश की जाएंगी। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर सोशल मीडिया के जरिए झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप ने संगठित अभियान चलाकर शिक्षकों को लावारिया कुत्तों की गिनती के काम में लगाने का झूठ फैलाया है।

10 माह उपलब्धियों से भरे : भाजपा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के 10 माह के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताते हुए आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को ठप हालत में छोड़ गई थी, लेकिन भाजपा ने मात्र 10 माह में राजधानी को फिर से विकास की राह पर ला खड़ा किया है। हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो

स्पष्टीकरण के बाद भी भ्रामक बयान देना शर्मनाक : सचदेवा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षकों को कुत्तों की गिनती की ड्यूटी पर लगा रही है। सचदेवा ने इसे बेहद शर्मनाक, भ्रामक और दिल्लीवासियों को गुमराह करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सचदेवा ने कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और नगर निगम की ओर से स्पष्ट रूप से यह कहा जा चुका है। उन्होंने कहा है कि न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है और न ही सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के इस झूठे दावे को दोहराना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भी है।

शीतकालीन सत्र में सरकार की खामियां उजागर करेगी आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने पांच जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा सरकार के 10 महीने के कार्यकाल की नाकामियों को जोर-शोर से उठाने का ऐलान किया है।

आप विधायक दल के चीफ व्हीप संजीव झा ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा सरकार से हर मोर्चे पर जवाब मांगा जाएगा।

संजीव झा ने कहा, 10 महीनों का मांगेंगे हिसाब

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन 10 महीने बीतने के बाद भी जनता को कोई ठोस राहत नहीं मिली।

संजीव झा के अनुसार, भाजपा सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने अपने 10 महीनों के कार्यकाल में दिल्ली की जनता के हित में आखिर क्या किया।

भाजपा पर नाकामियों से बचने का आरोप

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर आगामी विधानसभा सत्र को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की भेंट चढ़ाकर अपनी नाकामियों से बचने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक बार फिर जनता से जुड़े असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया और कई घोटाले किए, लेकिन भाजपा सरकार को भी यह जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 महीनों में उसने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। उन्होंने सवाल उठाया कि दमघोंटू प्रदूषण, यमुना की सफाई, डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल और जर्जर सड़कों की हालत सुधारने को लेकर भाजपा सरकार क्यों पूरी तरह विफल रही। ब्यूरो

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए आरोप

लोकनायक अस्पताल ने 500 बच्चों की सर्जरी कर दिया नया जीवन

अमर उजाला ब्यूरो

पीडियाट्रिक सर्जरी सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि जिंदगी सुरक्षित रखने का है विषय

नई दिल्ली। लोकनायक अस्पताल में एक साल में रिकॉर्ड 500 से अधिक बच्चों की सर्जरी कर उन्हें नया जीवन दिया है। यह बच्चे जन्मजात शारीरिक विकृतियों की बीमारियों से जूझ रहे थे। जिसमें नवजात से लेकर बच्चे शामिल थे। इसमें कई बच्चों की दुर्लभ सर्जरी कर उनकी जान बचाई गई। नवजात और बच्चों की सर्जरी के संबंध में पीडियाट्रिक सर्जरी डे के उपलक्ष्य में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध लोकनायक अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की अध्यक्ष डॉ. सिम्मी के. रतन ने किया। अंडरग्रेजुएट छात्रों को पीडियाट्रिक सर्जरी से परिचित और उनका मार्गदर्शन किया गया।

लोकनायक अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन। स्रोत : विभाग

विधानसभा अध्यक्ष ने सीआरपीएफ के जवानों से किया संवाद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 103वीं बटालियन के जवानों और अधिकारियों से संवाद किया और देश की आंतरिक सुरक्षा में उनकी अहम भूमिका की सराहना की।

इसमें सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनके परिवारजन और बच्चे भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा हालात में कार्य करते हुए सीआरपीएफ के जवान साहस, अनुशासन और अडिग पेशेवर प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है और लोकतंत्र, शांति तथा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में इसकी भूमिका अतुलनीय है।

उन्होंने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों, वामपंथी उग्रवाद से निपटने, चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन को दी गई सहायता में सीआरपीएफ के योगदान को विस्तार से रेखांकित किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सीआरपीएफ की भागीदारी का उल्लेख करते हुए वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया।

चिंताजनक

जर्नल ऑफ मिड-लाइफ हेल्थ में प्रकाशित शोध में हुआ खुलासा

काम के बोझ तले डॉक्टर, खुद जूझ रहे गंभीर बीमारियों से

अमर उजाला ब्यूरो

48 प्रतिशत चिकित्सक उच्च रक्तचाप से पीड़ित, शोध के नतीजों से चला पता

23 प्रतिशत को डायबिटीज, 14% को हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याएं

नई दिल्ली। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सेहत सुधारने में दिन-रात जुटे डॉक्टर आज खुद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी, बढ़ती जिम्मेदारियां, नाइट शिफ्ट और मानसिक तनाव ने उनकी जीवनशैली को इस कदर प्रभावित किया है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य बीमारियों की चपेट में आ गए हैं।

यह खुलासा जर्नल ऑफ मिड-लाइफ हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया शोध में हुआ है, जिसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। शोध में दिल्ली समेत देश के सात राज्यों के 265 चिकित्सकों को शामिल किया गया। अध्ययन 2025 में ऑनलाइन माध्यम से चार महीनों तक हुआ। इसमें डॉक्टरों की दिनचर्या, काम का दबाव और स्वास्थ्य मानकों का विश्लेषण हुआ। शोध का नेतृत्व एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने किया, जबकि कोलकाता और झारखंड के चिकित्सा संस्थानों ने भी इसमें सहयोग दिया।

इलाज करने वालों को ही घेर रहीं बीमारियां

शोध के नतीजों के अनुसार, 48% चिकित्सक हाई ब्लडप्रेशर से पीड़ित मिले। 23% को डायबिटीज और करीब 14% को हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड व हृदय रोग जैसी समस्याएं थीं। कुछ डॉक्टरों में मोटापा और धूम्रपान की आदत भी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार, यह आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि ये मरीजों के नहीं बल्कि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों के हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यदि डॉक्टरों के काम के घंटे, मानसिक तनाव और वर्क-लाइफ बैलेंस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

सांकेतिक

क्रेडिट स्कोर और यूपीआई से लेकर पैन कार्ड तक, कल से होंगे ये जरूरी बदलाव

2025 के समापन के साथ ही कल से नए साल यानी 2026 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में वित्तीय मोर्चे पर कई तरह के बदलाव होंगे, जो आपके लिए जरूरी हैं। इनमें क्रेडिट स्कोर से लेकर पैन कार्ड को लिंक करने और यूपीआई से लेकर टैक्स तक के मामले शामिल हैं। ये सभी आपके वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपने समय रहते बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, तो जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपकी वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ब्यूरो

क्रेडिट स्कोर : अब हर सप्ताह होगा अपडेट

क्रेडिट ब्यूरो को अब तक हर 15 दिन में ग्राहकों का डाटा अपडेट करना होता था, लेकिन एक जनवरी, 2026 से इसे साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि लोन चुकाने, डिफॉल्ट करने या भुगतान व्यवहार में सुधार क्रेडिट स्कोर में तुरंत दिखाई देगा। वहीं, समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा। इससे लोन पात्रता और ब्याज दरों पर सीधा असर पड़ेगा।

पैन-आधार लिंक

अधिकांश बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो एक जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपके बैंक खाते प्रतिबंधित किए जा सकते हैं या सेवाएं देने से इन्कार किया जा सकता है। टैक्स रिफंड अटकने, बैंक खाता खोलने और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने में दिक्कत आ सकती है।

यूपीआई : डिजिटल भुगतान पर अब सख्त नियम

डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक जनवरी से डिजिटल लेनदेन के नियम सख्त हो रहे हैं। ज्यादा सख्त केवाईसी नियमों का पालन करना होगा। डिजिटल भुगतान पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बैंकों ने यूपीआई लेनदेन पर जांच को मजबूत करने का फैसला किया है। धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए वॉट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप के लिए सिम सत्यापन मानदंडों को अधिक सख्त बनाया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी खुशखबरी लेकर आ सकता है।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। इससे वेतन संरचना में संशोधन होने की संभावना है। जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। इससे महंगाई से कुछ हद तक बचाव होगा।

होम लोन : सस्ता होने की उम्मीद, घट सकती है किस्त

आरबीआई ने दिसंबर में रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। कुछ बैंकों ने इस फैसले का तुरंत ग्राहकों को फायदा दे दिया। हालांकि, कई बैंकों ने अब भी इसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। ऐसे में नए साल से कुछ ग्राहकों को फायदा मिल सकता है और उनके होम लोन की किस्त घट सकती है।

■ *मिलेगा नया रिटर्न फॉर्म : करदाताओं को जनवरी में एक नया आयकर रिटर्न फॉर्म मिलने की उम्मीद है। यह फॉर्म संभवतः बैंकिंग लेनदेन और खर्च के विवरण से पहले से भरा होगा। इससे फाइलिंग आसान हो जाएगी, लेकिन जांच भी बढ़ेगी और त्रुटियों या चूक की गुंजाइश कम हो जाएगी।*

आईटीआर भरने का आज आखिरी मौका

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। जो करदाता अब तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं, वे 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न (बिलेटेड रिटर्न) दाखिल कर सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न नहीं भरते हैं, तो टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने के लिए अपडेटेड रिटर्न का सहारा लेना होगा, जिसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

वीई कमर्शियल को मिला 192.3 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस

नई दिल्ली। आयशर मोटर्स की अनुषंगी कंपनी वीई कमर्शियल व्हीकल्स लि. को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए क्रेडिट नोटस जानकारी देने में देरी से जुड़े मामले में जुर्माने के साथ 192.36 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस मिला है।

आयशर मोटर्स ने मंगलवार को बताया कि वीई कमर्शियल व्हीकल्स लि. को मध्य प्रदेश के उज्जैन आयुक्त कार्यालय के सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से इस साल जुलाई में कारण बताओ नोटिस मिला था। इसमें 168.19 करोड़ की जीएसटी राशि और इतनी ही रकम का जुर्माना लगाया गया था। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद कंपनी को 29 दिसंबर, 2025 को कर मांग नोटिस मिला। इसमें 96.18 करोड़ की कर मांग और इतनी ही जुर्माना राशि एवं ब्याज शामिल है। कंपनी ने कहा, इस नोटिस से कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एजेंसी

एस्कॉर्ट्स कुबोटा को भी 3.40 करोड़ का नोटिस

कृषि एवं निर्माण उपकरण बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लि. को महाराष्ट्र के कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता से जुड़े एक मामले में 3.4 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग का नोटिस मिला है। इसमें 1,76,29,853 रुपये का कर मांग नोटिस है। इसके अलावा, 1,46,58,378 रुपये का ब्याज और 17,62,985 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह नोटिस 29 दिसंबर, 2025 को मिला। कंपनी ने कहा, वह इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।

न्यूज डायरी

50,000 टन ऑर्गेनिक चीनी निर्यात की मंजूरी

मुंबई। सरकार ने हर वित्त वर्ष के दौरान 50,000 टन तक ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात की मंजूरी दी है। यह निर्यात एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के नियमों के तहत होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नोटिफिकेशन में कहा, ऑर्गेनिक चीनी का निर्यात हर वित्त वर्ष में 50,000 टन की कुल सीमा के तहत एपीडा के तय किए गए तरीकों के आधार पर किया जाएगा। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे मजबूत

मुंबई। डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 23 पैसे की बढ़त के साथ 89.75 पर बंद हुआ। आरबीआई के डॉलर बेचने से रुपया लाभ में रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा, मजबूत औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों ने स्थानीय मुद्रा को सहारा दिया। हालांकि, मजबूत डॉलर, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पूंजी निकासी ने तेज वृद्धि को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.98 पर खुला। एजेंसी

ब्लिंकिट के सीएफओ का एक साल में ही इस्तीफा

नई दिल्ली। इटरनल के स्वामित्व वाली क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) विपिन कपूरिया ने एक साल में ही इस्तीफा दे दिया है। कपूरिया का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब घरेलू ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। प्रतिद्वंद्वी कंपनी जेप्टो ने गोपनीय तरीके से 11,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ का मसौदा जमा कराया है। एजेंसी

वाणिज्यिक परिवहन सेगमेंट में उतरी ह्यूंडई

नई दिल्ली। ह्यूंडई मोटर इंडिया ने प्राइम टैक्सी श्रृंखला के साथ वाणिज्यिक परिवहन सेगमेंट में प्रवेश की मंगलवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा, फ्लीट संचालकों एवं टैक्सी उद्यमियों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस श्रृंखला में प्राइम एचबी (हैचबैक) और प्राइम एसडी (सेडान) मॉडल शामिल हैं। इन मॉडल की शुरुआती कीमत क्रमशः 5,99,900 रुपये और 6,89,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है। एजेंसी

पीएंडजी होम प्रोडक्ट को 683 करोड़ का फायदा

नई दिल्ली। एरियल और टाइड की निर्माता प्रॉक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स को 2024-25 में 683.29 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। उसके पहले के साल की तुलना में यह 19.1 फीसदी अधिक है। परिचालन से राजस्व 3.4 फीसदी बढ़कर 9,054.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कुल आय दो फीसदी घटकर 9,228.83 करोड़ रुपये रह गई। एजेंसी

महंगाई के मोर्चे पर राहत के बीच इस वर्ष रेपो दर में हो चुकी है 1.25 फीसदी की कटौती

नए साल में आरबीआई से और प्रोत्साहन की आस, रुपये के प्रबंधन पर रहेगी नजर

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत के साथ मजबूत विकास दर ने इस बात की उम्मीद बढ़ा दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नए साल यानी 2026 में भी प्रोत्साहन दे सकता है। इस बीच, सबकी नजरें रुपये के प्रबंधन पर रहेंगी, जिसमें हालिया महीनों में लगातार गिरावट देखने को मिली।

रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई के बीच आरबीआई ने 2025 में छह मौद्रिक नीति समीक्षाओं में से चार में अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कुल 1.25 फीसदी की कटौती की। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस साल फरवरी में अपने पहले मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक से ही वृद्धि को समर्थन देने के लिए दरों में कटौती की शुरुआत की थी। इसके बाद जून में भी उन्होंने रेपो दर में 0.50 फीसदी की बड़ी कटौती की, क्योंकि कम महंगाई से नीतिगत स्तर पर ढील देने की महत्वपूर्ण गुंजाइश बनी।

नौकरशाह से केंद्रीय बैंक के गवर्नर बने मल्होत्रा ने पद संभालने के एक वर्ष पूरे होने पर मौजूदा स्थिति को भारत के लिए **दुर्लभ रूप से संतुलित आर्थिक दौर करार दिया।** इसमें अमेरिका के टैरिफ और भू-राजनीतिक बदलाव जैसे प्रतिकूल कारकों के बावजूद वृद्धि दर आठ फीसदी से ऊपर रही और महंगाई एक फीसदी से नीचे रही। गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे चलकर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कुछ नरम पड़ सकती है और अब तक घट रही खुदरा महंगाई भी बढ़कर आरबीआई के चार फीसदी के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी।

रुपये में लगातार गिरावट थामना सबसे बड़ी चुनौती

आरबीआई ने 2025 में अपने 90 वर्ष पूरे किए और इस साल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रुपया का डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर से नीचे फिसलना रहा। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उसका बाजार में हस्तक्षेप किसी स्तर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए होता है।

आरबीआई ने घरेलू मुद्रा के कमजोर होने के बीच इस साल के पहले नौ महीनों में 38 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार बेचा। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये का प्रबंधन आगे भी केंद्रीय बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।

■ **रुपया इस साल अब तक 4.79 फीसदी टूट चुका है। 31 दिसंबर, 2024 को यह डॉलर के मुकाबले 85.64 के स्तर पर बंद हुआ था।**

वास्तविक महंगाई के आंकड़ों पर उठे सवाल

चालू कीमतों पर जीडीपी वृद्धि कम रहने की चिंताओं के बीच मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई के कदम वास्तविक जीडीपी के आधार पर तय होते हैं, जो महंगाई घटाने के बाद सामने आती है। वास्तविक महंगाई के आंकड़े आरबीआई के अनुमानों से काफी कम रहे, जिससे केंद्रीय बैंक की पूर्वानुमान क्षमता को लेकर कुछ सवाल उठे। **इस पर डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा, आकलन में किसी तरह का प्रणालीगत पक्षपात नहीं है।**

मुख्य आय में गिरावट ने दिया बैंकों को झटका

रेपो दर कटौती और उधारी लागत में गिरावट की स्पष्ट अपेक्षाओं के चलते आरबीआई के कदम से बैंकों को झटका लगा। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी और मुख्य आय में गिरावट से बैंक प्रभावित हुए। हालांकि, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने और खास तौर पर नियामकीय ढील जैसे कदमों ने असर को कुछ हद तक कम किया।

■ **ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से समाधान पर रहा जोर :** आरबीआई ने पूरे साल नियामकीय ढील के लिए कई उपाए किए गए। अक्तूबर की मौद्रिक नीति घोषणा इसका चरम रही, जिसमें 22 नियामकीय उपाय शामिल थे। इनमें से कुछ उपाय आरबीआई जैसे संस्थान के लिए असामान्य थीं। **इनमें बैंकों को भारतीय कंपनियों की ओर से वैश्विक अधिग्रहणों के लिए वित्तपोषण की अनुमति देना शामिल है।** मल्होत्रा का जोर ग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता और शिकायतों का तेजी से समाधान करने पर रहा है, जो उनके कई भाषणों और टिप्पणियों में झलकता रहा है।

सीपीआई की गणना पद्धति में होगा बदलाव, 2026 में कम रहेगी महंगाई

खाद्य कीमतों में नरमी और जीएसटी कटौती ने उच्च कीमतों से दी राहत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। खुदरा महंगाई को लक्षित करने के लिए सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की गणना पद्धति में बदलाव और मौद्रिक नीति में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी और जीएसटी दरों में कमी के कारण इस वर्ष उच्च महंगाई से राहत मिली है। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई अगर 2 से 6 फीसदी के दायरे में बनी रही, तो आरबीआई रेपो दर में एक बार और कटौती कर सकता है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के अलावा सरकार के सितंबर में लगभग 400 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी करने के निर्णय ने देश में मूल्य स्थिति को और बेहतर बनाने में मदद की। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ने भी 2025 तक मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के स्पष्ट संकेत दिखाए। शुरुआती महीनों में सकारात्मक लेकिन घटती डब्ल्यूपीआई महंगाई दर्ज की गई, जो विशेष रूप से खाद्य और ईंधन श्रेणियों में मूल्य दबाव में नरमी को दर्शाती है।

खुदरा महंगाई नवंबर, 2024 से घटनी शुरू हुई और तब से जून, 2025 तक यह रिजर्व बैंक के 2 से 4 फीसदी के दायरे में बनी रही। इसके बाद यह 2 फीसदी से भी नीचे आ गई। सीपीआई में लगभग 48 फीसदी हिस्सा रखने वाली खाद्य महंगाई जनवरी में लगभग 6 फीसदी से घटनी शुरू हुई और जून में नकारात्मक स्तर पर यानी शून्य से नीचे पहुंच गई। नवंबर में खाद्य महंगाई (-)3.91 फीसदी थी।

पहली छमाही में 4 फीसदी का अनुमान

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, अगले वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में शीर्ष महंगाई के 4 फीसदी के लक्ष्य के करीब रह सकती है। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई काफी कम रहने की संभावना है, जैसा 2024 की शुरुआत से ही रुझान रहा है।

■ **अच्छे कृषि उत्पादन,** कम खाद्य कीमतों और वैश्विक कमोडिटी कीमतों के असाधारण रूप से अनुकूल दृष्टिकोण से संकेत मिलता है कि पूरे वर्ष (2025-26) के लिए खुदरा महंगाई करीब 2 फीसदी रह सकती है, जो वर्ष की शुरुआत में अनुमानित दर का आधा है।

फरवरी में आएगी सीपीआई की नई श्रृंखला

आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में पहले ही परामर्श पत्र जारी कर चुका है। इस बीच सरकार आधार वर्ष (2024=100) के साथ एक नई सीपीआई श्रृंखला पर काम कर रही है। इसमें सूचकांक संकलन में उपयोग होने वाले कई सारे पैमानों में बदलाव किया जाएगा।

■ एक दशक से अधिक समय के बाद किया जा रहा यह बदलाव मुद्रास्फीति आंकड़ों की प्रतिनिधित्व क्षमता, सटीकता, विश्वसनीयता और समग्र गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार खुदरा महंगाई की नई श्रृंखला फरवरी में जारी कर सकती है।

चांदी फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, सोना 2,800 रुपये सस्ता

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच 1,000 रुपये बढ़े चांदी के दाम, पीली धातु में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट

नई दिल्ली। मजबूत वैश्विक संकेतों के अनुरूप चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1,000 रुपये के भारी उछाल के साथ 2.41 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और यह 2,800 रुपये सस्ती होकर 1,39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

सोमवार को चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ था। सराफा कारोबारियों ने कहा, मजबूत औद्योगिक मांग और वैश्विक कीमतों में तेजी से स्थानीय बाजार में चांदी को बढ़ावा मिला। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद चांदी को ढांचागत आपूर्ति की दिक्कतों और मजबूत औद्योगिक मांग (खासकर सौर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा सेंटर बुनियादी ढांचा) से समर्थन मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी 3.72 डॉलर यानी 5.15 फीसदी बढ़कर 75.85 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। वहीं, हाजिर सोना 69.61 डॉलर यानी 1.61 फीसदी बढ़कर 4,401.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। **उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स)** में मार्च 2026 डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध की कीमत 9,590 रुपये यानी 4.27 फीसदी बढ़कर 2,34,019 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसमें 11,915 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोमवार को चांदी 14,387 रुपये यानी छह फीसदी बढ़कर 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। एजेंसी

दिसंबर में तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच सकता है रूस से कच्चा तेल आयात, भारत में तेजी से घटी मांग

नई दिल्ली। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात दिसंबर, 2025 में तेजी से घट सकता है। लेकिन, यह गिरावट आपूर्ति स्रोतों में संरचनात्मक बदलाव के बजाय अल्पकालिक बाधाओं की ओर संकेत कर रही है।

रियल टाइम आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी केप्लर के मुताबिक, दिसंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) रहने का अनुमान है। यह दिसंबर, 2022 के बाद तीन साल सबसे निचला स्तर होगा। नवंबर में भारत ने रूस से 18.4 लाख बीपीडी कच्चा तेल खरीदा था। इस गिरावट के बीच भारतीय रिफाइनरी गैर-प्रतिबंधित कंपनियों से रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं।

विश्लेषकों ने अक्तूबर में ही इस गिरावट की ओर इशारा किया था। ऐसा रूस के शीर्ष निर्यातकों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी कार्रवाई एवं रूस से जुड़े उत्पाद प्रवाह पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के चलते हुआ।

केप्लर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा, दिसंबर में भारत में रूसी कच्चे तेल की मांग तेजी से घटी है और आयात 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। जनवरी से नए बिचौलियों के आने और आपूर्ति श्रृंखलाओं के दोबारा स्थापित होने के साथ कच्चे तेल के आयात में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है। एजेंसी

कंपनियां 31 जनवरी तक दाखिल कर सकेंगी वित्तीय विवरण और सालाना रिटर्न

नई दिल्ली। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मंगलवार को कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण और सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी। यह विस्तार कंपनी कानून के तहत 2024-25 से संबंधित फाइलिंग के लिए दिया गया है। पहले वित्तीय विवरण और सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी।

मंत्रालय ने यह फैसला विभिन्न हितधारकों से मिले आवेदनों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई कंपनियों और पेशेवरों ने फाइलिंग प्रणाली से संबंधित तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया था। मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा, इसके लिए कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क से छूट भी दी गई है। एजेंसी

शेयर बाजार : विदेशी पूंजी निकासी के बावजूद 30 लाख करोड़ बढ़ गई संपत्ति

विदेशी पूंजी निकासी, टैरिफ संकट, घरेलू बाजार के उच्च मूल्यांकन और कमजोर रुपये जैसी कई चुनौतियों के बावजूद बीएसई सेंसेक्स में इस साल 8 फीसदी से अधिक की तेजी आई है। इससे निवेशकों की पूंजी 2025 में 30 दिसंबर तक करीब 30 लाख करोड़ बढ़ गई। घरेलू निवेशकों के मजबूत समर्थन से बाजार पर दबाव कम पड़ा। ब्यूरो

ऐसे बढ़ती गई बाजार पूंजी

471.72 लाख करोड़ पहुंच गई बाजार पूंजी 30 दिसंबर, 2025 तक

441.95 लाख करोड़ रुपये था पूंजीकरण 31 दिसंबर, 2024 को

तब से अब तक 29.77 लाख करोड़ की बढ़त

एक साल में सेंसेक्स

6,536.07 अंक या 8.36 फीसदी चढ़ा सेंसेक्स, 30 दिसंबर, 2025 को 84,675.08 पर बंद

78,139.01 अंक पर बंद हुआ था 31 दिसंबर, 2024 को

9.70 फीसदी या 2,294.05 अंक की बढ़त रही निफ्टी में

नौ शहरों में मकानों का पंजीकरण 5 फीसदी घटकर 5.45 लाख इकाई

नई दिल्ली। देश के नौ शहरों में इस साल 25 दिसंबर तक आवासीय संपत्तियों का पंजीकरण पांच फीसदी घटकर 5.45 लाख इकाई रहा। इस दौरान कुल मूल्य 11 फीसदी बढ़कर 4.46 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वर्ष 2024 के दौरान 5.77 लाख मकान पंजीकृत हुए थे, जिनका कुल मूल्य 4.03 लाख करोड़ रुपये था।

रियल एस्टेट सलाहकार स्क्वायर याड्‌र्स के मुताबिक, ये आंकड़े पुणे, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पंजीकृत नए एवं पुराने दोनों प्रकार के संपत्तियों से जुड़े हैं। कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ तनुज शोरी ने कहा, अधिक खर्च योग्य आय वाले समृद्ध भारतीयों की संख्या में तेज बढ़ोतरी के बीच 2025 में खासकर मुंबई महानगरीय क्षेत्र जैसे बाजारों में प्रीमियम और लग्जरी मकानों का कुल मूल्य में वर्चस्व रहा। हालांकि, मांग संरचनात्मक रूप से मजबूत बनी हुई है, लेकिन नए साल यानी 2026 में लग्जरी मकानों की बिक्री में वृद्धि की रफ्तार धीमी रह सकती है। एजेंसी

उपलब्धि ऊंची ब्याज दरें, कमजोर मांग एवं व्यापार तनावों के बीच भारत ने तेज विकास दर, नियंत्रित महंगाई और मजबूत घरेलू मांग का किया प्रदर्शन

वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू ताकत के दम पर 2025 में चमकता सितारा बना रहा भारत

अमर उजाला नेटवर्क

नई दिल्ली। साल 2025 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सुस्ती और अनिश्चितता का वर्ष रहा, लेकिन भारत इस परिदृश्य में एक अपवाद के रूप में उभरा। अमेरिका एवं यूरोप में ऊंची ब्याज दरें, कमजोर उपभोक्ता मांग और व्यापार तनावों के बीच भारत ने अपेक्षाकृत तेज विकास दर, नियंत्रित महंगाई और मजबूत घरेलू मांग का प्रदर्शन किया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और आरबीआई के आकलन बताते हैं कि 2025 में भारत की आर्थिक कहानी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संरचनात्मक मजबूती से गढ़ी गई। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के मुताबिक, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2025 में करीब 6.8 फीसदी रही। यह वैश्विक औसत 3.2% से अधिक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों में भी सेवा क्षेत्र, निर्माण और सार्वजनिक निवेश को विकास का प्रमुख इंजन बताया गया। सीएमआईई के अर्थशास्त्री महेश व्यास का कहना है कि भारत की वृद्धि का सबसे बड़ा आधार घरेलू मांग है, जिसने निर्यात और वैश्विक व्यापार की सुस्ती के असर को संतुलित किया।

महंगाई व आरबीआई : संतुलन की परीक्षा

2025 में भारत में खुदरा महंगाई औसतन 5.4 फीसदी रही, जो कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम थी। खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद मुख्य महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित रही। इससे आरबीआई को भी राहत मिली और उसने मौद्रिक नीति के मोर्चे पर विकास-समर्थक लेकिन सतर्क नीति अपनाई।

सरकारी पूंजीगत खर्च और निजी निवेश से बढ़ा रोजगार

2025 में केंद्र का पूंजीगत खर्च जीडीपी के 3.4 फीसदी तक पहुंच गया। सड़क, रेलवे, रक्षा उत्पादन और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश ने मांग एवं रोजगार दोनों को सहारा दिया। विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक निवेश ने निजी क्षेत्र के लिए क्राउड-इन इफेक्ट पैदा किया। **नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के मुताबिक,** भारत की विकास रणनीति अब निवेश और उत्पादकता बढ़ाने पर आधारित है, जो इसे लचीला बनाती है।

अमेरिकी टैरिफ : कितना गहरा था झटका

अमेरिकी टैरिफ को इस वर्ष का सबसे बड़ा बाहरी आर्थिक झटका माना गया। अमेरिका को भारत के निर्यात में दूसरी और तीसरी तिमाही में 6-7 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि, इस झटके का असर सीमित रहा, क्योंकि यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में निर्यात बढ़ा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिस्वजीत धर के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी विविध हो चुकी है कि एक बाजार का झटका सिस्टमेटिक संकट नहीं बन पाया।

2026 में...अवसरों और जोखिम के बीच संतुलन

2026 भारत के लिए नीतिगत फैसलों, वैश्विक भू-आर्थिक बदलावों और घरेलू सुधारों की वास्तविक परीक्षा का वर्ष बनेगा। नए साल में भारत की आर्थिक दिशा अवसरों और जोखिमों दोनों से तय होगी। 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5-6.9 फीसदी रह सकती है और भारत सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

कल्पमेधा

जब आप सहर्ष वही बने रहने पर राजी होते हैं, जो आप हैं और तुलना, प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते हैं, तो सभी आपका सम्मान करते हैं और आपको इज्जत देते हैं।

– लाओत्से

संरक्षण की सुध

हाल ही में अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई परिभाषा सामने आने के बाद स्वाभाविक ही यह बहस तेज हो गई कि अगर इसे कसौटी बनाया गया, तो आने वाले वक्त में स्थानीय पारिस्थितिकी पर इसका क्या असर पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता के स्तर पर सौ मीटर की ऊंचाई वाली परिभाषा को लेकर चिंता जताई गई और एक बड़े इलाके के पर्यावरण पर जोखिम की आशंका के मद्देनजर इसमें फिर से बदलाव की मांग की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगा दी और कहा कि कुछ महत्त्वपूर्ण अस्पष्टता को दूर करने की जरूरत है। इसमें एक सवाल यह भी शामिल है कि क्या सौ मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच पांच सौ मीटर का अंतर पर्यावरण संरक्षण के दायरे के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को कम कर देगा। गौरतलब है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रपट आने तक नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी गई थी।

दरअसल, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत-शृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और बिना रोकटोक खनन से समूचे क्षेत्र में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। इसी संबंध में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की थी कि अरावली पहाड़ियों के संबंध में स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है। समिति ने यह भी कहा था कि अरावली जिलों में स्थित सौ मीटर या उससे अधिक की किसी भी भू-आकृति को पहाड़ी माना जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसे स्वीकार्यता मिलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अरावली के जीवन को लेकर चिंता जताई गई और कई सवाल उठे। यह एक जगजाहिर तथ्य है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में फैली अरावली पहाड़ियां कैसे एक जीवन-रेखा की भूमिका में खड़ी हैं और पर्यावरण के लिहाज से इसकी कितनी अहमियत है। ऐसे में स्वाभाविक ही यह सवाल उठा कि इस पर्वत श्रेणी में निर्बाध खनन गतिविधियों को अगर खुली छूट दी गई तो यह सार्वजनिक हित के लिहाज से कितना सही है!

पर्यावरण विशेषज्ञों और इस मसले पर शोधकर्ताओं का साफ मानना रहा है कि अगर सौ मीटर से नीचे की सभी पहाड़ियों में खनन की इजाजत दे दी जाती है, तो इसका असर समूचे इलाके में पड़ेगा। पश्चिम की तरफ से आने वाली गर्म हवा और धूल भरी आंधियों को रोकने में अरावली की पहाड़ियां एक तरह की दीवार का काम करती हैं। इस संदर्भ में देखें तो इन पहाड़ियों की यह भूमिका और महत्त्व सभी जानते हैं कि अगर इन्हें नुकसान पहुंचा, तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में धूल भरी आंधियों और सूखे का प्रकोप काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर कोई सख्त नियम-कायदे तय नहीं किए गए, तो उसके बाद उस इलाके में खनन और निर्माण से जुड़ी अन्य गतिविधियों से पर्यावरण पर व्यापक पैमाने पर नकारात्मक असर पड़ेगा और पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट हो जाने की आशंका है। यह सही है कि विकास की राह न रुके, लेकिन अगर इसकी कीमत पर एक बड़े इलाके के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है, तो विकास की परिभाषा पर सवाल उठेंगे।

सपना और सच

देश में पिछले कुछ वर्षों से एनआरआइ यानी अनिवासी भारतीयों से शादी रचाने का चलन बढ़ रहा है। विदेश की चकाचौंध यहां के परिवारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मगर कई बार उनके ये सपने तब डरावनी हकीकत में बदल जाते हैं, जब उन्हें धोखाधड़ी, शोषण, परित्याग, और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रपट से पता चलता है कि इस तरह की परेशानियां सबसे ज्यादा पंजाब की महिलाओं को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि यहां अनिवासी भारतीयों से विवाह का आंकड़ा भी ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, और केरल सहित दूसरे राज्यों का स्थान आता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में दो देशों के शामिल होने से कानूनी प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है। हालांकि, सरकारी तंत्र में इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए व्यवस्था मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका प्रभावी असर कम ही दिखाई देता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रपट के मुताबिक, वर्ष 2024 में देशभर से ऐसे मामलों से जुड़ी चार सौ से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। जबकि, इस वर्ष एक जनवरी से 31 मार्च तक यह आंकड़ा सौ से ज्यादा रहा। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष पंजाब में अनिवासी भारतीयों से विवाह के विवाद को लेकर सबसे ज्यादा 49 शिकायतें मिली। इसी तरह, महाराष्ट्र से 37 और दिल्ली से 31 मामले सामने आए। पंजाब में इस तरह के मामले अधिक होने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके तेज किया जाता है। विदेश में भारतीय दूतावासों और मिशनों के जरिए भी समाधान तलाशने की कोशिश की जाती है। मगर हकीकत यह है कि विदेश में भाषा, कानून और सामाजिक सहयोग के अभाव में पीड़ित महिलाओं के लिए मदद पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाए, ताकि दोषियों को जल्द न्याय के कठघरे में लाया जा सके।

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नई संभावनाएं

नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के आकार लेने से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा व्यापार घाटे की चिंताएं भी कम होंगी।

जयंतीलाल भंडारी

अमेरिका की ओर से भारी-भरकम शुल्क लगाने के बावजूद भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) इस समय निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य कई देशों के साथ एफटीए के आकार लेने से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ेंगे और व्यापार घाटे की तमाम चिंताएं भी कम होंगी। हाल ही में जारी विदेश व्यापार के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 अरब डालर से बढ़ कर 73.99 अरब डालर हो गया। निर्यात में 15.52 फीसद की वृद्धि हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यापार समझौतों में नए श्रम कानून जान फूंकते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में भारत से निर्यात नई ऊंचाई पर होंगे। पिछले दिनों सरकार ने कहा कि भारत द्वारा किए गए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते से पेशेवर सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के कारण भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसर खुलेंगे और पेशेवर सेवाओं का निर्यात भी बढ़ेगा।

गौरतलब है कि हाल ही में 22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है और इस समझौते से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क सुनिश्चित किया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में अगले पंद्रह वर्षों में 20 अरब डालर के प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है। दूसरी ओर, भारत ने न्यूजीलैंड के 70 फीसद उत्पादों के लिए शुल्क में कमी की पेशकश की है, जो 95 फीसद द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को शामिल करती है। ऐसे में इस समझौते से 30 फीसद उत्पादों के लिए शुल्क खत्म हो जाएगा। इस समझौते के तहत लगभग 29.97 फीसद उत्पादों को सूची से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, दही, पनीर, मांस और मट्ठा के साथ अन्य पशु उत्पाद, चना, मक्का, बादाम, चीनी एवं प्याज जैसी वस्तुएं शामिल हैं। एफटीए लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के लिए भारत का शुल्क घट कर 13.18 फीसद हो जाएगा।

इस मुक्त व्यापार समझौते का मजबूत पक्ष भारत से सेवा निर्यात बढ़ाना और यहां से पेशेवरों को न्यूजीलैंड में अच्छे अवसरों के लिए आगे बढ़ाना भी है। यह समझौता भारत की प्रतिभाओं, नवउद्यम और नवाचार के लिए एक मजबूत बुनियाद प्रदान करता है। यह भारत के लिए सबसे प्रमुख सेवाओं की ऐसी पेशकश करता है, जो अब तक किसी भी पिछले समझौते में शामिल नहीं रहा है। यह समझौता न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों पर संख्या संबंधी सीमाओं को भी हटाता है। साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों के लिए तीन वर्ष तक और डाक्टरेट कर चुके विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के बाद चार साल तक न्यूजीलैंड में काम करने अवसर प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भारत के कुशल पेशेवरों के लिए मुक्त व्यापार समझौता एक नया अस्थायी रोजगार प्रवेश (टीईई) यानी वीजा प्रदान करता है। इसका लाभ उच्च मांग वाले क्षेत्रों के भारतीय पेशेवर ले सकेंगे।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के महज चार दिन पहले 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में मस्कट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान के उनके समकक्ष कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) कहा गया है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत-ओमान के बीच समझौते के तहत भारत के 98 फीसद निर्यात को ओमान के बाजार में शून्य शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इस समझौते से भारत के कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवाई, वाहन, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर से भारत से करीब 3.64 अरब डालर के निर्यात पर ओमान में फिलहाल लगने वाला पांच फीसद शुल्क शून्य हो जाएगा। इसके बदले में भारत ने ओमान से आने वाले विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी सुनिश्चित की है।

> **भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के महज चार दिन पहले 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के उनके समकक्ष कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) कहा गया है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि ओमान के साथ समझौते के तहत भारत के 98 फीसद निर्यात को वहां के बाजार में शून्य शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इस समझौते से भारत के कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवाई, वाहन, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।**

ओमान से भारत आने वाले 95 फीसद उत्पादों के शुल्क कम होंगे। इनमें खजूर, मार्बल और 'पेट्रोकेमिकल' उत्पाद शामिल हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के हित में कई अहम बातें हैं। हमारे देश ने घरेलू हितों की रक्षा के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। पेशेवर आवाजाही पर भी एफटीए में भारत के हित हैं। पहली बार ओमान ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही पर व्यापक रियायतें दी हैं। अब एक अप्रैल 2026 से भारत-ओमान समझौता लागू होने के बाद भारतीय उत्पाद और सेवा निर्यात ओमान में बढ़ सकेंगे और हमारा प्रतिकूल व्यापार असंतुलन कम होगा।

यह बात अहम है कि राजग शासन के दौरान मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति से संबंधित जो नए आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उनके मुताबिक जहां इन देशों के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा है, वहीं इन देशों में निर्यात भी बढ़ रहे हैं। वहां से भारत को अधिक निवेश प्राप्त हो रहा है। एक अक्तूबर से भारत और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। एफ्टा देशों को निर्यात बढ़ने लगे हैं। इसी तरह भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया मुक्त व्यापार समझौता भी अहम है। पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ समझौते के विभिन्न पहलुओं पर रणनीतिक मंथन किया और कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसर बेजोड़ होंगे। इतना ही नहीं, नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और इजराइल सहित अन्य कई प्रमुख देशों के साथ भी व्यापार समझौते आकार लेते हुए दिखाई देंगे।

पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में 23वीं भारत-रूस शिखर बैठक में भारत के साथ 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार बढ़ा कर सौ अरब डालर किया जाना सुनिश्चित करते हुए भारत-रूस मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता तेजी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार और एफटीए के अधिकतम लाभ लेने और विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए एक अप्रैल 2026 से भारत में लागू किए जाने वाले नए श्रम कानून भी मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जिन नए श्रम कानूनों के तहत चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, उनसे श्रमिकों के लिए राहत और उद्योग-कारोबार के लिए आर्थिक रफ्तार का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। नए श्रम कानून के तहत चार श्रम संहिताएं- मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 शामिल हैं।

उम्मीद करना चाहिए कि नए वर्ष में सरकार दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आकार देने के साथ-साथ समझौते के लाभों को पाने के लिए देश के उद्योग-कारोबार और श्रम बल को नई दक्षता के साथ तैयार करेगी। ऐसे में यह भी उम्मीद करें कि ये समझौते भारत को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की डगर पर आगे बढ़ाएंगे।

दायित्व बोध का संकट

शिवम भारद्वाज

हाल ही में लखनऊ में जिस तरह के दृश्य सामने आए, वह उस व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति का आईना है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान सजावट के लिए लगाए गए पौधों को जिस सहजता से तथाकथित सभ्य लोगों ने उठा लिया, उसने एक असहज सवाल खड़ा किया है कि विकास की भाषा धाराप्रवाह बोलने वाले हम लोग, क्या अपने नागरिक होने का अर्थ भूलते जा रहे हैं! यह घटना इसलिए भी विचलित करती है क्योंकि इसमें वे लोग शामिल नहीं थे, जिनके लिए मजबूरी या अभाव का तर्क दिया जा सके। गमले उठाने वाले वैसे लोग थे, जिन्हें समाज संपन्न, शिक्षित और 'सभ्य' मानता है। जब लाखों रुपए की गाड़ी रखने वाला व्यक्ति कुछ सौ रुपए का सरकारी गमला उठाकर ले जाता है, तो यह उस मानसिकता की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें सार्वजनिक वस्तु को 'मुफ्त का माल' समझ लिया जाता है। यह आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक दरिद्रता का भी लक्षण है।

हम अक्सर यह मान लेते हैं कि शिक्षा, आय और आधुनिक जीवन-शैली अपने साथ अनुशासन और नैतिकता भी ले आती है, लेकिन ऐसी घटनाएं इस भ्रम को बार-बार तोड़ती हैं। सच यह है कि संपन्नता और संस्कार के बीच कोई स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। कई बार सुविधा और ताकत का अहसास व्यक्ति को नियमों से ऊपर होने का भ्रम दे देता है। यही भ्रम सार्वजनिक जीवन को सबसे गहरी चोट पहुंचाता है, क्योंकि इससे नागरिक जिम्मेदारी आत्मसात होने के बजाय धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है।

भारतीय संविधान नागरिकों को केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि उनके कर्तव्य भी स्पष्ट करता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक दायित्व है, लेकिन व्यवहार में हमने अधिकारों को प्राथमिकता और कर्तव्यों को औपचारिकता बना लिया है। अधिकारों की बात आते ही हम मुखर हो जाते हैं, लेकिन कर्तव्यों की चर्चा होते ही चुप्पी साध लेते हैं। यही असंतुलन समाज के नैतिक ढांचे को भीतर से खोखला करता है।

कुछ समय पहले भी लखनऊ में ही आम महोत्सव के दौरान प्रदर्शनी में सजाकर रखे गए आमों को लोगों ने लूट लिया था। वह भी किसी अव्यवस्थित या अभावग्रस्त भीड़ का आचरण नहीं था, बल्कि उन्हीं नागरिकों का था, जिन्हें ऐसे आयोजनों का जागरूक दर्शक और उपभोक्ता माना जाता है। इससे पहले बड़े आयोजनों के दौरान गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में सार्वजनिक स्थलों से फूल-पौधों की चोरी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। महंगी गाड़ियों में इन चीजों की चोरी की तस्वीरें और वीडियो सुर्खियों में आए थे। इसी तरह एक राजनीतिक रैली में लोग खाट लेकर भागते दिख रहे थे। समस्या किसी एक आयोजन या प्रशासनिक चूक की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता का परिणाम है, जो सार्वजनिक स्थान को 'सरकारी' और 'बेपरवाह इस्तेमाल' की वस्तु मान लेती है।

हम निजी बातचीत में भ्रष्टाचार, व्यवस्था की खामियों और प्रशासन की विफलताओं पर खुलकर चर्चा करते हैं, नेताओं और अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब अपने आचरण की बारी आती है, तो हम वही करते हैं जो हमें सुविधाजनक लगता है। हम अक्सर उन देशों की प्रशंसा करते हैं, जहां सड़कें साफ हैं, कतारें अनुशासित हैं और सार्वजनिक व्यवस्था सुचारु है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह नागरिकों के रोजमर्रा के छोटे-छोटे निर्णयों का फल है- कचरा जहां-तहां न फेंकने, नियम न तोड़ने और जो अपना नहीं है, उसे न छूने का निर्णय। सभ्यता इन्हीं निर्णयों से बनती है। वहां व्यवस्था केवल कानूनों से नहीं, बल्कि नागरिकों के आत्म-अनुशासन से चलती है। सार्वजनिक स्थल वहां सरकार की नहीं, नागरिकों की भी जिम्मेदारी होते हैं।

यह समझना जरूरी है कि सड़कें, उद्यान, स्मारक और सार्वजनिक स्थल किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं हैं। वे हमारे ही कर या टैक्स के पैसों से बने हमारे साझा स्थान हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाना आखिर अपनी ही सामूहिक संपदा को क्षति पहुंचाना है। यह वैसा ही है जैसे कोई अपने ही घर की चीजें तोड़ दे और फिर अव्यवस्था का रोना रोए। सभ्यता की पहचान ऊंची इमारतों, भव्य आयोजनों या चमकदार ढांचों से नहीं होती। उसकी पहचान नागरिकों के छोटे-छोटे व्यवहार से होती है। संस्कार किसी योजना या बजट से नहीं आते, वे रोजमर्रा के आचरण से बनते हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रशासन ने कितनी सुरक्षा की या कितने गमले लगाए, सवाल यह है कि क्या हम ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जहां सार्वजनिक नैतिकता केवल भाषणों और उपदेशों तक सीमित रह गई है!

किसी भी सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता। वह धीरे-धीरे होता है। शब्दों से पहले व्यवहार में, नीतियों से पहले आदतों में। जब नियम केवल दूसरों के लिए रह जाते हैं और सुविधा नैतिकता से बड़ी हो जाती है, तब पतन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है- चाहे बाहर से सब कुछ कितना ही आधुनिक क्यों न दिखे। ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास का अर्थ क्या केवल भव्य आयोजन, सजावट और चमकदार ढांचे हैं। अगर नागरिकों में जिम्मेदारी, संयम और साझा स्वामित्व का भाव नहीं होगा, तो यह विकास सतही और अल्पकालिक साबित होगा। नियमों का पालन डर से नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी से होना चाहिए, क्योंकि सभ्यता शोर से नहीं बचती, वह चुपचाप निभाए गए कर्तव्यों से बचती है। और इतिहास आखिर इन्हीं कर्तव्यों का हिसाब रखता है।

दुनिया मेरे आगे

> **हम अक्सर उन देशों की प्रशंसा करते हैं, जहां सड़कें साफ हैं, सार्वजनिक व्यवस्था सुचारु है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह नागरिकों के छोटे-छोटे निर्णयों का फल है- कचरा जहां-तहां न फेंकने, नियम न तोड़ने और जो अपना नहीं है, उसे न छूने का निर्णय। सभ्यता इन्हीं निर्णयों से बनती है।**

सफलता के पैमाने

हर वर्ष देश में लगभग पचास लाख से अधिक विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। यह आंकड़ा केवल शिक्षा जगत की चिंता नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य पर गहराते संकट का संकेत भी है। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके बच्चे और युवा सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, किंतु जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर हो जाते हैं, तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करता है। हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी परीक्षा-केंद्रित है, जहां अंक ही प्रतिभा का पैमाना बन गए हैं। असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानने के बजाय उसे नाकामी की तरह देखा जाता है। नतीजा यह कि अनेक छात्र आत्मविश्वास खो बैठते हैं और मानसिक दबाव में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति और भी भयावह होती है, क्योंकि वे दोबारा अवसर नहीं जुटा पाते। इसका असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब लाखों युवा अधूरी शिक्षा के साथ श्रम बाजार में उतरते हैं, तो देश को अकुशल कार्यबल मिलता है। इससे उत्पादकता घटती है, बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास की गति बाधित होती है।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

गुणवत्ता के बजाय

सरकार बुनियादी शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन सरकारी विद्यालय शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ करने के बाद भी इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या क्यों घटती जा रही है? असल में सरकार छात्रों की घटती संख्या के मूल कारणों पर गौर ही नहीं कर रही। मुख्य कारण यह है कि सरकार ने अपने दस कार्यों की पूर्ति के लिए केवल एक व्यक्ति नियुक्त कर रखा है, वह है- प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक। चुनाव हो या जनगणना, भैंस गिनवानी हो या बकरी, सभी कार्यों के लिए एक ही व्यक्ति है, और वह है प्राथमिक शिक्षक। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कुछ तो शिक्षक ही अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं और कुछ हैं भी, तो उन्हें सरकार मूल काम ही नहीं करने देती। इसलिए सरकार जब तक शिक्षकों को सिर्फ अध्यापन के लिए जिम्मेदारी नहीं देगी, तब तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने वाला।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ

ठगी की तकनीक

साइबर फर्जीवाड़े का सर्वाधिक शिकार पढ़े-लिखे और बुजुर्ग हो रहे हैं। जीवन भर की कमाई एक झटके में अपराधियों के खाते में चली जाती है। नए खाते खोलने के बैंकों के लक्ष्य से ये साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं। बैंकों में कर्मियों की कमी के कारण खातों पर निगरानी रखने में बैंकिंग तंत्र पूरी तरह विफल साबित हुआ है। करोड़ों रुपए खातों में आते हैं और आसानी से अपराधी अपने खाते में अंतरण कर लेते हैं और फिर तेजी से निकाल भी लेते हैं। रिजर्व बैंक को बैंकों के साथ मिल कर ऐसा तंत्र तैयार करना होगा कि खाताधारक के खाते से किसी सूरत में राशि निकल ही न सके। दूसरा जब भी कोई खाताधारक अपनी बड़ी राशि की आरटीजीएस कराए या किसी नए खातों में घबराहट दिखाते हुए अंतरण करने लगे, तो बैंक प्रबंधक को सतर्क हो जाना चाहिए। सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ऐसे मामलों पर अंकुश के लिए साइबर मुख्यालय बनाया जाना चाहिए।

– आरके शर्मा, रोहिणी, दिल्ली

स्वागतयोग्य पहल

'पढ़ने को प्रोत्साहन'(संपादकीय, 27 दिसंबर) पढ़ा। मौजूदा डिजिटल युग में छात्र-छात्राओं में पढ़ने की आदत कम हो रही है। इसके कारण उनकी परिपक्वता और सृजनात्मकता प्रभावित हो रही हैं। विपरीत परिस्थितियों से जूझने की उनकी क्षमता भी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल प्रशंसनीय है कि स्कूलों में अखबारों के वाचन पर जोर दिया जा रहा है। मगर इसमें निरंतरता नहीं रही, तो ऐसे आदेश निष्प्रभावी साबित होंगे। कम उम्र के बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देने के बुरे नतीजों को देखते हुए कई देशों ने इसके इस्तेमाल की उम्र सीमा तय कर दी है। अब जबकि भारत में एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, तब बड़े- बुजुर्गों का साथ बच्चों को मिलना बंद हो गया है। यही वजह है कि बच्चों में स्मार्टफोन की लत बढ़ रही है। यह चिंता की बात है।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का नव वर्ष संदेश पहली बार हिंदी और उर्दू में जारी

पहली बार, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने वर्ष 2026 के लिए अपना नववर्ष संदेश हिंदी सहित अन्य भाषाओं में जारी किया है। एंतोनियो गुतारेस का नववर्ष संदेश 11 भाषाओं में जारी किया गया है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश के साथ-साथ हिंदी और उर्दू भी शामिल हैं। इस अवसर पर उनके वीडियो संदेश में हिंदी सबटाइटल भी उपलब्ध कराए गए हैं। नये साल के लिए एक अपील में, महासचिव गुतारेस ने आज विश्व नेताओं से प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और विनाश के बजाय विकास में निवेश करने का आह्वान किया। गुतारेस ने सोमवार को 2026 के लिए अपने संदेश में कहा, 'जैसा कि हम नये साल में प्रवेश करने वाले हैं, दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। हमारे चारों ओर अराजकता और अनिश्चितता है। लोग हर जगह पूछ रहे हैं: क्या नेता सच में सुन रहे हैं? क्या वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं।

इस बार सर्दी में बर्फ विहीन हैं उत्तराखंड के पहाड़

सुनील दत्त पांडेय

दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन इस बार पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी का इंतजार ही होता रहा। सैलानियों की इच्छा बर्फबारी के दौरान आनंद उठाने की रहती है। इस बार सर्दियों में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड की पहाड़ियां बर्फ विहीन हैं। 2025 साल समाप्ति पर है और अभी तक इस सर्दियों में उत्तराखंड की पर्वतीय चोटियों में बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण पर्यटक तो मायूस है ही, साथी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के किसान बहुत निराशा है क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी उतनी ही सेब और अन्य फलों तथा सब्जियों की पहाड़ों में ज्यादा उपज होगी वहीं बारिश न होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में सरसों गेहूं की फसल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

बदलाव

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बी जोशी का कहना है कि इस वर्ष 2025 में मौसम पूरी तरह करवटें बदलते रहा, अगर हम ध्यान दें तो 2025 की शुरुआत में ठंड कम पड़ी बर्फ भी कम गिरी और बर्फ कम गिरने से हमारे हिमालय के हिमनदों में बर्फ की कमी बनी रही, गंगा के जलस्तर तथा हिमालय से उद्गम होने वाली अन्य नदियों के जलस्तर में काफी कमी आई, साथ ही कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित ओम पर्वत बर्फबारी कम होने और बर्फ के तेजी से पिघलने के बाद है ओम शब्द काफी समय तक अदृश्य रहा।

प्रोफेसर जोशी कहते हैं कि इस सब का कारण 2025 में बर्फ का कम गिरना और दूसरी ओर इस वर्ष गर्मियां भी उतनी तेज नहीं थी, जितनी 2022 और 2023 की वर्ष में रही लेकिन फिर भी वर्षा ऋतु इस वर्ष अच्छा प्रभाव बना रहा दूसरी ओर हमारे देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का प्रकोप बना रहा अनेक स्थानों पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई और कई स्थानों पर सामान्य से कम बारिश हुई। 2024 और 25 में हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में हुई अनेक प्राकृतिक दुर्घटनाएं हुई, जिनका सीधा संबंध बारिश के मौसम में अति वृष्टि होना रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस सब का कारण है जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया का जारी रहना। प्रोफेसर जोशी कहते हैं कि देखने में आया है कि पर्यावरणीय संतुलन लगातार असंतुलित हो रहा है जिसके कारण पर्यावरण का विस्थापन तेजी के साथ हो रहा है।

प्रोफेसर जोशी कहते हैं कि पिछले 10 साल से मैं यह मानता रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर में नवंबर से लेकर जनवरी तक के महीना में होने वाले अत्यधिक वायु प्रदूषण का कारण हरियाणा या पंजाब की धान की पायली जलने के कारण नहीं है वह मात्र एक छोटा सा कारक है, इसका मुख्य कारण दिल्ली और दिल्ली के चारों ओर का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, कंक्रीट के मकानों का लगातार तेजी के साथ निर्माण होना और पेट्रोल और अन्य ईंधन की गाड़ियों का तेजी से बढ़ना तथा बिजली की बढ़ती हुई खपत रहा है।

पिछले पूरे दशक में हमारी जीवनशैली में बिजली के वातानुकूलित उपकरणों जैसे एयर कंडीशनर और हीटर अत्यधिक उपयोग होना पर्यावरण संतुलन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, साथ ही वातावरण में धूल के के कणों की मात्रा तेजी के साथ बढी है, जंगलों घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन जैसे गैसों की मात्रा बढ़ रही है, इन सब का तात्कालिक प्रभाव पड रहा है, अगले साल जनवरी में समय पर पर्याप्त बर्फ नहीं गिरी तो हमारे हिमालय के क्षेत्र में हिमनदों की बर्फ और कम हो जाएगी, दूसरी ओर गर्मी बढ़ेगी और हिमनदों में जो भी बर्फ बची है वह तेजी के साथ पिघल जाएगी और नदियों में थोड़े समय के लिए जल स्तर तो बढ़ेगा परंतु बाद में स्थाई रूप से जल स्तर कम होता जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ अब तक बर्फबारी के इंतजार में हैं।

फाइल फोटो

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के किसान बहुत निराशा है क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी उतनी ही सेब और अन्य फलों तथा सब्जियों की पहाड़ों में ज्यादा उपज होगी वहीं बारिश न होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में सरसों गेहूं की फसल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अरावली पर्वतमाला से छेड़छाड़ की गई तो और भयानक होंगे हालात

प्रोफेसर बीडी जोशी कहते हैं कि आज पर्यावरण को लेकर हालत बहुत खराब है, स्थिति यह है कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए अरावली पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखला को भी पर्वत श्रृंखला मानने को तैयार नहीं है। और यदि अरावली पर्वतमाला से छेड़छाड़ की गई तो उसका प्रभाव दिल्ली सहित सीधे-सीधे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर पड़ेगा, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में भी गर्मी बढ़ेगी और हिमनद तेजी से पिघलेंगे।

विरासत के जरिए गणित का पाठ पढ़ाएगा एनसीईआरटी

सुशील राघव

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आठवीं के विद्यार्थियों को भारतीय विरासत के माध्यम से गणित का पाठ पढ़ाएगा। परिषद ने हाल ही में आठवीं कक्षा के लिए गणित की दूसरी पुस्तक 'गणित प्रकाश' भाग दो जारी की है जिसमें भारतीय विरासत के कई उदाहरणों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं इस पुस्तक में विद्यार्थियों को समझाने के लिए रोजमर्रा के ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

पुस्तक की प्रस्तावना में कहा गया है कि अलग-अलग अवधारणा के लिए संदर्भ देते समय भारतीय विरासत का भी ध्यान रखा गया है। विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध गणितीय विरासत और गणित में इसके वैश्विक योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए समस्या-समाधान दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में पुस्तक में भारतीय गणितज्ञों के योगदान को भी शामिल किया गया है। पुस्तक में पहला अध्याय 'भिन्न' के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि 'दशमलव भिन्न' शुरू होने से बहुत पहले, दसवें, बीसवें और सौवें हिस्से में गणना के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। 'प्रति सौ' का विचार ईसा पूर्व चौथी सदी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इस अध्याय में विद्यार्थियों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की गणना आदि के बारे में भी बताया गया है।

पहल

पुस्तक का दूसरा अध्याय 'बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय' पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि बौधायन, जो एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे (लगभग 800 ईसा पूर्व), इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रमेय को इस सामान्य रूप में और असल में आधुनिक रूप में बताया। उन्होंने सदियों पहले अपने 'शुल्बसूत्र' ग्रंथों में उस सिद्धांत का वर्णन किया। इस प्रमेय को ग्रीक दार्शनिक-गणितज्ञ पाइथागोरस (लगभग 500 ईसा पूर्व) के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस प्रमेय की तारीफ की और इसका अध्ययन भी किया। इसे अक्सर 'बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय' भी कहा जाता है ताकि सभी को पता चल सके कि किस प्रमेय की बात हो रही है। बौधायन ने बताया कि एक वर्ग का विकर्ण मूल वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुने क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाता है। या समकोण त्रिभुज के लिए आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योग हमेशा विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बौधायन ने वेदियों के निर्माण के लिए व्यावहारिक ज्यामितीय अनुप्रयोग प्रदान किए, जिसमें समकोण त्रिभुजों के लिए प्रमेय भी शामिल है। चौथा अध्याय ज्यामितीय विषयों को लेकर है। इसमें बताया गया है कि गणितीय आकृतियों (फ्रैक्टल्स) का इस्तेमाल इंसानों की बनाई कला में भी लंबे समय से होता आ रहा है। शायद सबसे पुरानी ऐसी गणितीय आकृति भारत के मंदिरों में मिलती हैं। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर में मिलता है, जो लगभग 1025 ईसवी में पूरा हुआ था। वहां एक ऊंची मंदिर की संरचना दिखती है, जो पूरी संरचना की छोटी-छोटी प्रतिलिपियों से बनी है, जिस पर उसी संरचना की और भी छोटी प्रतिलिपि हैं और इसी तरह आगे भी। गणितीय आकृति जैसे पैटर्न मदुरै, हम्पी, रामेश्वरम, वाराणसी और कई अन्य मंदिरों में भी मिलते हैं। पुस्तक में अंतिम और सातवां अध्याय 'क्षेत्रफल' पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि 'शुल्बसूत्र' में हमें क्षेत्रफल के विषय पर कई दिलचस्प समस्याएं मिलती हैं। 'शुल्बसूत्र' वेदियों (धार्मिक मंच) के निर्माण से भी संबंधित है।

आठवीं कक्षा की नई किताब में पैटर्न को समझने के लिए भारत के प्राचीन मंदिरों का उदाहरण लिया गया है। नई किताब में बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय शामिल किया गया है। यह प्रमेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बौधायन (करीब 800 ईसा पूर्व) की देन है, जो पाइथागोरस से सदियों पहले था।

सूर्य घर योजना : नव वर्ष में सौर ऊर्जा से एक करोड़ घर रोशन होंगे

पंकज रोहिला

देश में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (पीएमएसजी) के तहत एक करोड़ घरों तक यह योजना पहुंचेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत आम जनता को सस्ती दरों पर सौर उपकरण उपलब्ध कराना है ताकि अधिक से अधिक कार्बन तत्व में कमी लाई जा सके। योजना में आसानी से उपभोक्ता को केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता की मदद मिल सके। इसके लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक सहायता से जोड़ दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

लक्ष्य

दो साल में इस तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय को कड़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि कुल एक करोड़ के लक्ष्य से अभी भी मंत्रालय साढ़े अस्सी लाख यूनिट के लक्ष्य से पीछे है। सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली दी जा रही है और इस योजना का लाभ लेकर उपभोक्ता अपना हर साल का बिजली बिल कम कर सकते हैं। इस योजना में तीन से पांच किलोवाट के उपकरण लगाए जाते हैं, जोकि एक परिवार की बिजली की खपत को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। एक रपट के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह तक कुल 19,45,758 घरों में सोलर उपकरण लगाए गए हैं। जिससे कुल 24,35,196 परिवारों को लाभ हुआ है। इस योजना जुड़े हैं और इन परिवारों का मासिक बिजली बिल शून्य दर्ज किया गया है।

योजना के तहत अब तक 13926 करोड़ रुपए की सहायता उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है और 8.3 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 75021 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। देश में करीब-करीब सभी राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है और नए प्रावधानों की मदद से योजना को और अधिक तेजी लागू किया जा सकेगा। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक के मुताबिक पीएमएसजी योजना एक मांग आधारित योजना है और देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय बिजली कंपनी (डिस्काम) से जुड़ा कनेक्शन है, वे इस योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं।

नए प्रावधानों को आम जनता के लिए आसानी से इस योजना से जुड़ने के लिए किए गए हैं। सरकार इस योजना के लिए उपभोक्ता को राष्ट्रीय बैंकों से रेपो दर और वर्तमान में 5.76 प्रतिवर्ष के रियायती ब्याज दर पर दस वर्ष की अवधि के साथ फ्री लोन देती है। इस योजना के तहत आम जनता को अधिकतम 78 हजार रुपए की मदद की जाती है, जोकि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जाती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन की एक बिजली उत्पादन दर तय की है, जिसके आधार पर ही पहले आने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त योजना को तेजी से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए समय- समय पर योजना की समीक्षा भी मंत्रालय स्तर पर की जा रही है।

योजना में आसानी से उपभोक्ता को केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता की मदद मिल सके। इसके लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक सहायता से जोड़ दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मौज-मस्ती

गुलमर्ग में मंगलवार को बर्फ में मौज मस्ती करते पर्यटक।

एआइ एजेंट बने हकीकत, 2026 में चुनौतियां बरकरार

जनसत्ता विशेष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में 2025 एक निर्णायक मोड़ के रूप में उभरा, जब शोध प्रयोगशालाओं और प्रोटोटाइप तक सीमित प्रणालियां रोजमर्रा के औजारों के तौर पर सामने आने लगीं। इस बदलाव के केंद्र में एआइ एजेंटों का उदय रहा। ऐसी एआइ प्रणालियां जो अन्य साफ्टवेयर टूल का उपयोग कर सकती हैं और स्वायत्त रूप से काम कर सकती हैं। हालांकि एआइ पर 60 से अधिक वर्षों से शोध हो रहा है और 'एजेंट' शब्द लंबे समय से प्रचलन में है, लेकिन 2025 वह साल रहा जब यह अवधारणा डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के लिए ठोस रूप में सामने आई।

तकनीक

एआइ एजेंट सिद्धांत से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे का हिस्सा बने और बड़े भाषा माडल्स के साथ लोगों की बातचीत का तरीका बदल दिया, जो चैटजीपीटी जैसे चैटबाट्स को शक्ति देते हैं। 2025 में एआइ एजेंट की परिभाषा में भी बदलाव आया। अकादमिक दृष्टि से 'देखने, सोचने और कार्रवाई करने' वाली प्रणालियों से हटकर, एआई कंपनी एंथ्रापिक ने इसे ऐसे बड़े भाषा माडल के रूप में परिभाषित किया जो साफ्टवेयर टूल का उपयोग कर सकें और स्वायत्त कार्रवाई कर सकें। हालिया बदलाव इन माडलों की 'एक्शन क्षमता' का विस्तार है। टूल्स का इस्तेमाल, एपीआइ काल करना, अन्य प्रणालियों से समन्वय और स्वतंत्र रूप से कार्य पूरे करना। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। 2024 के अंत में एंथ्रापिक द्वारा माडल कान्टेक्स्ट प्रोटोकाल जारी किया गया, जिसने डेवलपर्स को बड़े भाषा माडलों को बाहरी टूल्स से मानकीकृत तरीके से जोड़ने की सुविधा दी। इसके साथ ही 2025 को एआइ एजेंटों का वर्ष बनने का आधार तैयार हुआ।

प्रकृति आधारित समाधान से साफ होंगे यमुना में गिरने वाले छोटे नाले

राकेश शर्मा

यमुना को दूषित कर रहे दिल्ली के छोटे नालों को प्रकृति-आधारित समाधान से साफ किया जाएगा। इस परियोजना के तहत नालों में बह रहे कच्चे सीवेज को यमुना में जाने से पहले उसी स्थान पर प्राकृतिक तरीके से उपचारित करने का लक्ष्य है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक राजीव मित्तल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक में मंजूरी दी गई। अधिकारियों की मानें, तो पिछले तीन वित्त वर्षों में यमुना नदी को स्वच्छ रखने में करीब 5536 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का उच्च स्तर पर है।

कवायद

इस समस्या के निपटान के लिए बैठक में शास्त्री पार्क, गोशाला और कैलाश नगर/रमेश नगर नालों के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान पर आधारित पर्यावरण-अनुकूल परियोजना को मंजूरी दी गई। इस तकनीक में प्रकृति की स्वच्छता क्षमता का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले नालों में चट्टान आधारित छन्नी लगाए जाएंगे। जिनमें अलग-अलग आकार के पत्थरों की परतें होंगी। इनके माध्यम से बहता पानी धीमा हो जाएगा और ठोस कण, गाद तथा कचरा नीचे बैठ जाएगा। पत्थरों की सतह पर विकसित होने वाले सूक्ष्मजीव जैविक प्रदूषकों को तोड़ने में मदद करेंगे। इसके बाद नालों में पत्थर की चिनाई से बने छोटे रुकावट और चेक बांध बनाए जाएंगे। इससे पानी कुछ समय के लिए ठहरता है। यह अवसादन को बेहतर बनाकर पानी में घुली आक्सीजन का स्तर को बढ़ाएगा। यह प्रक्रिया पानी में दुर्गंध कम करने और जल गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी।

इसके बाद जल पौधों का उपयोग होगा। इसमें टाइफा, कैना और रीड्स जैसे पौधे नाले में लगाए जाएंगे। यह नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे हानिकारक तत्वों को अवशोषित करेंगे। साथ ही पौधों की जड़ों में रहने वाले लाभकारी बैक्टीरिया गंदगी को प्राकृतिक रूप से विघटित कर देंगे। यह पूरी प्रणाली बिना बिजली और रसायनों के काम करती है। इस परियोजना की मदद से न केवल नालों के प्रदूषण को कम किया जा सकेगा बल्कि यमुना नदी के निर्मल और अविरल प्रवाह भी सुनिश्चित हो सकेगा।

पल्ला में मिला पानी साफ : डीपीसीसी द्वारा एएएमसीजी को सौंपी मासिक रपट में यमुना नदी का पानी सितंबर 2025 में पल्ला (दिल्ली में नदी का प्रवेश करने का स्थान) की निगरानी में स्वच्छ नदी स्तर पर पाया गया। यहां जैव-रासायनिक आक्सीजन डिमांड 2.5 मिलीग्राम और घुलित आक्सीजन का स्तर 9.5 पाया गया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वजीराबाद के बाद नजफगढ़ नाले के मिलने से यमुना के पानी का स्तर लगातार खराब होता चला जाता है।

कई परियोजनाएं अधूरी : नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। योजना के तहत यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए एनएमसीजी ने 2243 एमएलडी एसटीपी क्षमता के निर्माण के लिए 6534 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 35 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें से 21 परियोजनाएं पूर्ण हुई, जबकि कई अधूरी हैं।

इस कारण बढ़ रहा यमुना में प्रदूषण

राज्यसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी द्वारा दिए गए एक लिखित उत्तर में बताया गया कि अगस्त 2025 तक यमुना में उपचार के बाद डाले जाने वाले सीवेज में 414 एमएलडी का अंतर, कुछ स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का अभाव, नई परियोजनाओं के पूर्ण होने और सीवेज उपचार परियोजनाओं के उन्नयन में विलंब और ठोस अपशिष्ट उपचार में 4221 टीपीडी का बड़ा अंतर पाया गया।

अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, सात की मौत

यात्रियों को लेकर रामनगर जा रही थी, 10 से ज्यादा घायल

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 30 दिसंबर।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर मंगलवार सुबह जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। एक यात्री बस के खाई में गिर जाने से सात लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए रामनगर और हल्द्वानी के अस्पतालों में भेजा गया है। यह बस अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह छह बजे द्वाराहाट से निकलने के बाद हादसा हुआ।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की जब खबर आई तो पूरे अल्मोड़ा जिले में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी

बस अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह छह बजे द्वाराहाट से निकलने के बाद हादसा हुआ। संतुलन बिगड़ जाने से यह बस गहरी खाई में गिर गई।
मोदी ने गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जान-माल की हानि बहुत दुखद है।

मच गई और राहत-बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा भिकियासैंण-विनायक-जालली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास हुआ।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है। आपदा अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि राहत-बचाव कार्य तेजी से किए गए और घायलों को तुरंत इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस हादसे में हुई जान-माल की हानि बहुत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो।

वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के भिकियासैंण-विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केंद्रों में भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की सतत निगरानी की जा रही है और मैं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

जिला प्रशासन अल्मोड़ा के अनुसार मृतकों में 5 पुरुष 2 महिला शामिल हैं। सभी की पहचान हो चुकी है। मरने वालों में गोविंद बल्लभ (30), पार्वती देवी (75), सूबेदार नंदन सिंह (65), तारा देवी (50), गणेश (25) और उमेश (25) शामिल है।

प्रधानमंत्री से मिले अधीर रंजन, मतुआ समुदाय के मुद्दे पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में बांग्लाभाषी लोगों पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बांग्लाभाषी होना, बांग्लादेशी होना नहीं है लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में बंगाली बोलने वाले मजदूरों को शक की नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने इस बैठक में मतुआ समुदाय की समस्याओं को उनके समक्ष उठाया। और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

अधीर रंजन ने कहा कि इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा होने की आशंका है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि कई जगह पर इन लोगों से मारपीट की गई है और जेल या पुर्नवास केंद्र (डिटेंशन सेंटर) तक भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ये मजदूर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और मेहनत से गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जवाब के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह स्थिति पर नजर रख रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने वाली इस मुलाकात के राजनीतिक महत्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली आया था और इत्तेफाक से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। पत्र में बताया गया है कि बांग्लाभाषी लोगों का एकमात्र अपराध यह है कि वे बांग्ला भाषा में बात करते हैं जिसके कारण संबंधित प्रशासन अक्सर उन्हें पड़ोसी बांग्लादेश के लोग समझ लेता है और उन्हें घुसपैठिया मानकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करता है। पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह भेदभाव, हिंसा और देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाएं।

'वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन' ने जारी की वार्षिक रपट

मौसम की घटनाओं ने असमानता को उजागर किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दुनिया वर्ष 2025 के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है, लेकिन यह वर्ष मौसम की चरम घटनाओं के लिहाज से ठीक नहीं रहा है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में मौसम बहुत खराब रहा, जिससे लू, सूखा, तूफान और जंगल की आग जैसी घटनाएं और भी बदतर हो गईं।

इसकी वजह से लाखों लोग 'अनुकूलन की सीमाओं' के करीब पहुंच गए। ये परिस्थितियां कमजोर समूह और हाशिए पर पड़े समुदायों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। यह तथ्य 'वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन' की वार्षिक रपट में सामने आया है। इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे नतीजों से बचने के लिए जीवाश्म ईंधन की खपत में तेजी से कमी लाने की अपील की है। रपट के अनुसार, पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से लू काफी तीव्र हो गई हैं, और अब कुछ घटनाओं के होने की संभावना साल 2015 की तुलना में 10 गुना अधिक हो गई है।

साल 2025 में जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में खराब मौसम को बढ़ावा दिया, जिससे लू, सूखा, तूफान और जंगल की आग जैसी स्थितियां और भी बदतर हो गईं। इससे लाखों लोगों को अनुकूलन की सीमाओं के करीब धकेल दिया। पूरे साल वैश्विक तापमान बहुत अधिक रहा। हालांकि, अल नीनो दक्षिणी दोलन जैसे प्राकृतिक रूप से ठंड बढ़ाने वाली मौसम प्रणालियां भी इस दौरान मौजूद रहीं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण साल 2025 रेकार्ड पर सबसे गर्म वर्षों में से एक बन गया।

रपट के मुताबिक बेहद खराब मौसम कमजोर समूह और हाशिए पर पड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है। यह असमानता जलवायु विज्ञान में भी देखी जाती है, जहां आंकड़ों की कमी और जलवायु माडल में सीमाओं के कारण 'वैश्विक दक्षिण' की घटनाओं के विश्लेषण में दिक्कत आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की कमजोरी और जोखिम को कम करने से उनकी जान बचती है, लेकिन कुछ भयानक घटनाओं ने दिखाया कि मौसम बदलाव पहले से ही 'अनुकूलन की सीमाओं' के करीब धकेल रहा है।

समर्थन दक्षिण मुंबई निकाय चुनाव में शिवसेना (उद्धव और मनसे) के समर्थकों ने नामांकन करते समय दिखाई एकजुटता।

एंजेल चकमा हत्याकांड मामले में जांच के लिए एसआइटी गठित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड में चौतरफा दबाव के बीच देहरादून की पुलिस ने मंगलवार को मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन कर दिया और साथ ही कहा कि मामले की अब तक की जांच में नस्लीय दुर्व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि पुलिस हत्याकांड में शामिल फरार मुख्य आरोपी नेपाल के यज्ञराज अवस्थी को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुकी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने अवस्थी पर घोषित 25 हजार रुपए के इनाम को भी बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि नौ दिसंबर को हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर लिए हैं और पूरी वारदात भीड़भाड़ वाली जगह पर शाम सवा छह बजे के बाद 40-50 सेकंड के भीतर हुई। उन्होंने कहा, 'घटना के पीछे की पूरी सच्चाई एंजेल पर चाकू से वार करने वाले मुख्य आरोपी अवस्थी की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगी।'

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी और पीड़ित पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते थे और पूरी घटना 'इन द हीट आफ द मोमेंट' में हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या वारदात में शामिल चाकू बरामद हो गया है, एसएसपी ने कहा कि अवस्थी ने पास में खड़ी अंडे की ठेली से उसका चाकू उठाकर एंजेल पर वार किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। एसएसपी ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित खबरों में घटना को नस्लीय दुर्व्यवहार से जोड़े जाने को गलत बताया।

पंजाब विधानसभा में जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित

'वीबी-जी राम जी' कानून के खिलाफ अभियान के संदर्भ में मंत्री शिवराज ने कहा

पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाना संविधान के विरुद्ध

चंडीगढ़, 30 दिसंबर (ब्यूरो)।

पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में 'वीबी-जी राम जी'कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया।

यह प्रस्ताव पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया। लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद, यह प्रस्ताव प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। सत्ताधारी आप और विपक्षी कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया, जबकि भाजपा के सदस्य मतदान से दूर रहे।

जब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान बोल रहे थे तो कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने उन्हें कई बार टोका। विधानसभा अध्यक्ष ने खैहरा को सदन से बाहर निकालने के लिए कह दिया। इससे कांग्रेस विधायक भड़क गए और मुख्यमंत्री के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को बोलने का मौका दिया।

प्रस्ताव पेश करते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण), या वीबी-जी राम जी अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों को बुरी तरह प्रभावित करेगा, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनेरगा) पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी 'वीबी-जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने को संविधान और संघीय ढांचे की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया। साथ ही कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को मानना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

भोपाल में अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में चौहान ने पंजाब विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये 'अंध विरोध' की राजनीति है और कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में कोई कानून बनती है तो विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना हमारे संवैधानिक ढांचे की भावना के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या यह उचित होगा कि राज्य के कानून के खिलाफ जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करने लगे? उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा पारित कानूनों को मानना केंद्र और सभी राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और विधानसभा में कुछ दल जो कर रहे हैं, वह अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

चौहान ने एक रपट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) सहित कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, लेकिन न तो दोषियों पर कार्रवाई की गई और न ही गबन की गई राशि की वसूली हुई। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 13 हजार 304 ग्राम पंचायतों में से केवल पांच हजार 915 में ही सामाजिक अंकेक्षण हुआ है। उन्होंने कहा कि रपट में करीब 10 हजार 653 वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन इनमें किसी पर कार्रवाई नहीं की गई।

पेज 1 का बाकी

यूपी में मतदाता मसविदा सूची छह जनवरी, अंतिम सूची छह मार्च को

करेगा। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद छह मार्च को अंतिम सूची को जारी किया जाएगा। अब से पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक यह सूची 28 फरवरी को जारी की जानी थी। आयोग दावा था कि राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, इसके बाद ही आयोग ने बिहार में पुनरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू किया था। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान कोई भी मतदाता फार्म 6 भरकर नया नाम जुड़वा सकता है।

इसी प्रकार किसी का नाम कटवाना है तो इसके लिए फार्म सात भरा जा सकता है जबकि फार्म आठ का प्रयोग मतदाता अपने स्थान बदलने की जानकारी दे सकते है। जितने भी आवेदन आएंगे उनका निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण प्रक्रिया 27 फरवरी तक चलेगी। जब निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी, उस समय उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से अधिक बताई गई थी।

आयोग के मुताबिक, पुनरीक्षण आने के बाद जब मतदाता सूची का अगला चरण जब शुरू होगा। तो नए मतदाता फार्म छह भरकर सूची में शामिल हो सकेंगे। आयोग ने सभी नए मतदाताओं से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे आंए। ऐसे मतदाताओं के लिए आयोग ने पर्याप्त संख्या में बूथ स्तर के अधिकारी के पास फार्म उपलब्ध कराएं है, इसके अतिरिक्त आयोग की वेबसाइट पर भी जाकर ये फार्म भरा जा सकते हैं।

आर्थिक वृद्धि के लिए सतत सुधार जरूरी

लिए एजंडा' था। बैठक में मोदी ने वैश्विक स्तर की क्षमताओं के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय एकीकरण हासिल करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया और बजट निर्धारण में 2047 के लिए संकल्प को केंद्रीय रूप से रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक श्रम शक्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाए रखना जरूरी है।

चर्चा के दौरान अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों ने निर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के उपायों पर रणनीतिक सुझाव साझा किए। विशेषज्ञ समूह ने कृत्रिम मेधा (एआइ) की भूमिका को विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने वाला उपकरण बताया और भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना (डीपीआइ) को लगातार बढ़ाने पर भी चर्चा की। घरेलू बचत में वृद्धि, मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए संरचनात्मक बदलावों की गति को तेज करना इस चर्चा के केंद्र में रहा। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा एवं शक्तिकांत दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम और आयोग के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

इसके अलावा कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ भी इस बैठक में मौजूद रहे। इनमें पूर्व सीईए शंकर आचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, एनआर भानुमूर्ति, पूर्व एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल, धर्मकीर्ति जोशी, उमाकांत दास, पिनाकी चक्रवर्ती, इंद्रनील सेन गुप्ता, समीरन चक्रवर्ती, अभिमान दास, राहुल बाजोरिया, मोनिका हलन और सिद्धार्थ सान्याल शामिल थे।

मंत्री ने बंगलुरु में हेलिकाप्टर 'ध्रुव एनजी' को हरी झंडी दिखाई

बंगलुरु, 30 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित अगली पीढ़ी के हेलिकाप्टर 'ध्रुव एनजी' को हरी झंडी दिखाकर पहली उड़ान के लिए रवाना किया। यहां उड़ान भरने से पहले केंद्रीय मंत्री ने हेलिकाप्टर की उन्नत प्रणालियों और विशेषताओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए पायलट के साथ काकपिट में प्रवेश किया।

हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार, 'ध्रुव एनजी' महज 5.5 टन का एक हल्का, दो इंजन वाला और बहु-भूमिका हेलिकाप्टर है, जिसे भारतीय भूभाग की विविध और चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह हेलिकाप्टर भारतीय विमानन इतिहास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है और उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एचएएल के सभी कर्मचारियों, डिजाइनरों और इंजीनियरों से लेकर तकनीशियनों तक को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि एचएएल लंबे समय से रक्षा विभाग के लिए एक प्रमुख संस्थान की तरह काम कर रहा था लेकिन अब यह रक्षा और नागरिक विमानन संस्थान के रूप में विकसित हो रहा है। नायडू ने कहा, 'नागरिक विमानन मंत्री के रूप में यह मेरे लिए विशेष रूप से गर्व का क्षण है।' उन्होंने कहा कि यह विकास स्वदेशी एअरोस्पेस विनिर्माण में भारत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

छोटे उल्लंघन अपराध की श्रेणी से बाहर, अदालतों पर बोझ कम होगा

लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज हो गई है। मोदी ने कहा कि यह बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बदलते स्वरूपों में स्पष्ट है, जिसके लिए तेजी से महत्वाकांक्षी होते समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि और सक्रिय अवसंरचना नियोजन की आवश्यकता है। यह बैठक नीति आयोग में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय 'आत्मनिर्भरता एवं संरचनात्मक रूपांतरण: विकसित भारत का मसविदा था।

प्रधानमंत्री ने बैठक में वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण प्राप्त करने के लिए मिशन-आधारित सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन-आधारित सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की नीति निर्माण और बजट निर्धारण वर्ष 2047 के दृष्टिकोण से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की कि देश वैश्विक कार्यबल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे।

हर साल बजट से पहले ऐसी बैठकें आयोजित की जाती है। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह के पहले सप्ताह में इस बार बजट सत्र होगा, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। इससे पहले भी केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी ही बैठकें आयोजित कर चुकी है।

मंत्रालय इंडिगो उड़ान व्यवधानों पर जांच समिति की रपट का विश्लेषण कर रहा : मंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय वर्तमान में उस समिति द्वारा प्रस्तुत रपट का विश्लेषण कर रहा है जिसने इस महीने की शुरुआत में इंडिगो से जुड़ी व्यापक उड़ान व्यवधानों की जांच की थी। यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'रपट मंत्रालय को सौंप दी गई है। हम रपट का विश्लेषण कर रहे हैं, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से राय ले रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।'

अधिकारियों के अनुसार डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्मणे की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन पांच दिसंबर को उन परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा और आकलन करने के लिए किया गया था जिनके कारण बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधान उत्पन्न हुए। समिति ने शुक्रवार शाम को अपनी रपट सौंप दी थी।

इस महीने की शुरुआत में इंडिगो ने एक ही दिन में 1,600 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं जिसके बाद कई दिनों तक बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द की गईं। पायलटों के आराम संबंधी संशोधित नियमों को लागू करने में अपर्याप्त योजना को व्यवधानों का मुख्य कारण बताया गया।

व्यवधानों के बाद डीजीसीए ने देश की सबसे बड़ी एअरलाइन इंडिगो को अपने शीतकालीन कार्यक्रम में 10 फीसद की कटौती करने का निर्देश दिया और एअरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स और मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) इसिड्रे पोरक्वेरास को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

पांच दिसंबर को समिति के गठन संबंधी आदेश में कहा गया था कि प्रथम दृष्टया स्थिति आंतरिक निगरानी, परिचालन तत्परता और अनुपालन योजना में कमियों को इंगित करती है, जिसके लिए 'स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।' डीजीसीए के आदेश के अनुसार, उसने समय-समय पर एअरलाइन को फ्लाइट ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की समयबद्ध तैयारी के लिए बार-बार निर्देश और अग्रिम अनुदेश जारी किए थे।

आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन अलग नहीं : उपराष्ट्रपति

वरकला, 30 दिसंबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जीवन को अलग नहीं किया जा सकता और यदि आस्था समाज को बेहतर नहीं बना सके तो वह अधूरी रह जाती है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र का निर्माण केवल मशीन और राजमार्ग से नहीं होगा, बल्कि मूल्यों, एकता और प्रेम से होगा। उपराष्ट्रपति ने यह बात तिरुवनंतपुरम के पास वरकला में संत एवं समाज सुधारक श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरि मठ में 93वीं शिवगिरि तीर्थयात्रा की शुरुआत के मौके पर कही। उन्होंने कहा, 'आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जीवन को अलग नहीं किया जा सकता।

भास्कर एक्सक्लूसिव | मप्र कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026 की तैयारी, एक ही लाइसेंस से गांव और शहर में काम कर सकेंगे बिल्डर

अवैध कॉलोनी 45 दिन में हटेगी, दस साल की सजा या 1 करोड़ जुर्माना

अब तक 7 साल तक की सजा और सिर्फ 10 लाख जुर्माना था

अनिल गुप्ता | भोपाल

नगरीय विकास विभाग 'मप्र कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026' लाने की तैयारी में है। इसके लागू होते ही शहर और गांवों में कॉलोनी डेवलपमेंट के नियम एक जैसे हो जाएंगे। नया कानून जहां ईमानदार बिल्डरों के लिए प्रक्रिया आसान करेगा, वहीं दावा है कि अवैध कॉलोनी बनाने वालों के लिए यह कड़ा कानून साबित होगा।

नए कानून के तहत बिल्डर एक ही लाइसेंस से गांव और शहर दोनों में काम कर सकेगा। पांच साल की तय अवधि में कॉलोनी विकसित होने के बाद उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट (कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र) भी 45 दिन में मिल जाएगा। इसमें एक दिन की भी देरी होती है तो डीम्ड परमिशन (स्वतः मंजूर) की व्यवस्था लागू मानी जाएगी। अवैध कॉलोनी बनाने पर अभी 7 साल की सजा या दस लाख जुर्माने का नियम है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 10 साल कैद या एक करोड़ जुर्माना(दोनों भी) किया जा रहा है। पूर्व में दस लाख जुर्माने की व्यवस्था का बिल्डर फायदा उठा लेते थे। राशि चुकाकर बच जाते थे। लेकिन अब उन्हें एक करोड़ रुपए देना होगा। इसके अलावा अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई को भी लोकसेवा गारंटी की तरह लाया जाएगा। यानी 45 दिन के भीतर अवैध कॉलोनी रोकने, हटाने और जब्ती की कार्रवाई हो जाएगी।

▪ लोकसेवा गारंटी में शामिल होगी इसके खिलाफ कार्रवाई

पांच साल की तय अवधि में कॉलोनी का विकास होने के बाद 45 दिन में ही कार्यपूर्ति सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 दिन भी अधिक होने पर डीम्ड मंजूरी होगी

नया एक्ट...

इस तरह होगी कार्रवाई... नोटिस, मोहलत फिर एक्शन

1. पता चलने पर 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।
2. नोटिस में संबंधित को 15 दिन की मोहलत मिलेगी कि खुद उस अवैध निर्माण को हटा लिया जाए।
3. अवधि पूरी होने पर सरकार खुद 15 दिन में हटा देगी, जमीन भी जब्त होगी।

मौजूदा एक्ट से हटेंगी कॉलोनी से जुड़ी धाराएं

नगर पालिका अधिनियम और पंचायत एवं ग्राम स्वराज के मौजूदा अधिनियम की कुछ धाराओं को शामिल करके नया एक्ट बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नया एक्ट लागू होने के बाद पुराने अधिनियम से वो धाराएं हट जाएंगी जो कॉलोनी डेवलपमेंट और कॉलोनाइजर से जुड़ी हैं। इन्हें नए एक्ट में रखने के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। नए अधिनियम में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का बड़ा अधिकार कलेक्टरों के हाथ में जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में कमिश्नर सक्षम होंगे, जबकि बाकी क्षेत्र में कलेक्टरों को कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। वे एसडीएम को भी सक्षम अधिकार दे सकते हैं। ताकि निर्णय तुरंत हो सके।

अभी अवैध कॉलोनियों की स्थिति

सरकारी रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों के अनुसार, मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या 8000 से अधिक हो चुकी है। सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2016 तक बनी 6,077 कॉलोनियों को वैध (नियमित) करने की प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में कट ऑफ डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया। इससे लगभग 2500 अतिरिक्त कॉलोनियां इस सूची में जुड़ गईं। वर्ष 2025 तक 16 नगर-निगमों के क्षेत्रों में ही लगभग 4,000 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग की पहचान की गई है। यदि सभी नगरीय निकायों (कुल 413) को शामिल किया जाए, तो यह आंकड़ा 8,000 पार होगा।

जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की परीक्षा 4 को, व्यापमं ने अपलोड किए प्रवेश पत्र

रायपुर | जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा 4 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में नियुक्ति के लिए हो रही भर्ती परीक्षा दो जिलों में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट www.vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले जाना होगा। प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लेना होगा।

नवा रायपुर में अब नहीं खुलेगा वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल

नवा रायपुर में 20 एकड़ में फैले भव्य निर्माणाधीन स्कूल को निजी हाथों में देने की तैयारी। फोटो- सुधीर सागर

रायपुर में 50 करोड़ से बना भवन अब निजी हाथों में देने की तैयारी

भास्कर एक्सक्लूसिव

सुधीर उपाध्याय | रायपुर

नवा रायपुर में निर्माणाधीन वर्ल्ड क्लास रेसीडेंशियल स्कूल, जिसे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाना था, अब निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग स्तर पर कुछ निजी ग्रुप से बातचीत चल रही है। इस पर अब तक सरकार करीब 50 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

राज्य सरकार ने 2022 में इसके निर्माण की घोषणा की थी। पहले चरण का 80 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। अब स्कूल के संचालन मॉडल को लेकर मंथन हो रहा है। हाल ही में संचालन समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में स्कूल संचालित हो रहे हैं। लिहाजा इसे भी पारंपरिक सरकारी मॉडल पर चलाने की बजाए निजी हाथों में सौंपना चाहिए।

इस संस्थान के संचालन के लिए बनी है समिति

वर्ल्ड क्लास स्कूल की घोषणा 2022 में हुई। इसके संचालन के लिए एक समिति बनाई गई। इसमें तय किया गया कि मुख्यमंत्री इस उत्कृष्ट विद्यालय समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा समिति में सदस्य सचिव एवं अन्य सात सदस्य भी होंगे। पिछले दिनों इस समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूल का संचालन बड़े निजी ग्रुप को दें। जानकारी के मुताबिक कई बड़े निजी ग्रुप ने स्कूल संचालन के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क भी किया है।

राष्ट्रीय स्तर की संस्था को सौंपे जाने का भी है विकल्प

यह चर्चा भी सामने आ रही है कि स्कूल भवन को किसी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्था को लीज पर दिया जा सकता है। इन विकल्पों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से यहां पारंपरिक सरकारी स्कूल का संचालन नहीं होगा। आने वाले दिनों में इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

▮ स्कूल के पहले चरण का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग से हैंडओवर को लेकर जानकारी प्राप्त होने के बाद इसे संबंधित संस्था को सौंप दिया जाएगा। **-चंदन कुमार,** सीईओ, एनआरडीए

छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल... स्टाफ की कमी से जूझ रहे हमर अस्पताल, ड्रेसिंग के लिए भी भेज रहे बड़े अस्पताल

भास्कर न्यूज | रायपुर

राजधानी में आम लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए हमर अस्पताल का बुरा हाल है। हालात ये हैं कि कई केंद्रों में ड्रेसिंग जैसी बुनियादी सुविधा भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

मरीज जब छोटे-मोटे घाव, चोट या फॉलोअप के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं तो उन्हें सीधे मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी जा रही है। इससे न केवल मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की योजना थी कि शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कर छोटे इलाज, ड्रेसिंग, जांच और दवाइयों की सुविधा मोहल्ले और वार्ड स्तर पर दी जाए, ताकि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों पर दबाव कम हो। लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट दिखाई दे रही है। स्टाफ की भारी कमी, संसाधनों का अभाव और व्यवस्थागत लापरवाही के कारण राजधानी के कई स्वास्थ्य केंद्र केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं।

इलाज नहीं मिला

केस- 1

उरकुरा निवासी राकेश मिश्रा ने बताया कि फैक्ट्री में उनके हाथ में एक मशीन गिर गई थी। उनका अंगूठा सूज गया है। इसके साथ ही उसमें पानी भर गया है। इसे निकलवाने और इसका इलाज करवाने जब वे भनपुरी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि यहां ड्रेसर नहीं है। उन्हें अंबेडकर अस्पताल जाने कह दिया गया।

सामान ही नहीं था

केस- 2

भाठागांव निवासी कुछ दिन पहले बाइक से गिर गए थे। पैर में गहरी चोट आने के बाद वे पास के भाठागांव के हमर अस्पताल पहुंचे। वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि ड्रेसिंग का सामान उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर भी नियमित नहीं हैं। रमेश को सीधे मेडिकल कॉलेज रायपुर जाने की सलाह दे दी गई।

सुविधाओं में भी पीछे

रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमर अस्पताल के रूप में डेवलप किया गया है। लेकिन ये केंद्र सुविधाओं के मामले में अब भी पीछे ही हैं।

▮ जिस सेंटर की बात कर रहे हैं, वहां हो सकता है स्टाफ ना हो, लेकिन ड्रेसिंग तो हर केंद्र में करने के आदेश दिए हैं। लेकिन इसकी जांच करवाता हूं।
- डॉ मिथिलेश चौधरी, सीएमएचओ, रायपुर।

थाने का फर्जी सील-लेटर पेड बना कर बैंक से निकाल लिए 31 लाख रुपए

भास्कर न्यूज | सारंगढ

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला महाठग शिवा साहू एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सरसींवा थाने की सील और लेटरपैड फर्जी तरीके से तैयार कर बैंकिंग सिस्टम को गुमराह करने का है। थाना सरसींवा के अनुसार शिवा साहू ने थाना सरसींवा के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार कराया। नकली दस्तावेज व थाना के नाम पर आवेदन, लेटरपेड व सील को जमानत से जुड़े दस्तावेजों के साथ संलग्न कर बैंक को दर्शाया कि होल्ड अकाउंट खोलने की अनुमति पुलिस ने दी है। इसके बाद बैंक से अपने साथी व तथाकथित प्रेमिका व उसके पिता के नाम से लाखों रुपए निकाले। फर्जी दस्तावेजों को लेकर शिवा साहू खुद बैंक पहुंचा और रकम निकाली। उसने डिगम जोल्हे के नाम पर 10 लाख रुपए, ऋतु साहू और उसके पिता चन्द्रहास साहू के नाम पर 21 लाख रुपए की निकासी एचडीएफसी बैंक से कराई।

हमारी हरियाली के हत्यारे कौन? • 24 मई को एक ही दिन में दी गईं 237 मंजूरियां

जिस बैठक में मस्तीपुरा में खनन को मंजूरी, उसी में 236 और को हरी झंडी मिली, इनकी जांच कब?

हरेकृष्ण दुबोलिया | भोपाल

भोपाल के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के मस्तीपुरा गांव में जिस सरकारी जमीन पर घना जंगल है, वहां खनन की मंजूरी मप्र स्टेट एनवायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) की बैठक को बायपास करके दी गई। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद यहां पेड़ों की कटाई पर रोक तो लग गई, लेकिन अब पूरी पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दरअसल, जिस दिन मस्तीपुरा में खनन की मंजूरी दी गई, उसी दिन यानी 24 मई 2025 को प्रदेश में कुल 237 खदानों को डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) जारी की गई। नियमों के मुताबिक, किसी भी खनन परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले स्पेशल एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी तकनीकी जांच करती है। इसके बाद सिया की बैठक में विस्तृत अप्रैजल अनिवार्य होता है। लेकिन इन 237 मंजूरियों से पहले करीब 45 दिनों तक सिया की बैठकें नहीं बुलाई गईं। इसके बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव पर्यावरण नवनीत मोहन कोठारी के अनुमोदन पर एप्को के अस्थायी कार्यकारी निदेशक आर. उमा महेश्वरी, जो तब सिया के पदेन सदस्य सचिव भी थे, ने एक ही दिन में 237 डीम्ड ईसी जारी कर दीं।

इस प्रक्रिया पर सिया के तत्कालीन चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान व नवनीत कोठारी के बीच विवाद भी हुआ। बाद में सरकार ने कोठारी और महेश्वरी को उनके पदों से हटा दिया। अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विजिलेंस टीम मामले की जांच कर रही है, पर कोई सार्वजनिक समीक्षा नहीं आई है।

जहां पूरा जंगल, वहां दो प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 53 पेड़ बताए, कहा- इनमें भी सिर्फ 9 कटेंगे

28 दिसंबर को प्रकाशित

मस्तीपुरा के खसरा नंबर-2 की जिस सरकारी जमीन पर हजारों हरे-भरे पेड़ हैं, वहां मुरम-कोपरा खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी आवेदनों में एक प्रोजेक्ट में सिर्फ 10 और दूसरे में 43 पेड़ दर्शाए गए। दावा भी किया गया कि या तो एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, या फिर सिर्फ 9 पेड़ काटे जाएंगे।

पूर्व सिया चेयरमैन बोले- तथ्य छिपाकर दी मंजूरी

▮ मस्तीपुरा की खसरा नंबर-2 की खदानों का मामला जांच और मूल्यांकन के लिए सिया के पास आया ही नहीं। तत्कालीन मेंबर सेक्रेटरी व प्रमुख सचिव पर्यावरण ने कानून के खिलाफ जाकर डीम्ड ईसी जारी की, जिससे माफिया व अफसरों की मिलीभगत सामने आती है। पूर्व खनन निदेशक मस्तीपुरा की सैद्धांतिक मंजूरी रद्द कर चुके थे। जांच होती तो पर्यावरणीय मंजूरी रद्द होना तय था। ऐसे 237 मामलों में तथ्य छिपाकर, चुनिंदा तरीके से डीम्ड ईसी दी गईं।' **-शिव नारायण सिंह चौहान,** तत्कालीन सिया चेयरमैन

एसआईआर • 5 जनवरी से 1.16 लाख मतदाताओं के दावे-आपत्तियों पर होगी सुनवाई

नो-मैपिंग वोटरों को नोटिस देना शुरू... वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए तो होगी जेल

भास्कर न्यूज | भोपाल

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का ड्राफ्ट रोल जारी होने के दस दिन बाद 5 जनवरी से जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण-पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों के नो-मैपिंग वाले 1 लाख 16 हजार 925 मतदाताओं की सुनवाई शुरू होगी। इसके लिए सोमवार से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस तामील होने के बाद मतदाता अपने दस्तावेज सीधे बीएलओ को दे सकेंगे। बीएलओ मौके पर ही दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, जिससे तय तारीख पर सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के अनुसार, नोटिस में 5 जनवरी से सुनवाई की तारीख अंकित है और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। मंगलवार से नोटिस तामीली का काम तेज किया जाएगा। नोटिस पर संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा, ताकि मतदाता सीधे संपर्क कर सकें।

निर्वाचन आयोग ने नो-मैपिंग वाले वोटरों और नाम कटने के बाद स्पष्ट निर्देश है कि बिना प्रमाण के किसी का नाम मतदाता सूची में न जोड़ा जाए। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें नाम जुड़वाने के लिए जिले से ही जारी हुए 12 वैध दस्तावेज देने होंगे। इन दस्तावेजों की जांच पांच दिन में होगी। इस जांच पर निगरानी, मदद का जिम्मा खुद कलेक्टर का होगा। दस्तावेजों की जांच उसी विभाग से कराई जाएगी, जिसने उन्हें जारी किया है।

झूठी जानकारी देने पर जेल-जुर्माने का प्रावधान

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए झूठी जानकारी देना बीएनएस की धारा 217 के तहत संज्ञेय अपराध है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर जेल हो सकती है। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत भी दंडनीय है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे मामलों में ईआरओ कार्रवाई के लिए सक्षम होंगे।

बस्तर: कांग्रेस विधायक की पत्नी सुमित्रा बाथरूम में लहुलुहान मिलीं

जगदलपुर | बस्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल अपने घर के बाथरूम में मंगलवार की सुबह लहुलुहान मिलीं। उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सुमित्रा अभी खतरे से बाहर हैं। एएसपी महेश्वर नाग ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विधायक की पत्नी मानसिक रूप से परेशान थीं। इसी कारण उन्होंने खुद को घायल कर लिया। मामले में तेजी से जांच जारी है। अभी जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार सुबह सुमित्रा बाथरूम गई थीं। इसके बाद जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आईं तो परिजन बाथरूम में गए और देखा कि वे घायल हालत में पड़ी हुई हैं।

देश की चुनिंदा पुलिस एकेडमी, विवि में करेंगे अध्ययन, रिसर्च पेपर तैयार करेंगे

न्यू क्रिमिनल लॉ पर रिसर्च के लिए एक साल की स्टडी लीव लेंगे परिवहन आयुक्त

भास्कर न्यूज | भोपाल

मप्र कैडर के 1998 बैच के आईपीएस और मौजूदा परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा अप्रैल-2026 से एक साल की स्टडी लीव पर जाएंगे। उन्होंने सोमवार को राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय को आवेदन भेज दिया है।

यह स्टडी लीव देश में जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन, उसकी प्रक्रिया और उससे जुड़ी नई पद्धतियों को समझने के मकसद से ली जा रही है। शर्मा देश की चुनिंदा पुलिस अकादमियों व विश्वविद्यालयों में जाकर अध्ययन करेंगे। अपने अनुभवों के आधार पर रिसर्च पेपर तैयार करेंगे। अभी शर्मा के पास परिवहन आयुक्त की अहम जिम्मेदारी है। उनके स्टडी लीव पर जाने से पहले विभागीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शर्मा के सेवानिवृत्त होने में 9 साल बचे हैं।

22 दिसंबर को प्रकाशित खबर।

डिजिटल एविडेंस पर सीखने की बड़ी संभावना

मौजूदा समय में डिजिटल एविडेंस कैप्चर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैधानिकता और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिसिंग में बड़े बदलाव हो रहे हैं। साथ ही नए क्रिमिनल लॉ में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका भी काफी बढ़ी है। ऐसे दौर में वरिष्ठ आईपीएस अफसर का इस विषय पर गहन अध्ययन करना राज्य पुलिस के लिए भी उपयोगी माना जा रहा है।

भास्कर खास | प्राइवेट होटल का किराया 25 से 30 फीसदी तक बढ़ा... गोवा, मुंबई आदि में भी ऐसे ही हालात

न्यू ईयर पर जेब पर भारी पर्यटन: भोपाल से उज्जैन-ओंकारेश्वर-पचमढ़ी टैक्सी किराया ₹1000 तक महंगा... एमपी टूरिज्म के सभी कमरे फुल

अनुराग शर्मा | भोपाल

नववर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही है। भोपाल से उज्जैन, ओंकारेश्वर और पचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। आम दिनों की तुलना में प्रति ट्रिप किराया करीब 1000 रुपये तक अधिक वसूला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन सभी स्थलों पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीटीडीसी) के होटल पूरी तरह फुल हो चुके हैं।

आमतौर पर भोपाल से उज्जैन का टैक्सी किराया 2000 से 2500 रुपए, पचमढ़ी के लिए 2200 से 2500 रुपए और ओंकारेश्वर के लिए 2800 से 3200 रुपए के बीच रहता है। लेकिन नववर्ष के पीक सीजन में यही किराया बढ़कर उज्जैन और पचमढ़ी के लिए 3000 से 3500 रुपए,ओंकारेश्वर के लिए 3800 से 4200 रुपए तक पहुंच गया है। टैक्सी संचालकों का कहना है कि नववर्ष पर मांग बढ़ने, सीमित वाहनों की उपलब्धता और लगातार ट्रिप के दबाव के कारण किराया बढ़ाना मजबूरी है।

पचमढ़ी में सबसे ज्यादा दबाव

पचमढ़ी में पर्यटकों का सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। यहां एमपीटीडीसी की 11 यूनिट्स हैं, जिनमें 180 से 190 कमरे हैं। नववर्ष को लेकर ये सभी कमरे फुल हो चुके हैं। निजी होटल भी 60% तक बुक हैं। आम दिनों में जहां एक कमरे का किराया 4500 से 5000 रुपये रहता है, वहीं नए साल में किराया 6500 से 7000 तक पहुंच गया है।

उज्जैन-ओंकारेश्वर में भारी भीड़, नहीं मिल रही कमरों की बुकिंग

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां एमपीटीडीसी के तीन प्रमुख होटल, जिनमें 100 से अधिक कमरे हैं, पूरी तरह भर चुके हैं। निजी होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे सीमित बचे हैं और किराए में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी तरह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहां एमपीटीडीसी के सीमित होटल और करीब 50 से 60 कमरे पहले ही फुल हो चुके हैं।

अन्य धार्मिक स्थलों पर भी परेशानी

महेश्वर और मैहर माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी ठहरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई श्रद्धालुओं को मजबूरी में कटनी और आसपास के कस्बों में रुकना पड़ रहा है। वहीं भोपाल से नए साल के पहले दिन सीहोर के गणेश मंदिर, भोजपुर और सलकनपुर जाने वालों की भीड़ के कारण यहां के होटल और लॉज भी बुक बताए जा रहे हैं।

प्रदेश के बाहर भी यही हाल

गोवा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी नए साल को लेकर यही स्थिति है। फ्लाइट और होटल किराए में तेज बढ़ोतरी के चलते कई लोग यात्रा में बदलाव करने को मजबूर हैं।

स्लॉटर हाउस के बाहर मिले चिकन के टुकड़े

पीसीबी और निगम अफसरों ने की स्लॉटर हाउस की जांच

भास्कर न्यूज | भोपाल।

मेट्रो डिपो के पास स्थित स्लॉटर हाउस के आसपास इलाके में बदबू आने और नाले में लाल पानी बहने की शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से जांच की। जांच के दौरान स्लॉटर हाउस के बाहर चिकन के अवशेष मिले हैं, जो यहां रहने वाले व्यवसायियों के बताए जाते हैं। पीसीबी के अफसरों ने कहा कि स्लॉटर हाउस में सभी मशीनें चालू हालत में मिली हैं। पीसीबी यहां लगातार जांच करेगा। उधर, कुरैशी समाज के लोगों ने मशीनों से पशुओं के काटे जाने का विरोध किया। सोमवार को स्लॉटर हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कहा कि इससे हमारा व्यवसाय खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि नए नियमों के अनुसार अब स्लॉटर हाउस के बाहर स्लॉटरिंग अवैध है। इसके साथ ही यहां लगने वाले पशु बाजार को लेकर भी विवाद की स्थिति है। मेट्रो रेल कंपनी ने यह जमीन सुभाष नगर स्टेशन की पार्किंग के लिए ली है। जबकि स्लॉटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग यहां पशु बाजार बनाए रखना चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे कुरैशी समाज के लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। समाज के लोगों ने कहा कि वे एक-दो दिन में निगम कमिश्नर से मुलाकात करेंगे।

27 दिसंबर को प्रकाशित खबर।

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
नई दिल्ली, बुधवार 31 दिसंबर, 2025

बिजनेस ब्रीफ

बागमाने लाएगा 4,000 करोड़ का रीट आईपीओ

बेंगलुरु | ब्लैकस्टोन समर्थित बेंगलुरु रियल इस्टेट डेवलपर बागमाने ग्रुप 4,000 करोड़ रुपए का रीट (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) आईपीओ लाने जा रहा है। ये देश का पांचवां ऑफिस रीट आईपीओ होगा। जानकारों के मुताबिक ग्रुप जल्द ही सेबी के पास दस्तावेज जमा करने वाला है। ग्रुप के पास बेंगलुरु में करीब 2 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस है। इसकी कुल कीमत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

पीएंडजी होम प्रोडक्ट्स का मुनाफा 19% बढ़ा

नई दिल्ली | एरियल, टाइड जैसे घरेलू उत्पाद बनाने वाली कंपनी पीएंडजी होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में 683 रु. करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। मंगलवार को शेयर बाजारों की दी गई जानकारी के मुताबिक ये लाभ 2023-24 की तुलना में 19.1% अधिक है। कंपनी की परिचालन से आय 3.4% बढ़कर 9,054 करोड़ रु. हुई, लेकिन कुल आय 2% घटकर 9,228 करोड़ रु. रह गई।

ब्लिंकिट के सीएफओ कपूरिया का इस्तीफा

बेंगलुरु | क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के सीएफओ विपिन कपूरिया के इस्तीफे के बाद इसकी पैरेंट कंपनी इटर्नल के शेयर मंगलवार को 2.21% तक गिरकर 276.60 रुपए पर आ गए। ये इसका 5 महीनों का सबसे निचला स्तर है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि एक साल पहले ब्लिंकिट जॉइन करने वाले विपिन कपूरिया अपने पूर्व नियोक्ता फ्लिपकार्ट में वापस लौट सकते हैं।

कंपनियों के रिटर्न भरने की तारीख 31 जनवरी

नई दिल्ली | कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने 2024-25 के लिए पेशेवरों और कंपनियों के वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इसके तहत कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। एमसीए-21 वी3 पोर्टल पर तकनीकी खराबी और स्लोडाउन की वजह से ये कदम उठाया गया। पहले सालाना विवरण दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर थी।

आईएचसीएल ने ताज जीवीके में हिस्सा बेचा

मुंबई | इंडियन होटल्स (आईएचसीएल) ने ताज जीवीके होटल्स में अपनी पूरी 25.52% हिस्सेदारी प्रमोटर जीवीके-भूपाल परिवार को 592 करोड़ रुपए में बेच दी। आईएचसीएल ने 16 लाख शेयर 370 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे। इन्हें जीवीके रेड्डी की बेटी शालिनी भूपाल ने एकमात्र खरीदार के रूप में खरीदा। मंगलवार को पूरे हुए इस सौदे के साथ दोनों पक्षों के बीच संयुक्त उद्यम का अंत हो गया।

ईटूई ट्रांसपोर्टेशन का आईपीओ 490 गुना भरा

मुंबई | रेल इंजीनियरिंग कंपनी ईटूई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का 84.22 करोड़ रु. का आईपीओ 30 दिसंबर को अंतिम दिन 490 गुना सब्सक्राइब हुआ। 164-174 इश्यू प्राइस वाले 34,62,40 रिजर्व शेयरों के अनुपात में 1,69,85,46,400 आवेदन मिले। गैर-संस्थागत निवेशकों का योगदान 871.67 गुना, खुदरा निवेशकों का 544 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों का 236.30 गुना रहा।

सौंदर्य प्रसाधन खरीद का बदल रहा रुझान • 4.5 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के 2025 के खरीदारी पैटर्न से मिली जानकारी

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर घंटे बिकी 1750 लिपस्टिक, 1,560 मॉइश्चराइजर

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश के सौंदर्य बाजार में रुझान लगातार बदल रहे हैं। ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म नायका की ब्यूटी रिवाइंड 2025 रिपोर्ट के मुताबिक सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री अब फैशन-आधारित विलासिता से हटकर परफॉरमेंस, उत्पाद की सामग्री और रोजमर्रा के उपयोग की सुविधा पर केंद्रित हो गई है। लोग प्रयोग के तौर पर खरीदारी करने के बजाय नियमित और दीर्घकालिक उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट करीब 4.5 करोड़ उपयोगकर्ता और 19,000 से अधिक पिन कोड पर डिलीवरी के आधार पर तैयार की गई है। इसके अनुसार, 2025 में प्लेटफॉर्म पर हर घंटे 1,750 लिपस्टिक, 1,560 मॉइश्चराइजर और 1140 क्लींजर बिके। नायका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 2025 में उसके प्लेटफॉर्म पर बिके सौंदर्य उत्पादों की संख्या जर्मनी की आबादी से भी ज्यादा रही।

बिक्री के अनूठे दावे: 575 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर बिक गए काजल

नायका का दावा है कि प्लेटफॉर्म पर साल भर में बिके मस्कारा एक के पीछे एक रखे जाएं तो मुंबई से पुणे तक की लंबाई कवर हो जाएगी। साल भर में बिके काजल को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उससे 575 बुर्ज खलीफा (दुनिया की सबसे ऊंची इमारत) बन जाएंगे। 2025 में बिके फेसवॉश एफिल टॉवर को 227 बार धो सकते हैं। इतनी सनस्क्रीन बिकी जो 39 हजार हाथियों को कवर कर ले।

11% की दर से बढ़ रहा कॉस्मेटिक मार्केट

मोर्डोर इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में देश का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट 1.89 अरब डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रु.) का था। ये 2030 तक करीब 11% सालाना की दर से बढ़कर 3.17 अरब डॉलर (करीब 28 हजार करोड़ रु.) का होने का अनुमान है।

कॉस्मेटिक विलासिता नहीं, दैनिक उपयोग की वस्तु

मोर्डोर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के प्रसार, बढ़ती डिस्पोजेबल आय और शहरीकरण ने कॉस्मेटिक्स को विलासिता के बजाय दैनिक उपयोग की वस्तुओं में शामिल कर दिया है। बिक्री में लोकप्रिय उत्पादों का हिस्सा 80% से ज्यादा है।

सौंदर्य प्रसाधन में लिप मेकअप का 37% हिस्सा

रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कॉस्मेटिक उत्पादों के बाजार में लिप-मेकअप की हिस्सेदारी 36.78% थी, जबकि आई मेकअप 11.74% सालाना की दर से बढ़ रहा है। स्किनकेयर में विशेष रूप से टिंटेड मॉइश्चराइजर की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है।

2025 निवेश के लिए कैसा रहा • सिल्वर फंड्स ने दिया रिकॉर्ड 128% औसत रिटर्न

म्यूचुअल फंड निवेशकों की संपत्ति रिकॉर्ड 80.8 लाख करोड़, लेकिन बढ़ने की रफ्तार 11% घटी

गोल्ड माइनिंग फंड 161% मुनाफे के साथ टॉप पर

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

वर्ष 2025 भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए ऐतिहासिक रहा। इसके द्वारा मैनेज की जाने वाली संपत्ति (एयूएम) का मूल्य 20.73 फीसदी की छलांग के साथ 80.80 लाख करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, बाजार में अस्थिरता के कारण एयूएम बढ़ने की रफ्तार 11.08 फीसदी घट गई। यह 2024 में 31.81 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी थी।

इस साल लार्जकैप और मिडकैप फंड्स ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर, स्मॉलकैप सेगमेंट में शेयरों की कीमतें गिरने से निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। पूरे साल की सबसे बड़ी हाईलाइट कीमती धातुएं रहीं, जिन्होंने इक्विटी के मुकाबले कहीं अधिक मुनाफा कमा कर दिया। म्यूचुअल फंड की विभिन्न श्रेणियों में सिल्वर फंड्स का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। इसने औसतन 128% का तगड़ा रिटर्न दिया। इसके बाद गोल्ड फंड्स ने 71% और इंटरनेशनल फंड्स ने 28% का औसत मुनाफा कराया।

गिरावट: स्मॉलकैप श्रेणी में ज्यादातर म्यूचुअल फंड नुकसान में रहे

वर्ष	एयूएम	वृद्धि
दिसं.-21	37.73	21.60%
दिसं.-22	39.89	5.73%
दिसं.-23	50.78	27.31%
दिसं.-24	66.90	31.81%
दिसं.-25	80.80	20.73%

एयूएम लाख करोड़ रु. में। (स्रोत: एम्फी)

रिकॉर्ड एसआईपी निवेश: वर्ष 2025 में नवंबर तक 11 माह में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिये कुल 3.04 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ, जो 2024 के 2.68 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 35,655 करोड़ रुपए (13%) अधिक है। अक्टूबर 2025 में एसआईपी निवेश 29,529 करोड़ रुपए के नए शिखर पर पहुंच गया।

स्मॉलकैप पर दबाव: स्मॉलकैप फंड्स में ऊंचे वैल्युएशन का करेक्शन हुआ। ज्यादातर फंड नुकसान में रहे। क्वांटम स्मॉलकैप फंड 1.81% रिटर्न के साथ इकलौता पॉजिटिव फंड रहा। सुंदरम, एचडीएफसी, पीजीआईएम और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉलकैप फंड्स का रिटर्न -1.56% से -1.88% के बीच रहा।

स्थिरता: लार्जकैप फंड से सीमित लेकिन भरोसेमंद रिटर्न हासिल हुआ

लार्जकैप फंड तीनों मार्केट-कैप सेगमेंट में सबसे स्थिर रहे। वैल्युएशन, अनुशासन और कमाई की स्पष्टता ने इन्हें सहारा दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने 10.1% रिटर्न दिया। मिराए एसेट, एसबीआई, आदित्य बिड़ला सन लाइफ और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स ने 8.9% से 7.9% के बीच रिटर्न दिया।

उतार-चढ़ाव: मिडकैप में रिटर्न अच्छा, लेकिन जोखिम ज्यादा रहा

मिडकैप फंड्स में रिटर्न ठीक रहा, लेकिन अस्थिरता ऊंची रही। सही स्टॉक चयन से फर्क पड़ा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने 8.23% दिया। मिराए एसेट, इनवेस्को, एचडीएफसी और टाटा मिडकैप फंड्स ने 6.6% से 4.2% तक रिटर्न दिया। सबसे कमजोर फंड का रिटर्न -11.78% रहा।

भास्कर एक्सपर्ट

पंकज श्रेष्ठा
हेड- इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, प्रभुदास लीलाधर

निवेश का 60% लार्ज, 40% मिड-स्मॉलकैप फंड में रखें

वैश्विक अस्थिरता, ट्रम्प टैरिफ जैसे कारणों की वजह से वर्ष 2025 काफी चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन वर्ष 2026 के बेहतर रहने की उम्मीद है। मजबूत जीडीपी ग्रोथ, आयकर, जीएसटी रेट में कटौती, आरबीआई द्वारा रेपो रेट 1.25% घटाकर 5.25% करने का असर इकोनॉमी में दिखेगा। आम निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड निवेश का 60% हिस्सा लार्जकैप में, 40% हिस्सा मिड और स्मॉलकैप में रखना चाहिए। यदि आप युवा हैं तो थोड़ा रिस्क लेकर 50% हिस्सा लार्जकैप में और 50% हिस्सा मिड-स्मॉल कैप में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लार्ज कैप बेहतर हैं। लक्ष्य 3-5 साल है तो मिड-स्मॉलकैप में निवेश करें।

मजबूत भरोसा • बीते साल से 59% बढ़ोतरी

रियल एस्टेट में आया 60 हजार करोड़ का निजी इक्विटी निवेश

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर विदेशी निवेशक भारत के बढ़ते ऑफिस और रेसीडेंशियल सेक्टर में निवेश बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सैविल्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेश 59% तक बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में 60,146 करोड़ रुपए का निवेश आया। खास बात ये रही कि वैश्विक भू-राजनैतिक अस्थिरता के बावजूद देश के रियल एस्टेट सेक्टर के पीई निवेश का 76% हिस्सा विदेशी निवेशकों से आया। सबसे ज्यादा पैसा (कुल इनफ्लो का 35.3%, करीब 21,544 करोड़ रु.) ऑफिस सेक्टर में लगा। इसके बाद डेटा सेंटर (23.2%) और रेसीडेंशियल (21%) श्रेणियां रही। डेटा सेंटर में निवेश पूरी तरह विदेशी पूंजी से आया, जबकि रेसीडेंशियल में घरेलू और विदेशी दोनों का योगदान रहा। सैविल्स के अनुसार, 2026 में पीई निवेश 6.5 बिलियन से 7.5 बिलियन डॉलर (58 से 68 हजार करोड़ रुपए) तक रहने की उम्मीद है। इसमें ऑफिस, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और प्रीमियम रेसीडेंशियल प्रमुख क्षेत्र होंगे।

हिस्सेदारी: रियल एस्टेट पीई निवेश में ऑफिस सेगमेंट का हिस्सा सबसे ज्यादा 35%, डेटा सेंटर दूसरे नंबर पर

क्षेत्र	हिस्सा (%)
ऑफिस (कार्यालय)	35.3%
डेटा सेंटर	23.2%
रेसिडेंशियल (आवासीय)	21%
इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स	9%
रिटेल	6%
हॉस्पिटैलिटी (होटल व पर्यटन)	5%
को-लिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग	0.5%

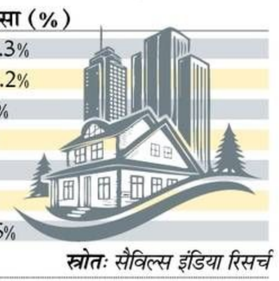

स्रोत: सैविल्स इंडिया रिसर्च

दबदबा • 16 साल में 10 गुना बढ़ी हिस्सेदारी

द. अफ्रीका में बिकने वाली 50% कारों का भारत से संबंध

एजेंसी | जोहानिसबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के ऑटो बाजार में भारत की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। साल 2025 में यहां बिकने वाली हर दूसरी कार का भारत से संबंध रहा। ये कारें या तो भारतीय कंपनियों जैसे महिंद्रा और टाटा की हैं या इनमें इस्तेमाल अहम पुर्जे भारत में बने हैं। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म लाइटस्टोन की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां भारत की हिस्सेदारी 2009 में महज 5% थी, जो 16 साल में 10 गुना बढ़कर 49% हो गई। भारत अब दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा ऑटो सोर्स बनता जा रहा है। खासतौर पर पिकअप और कार सेगमेंट में भारतीय कंपनियों और भारत में बने जापानी ब्रांड्स की मजबूत पकड़ दिखी है। एनालिस्ट एंड्रयू हिबर्ट के मुताबिक भारत में गाड़ियां बनाना कंपनियों के लिए बहुत सस्ता है। कम लागत का फायदा दक्षिण अफ्रीका के आम ग्राहकों को कम कीमतों के रूप में मिल रहा है। इससे भारतीय कारों की डिमांड में भारी उछाल आया है।

जापानी ब्रांड्स के 84% वाहन भारत से आयात

दक्षिण अफ्रीका में बिकने वाले जापानी ब्रांड के ज्यादातर वाहन असल में मेड इन इंडिया हैं। साल 2024 में जापान से मात्र 10% गाड़ियां ही बनकर आईं। बाकी 84% जापानी ब्रांड की सप्लाई सीधे भारतीय प्लांट से की गई। भारत की मारुति सुजुकी अब दक्षिण अफ्रीका में टोयोटा को भी गाड़ियां दे रही है। इसमें स्टारलेट क्रॉस, विट्ज और अर्बन क्रूजर जैसे मॉडल शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा: चीनी आयात से 3 गुना आगे निकला भारत

दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर हवॉल और चेरी जैसी चीनी कारें ज्यादा दिखती हैं। इससे उनके दबदबे का भ्रम बनता है। हालांकि ताजा आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। 2024 में चीनी आयात कुल बिक्री का सिर्फ 11% रहा। इसके मुकाबले भारत से 36% वाहन आयात हुए। वहीं स्थानीय उत्पादन का योगदान 37% था।

चुनौती • फूड डिलीवरी गिग वर्कर्स की हड़ताल से दबाव

नए साल पर लास्ट-मिनट ट्रैवल बुकिंग 28% बढ़ी, होटल के कमरों का किराया 45 फीसदी तक बढ़ा

अक्षरा श्रीवास्तव | नई दिल्ली

नए साल के जश्न के लिए देश भर के होटलों और लग्जरी विला में आखिरी समय में बुकिंग का बड़ा उछाल देखा जा रहा है। साल 2025 के अंतिम दिनों में लोनावला, नासिक, गोवा और कसौली जैसे पर्यटन स्थलों पर कमरों की मांग 31% तक बढ़ गई है। लग्जरी विला रेंटल कंपनी स्टेविस्टा को नए साल की कुल बुकिंग का करीब 28% हिस्सा पिछले 72 घंटों में ही मिला है। लोग अब भीड़भाड़ वाली पार्टियों के बजाय निजी विला में जश्न मनाना पसंद कर रहे हैं। भारी मांग के कारण कमरों के किराये में भी 9% से 45% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्टेविस्टा के सह संस्थापक अमित दमानी के मुताबिक, कमरों के किराये त्योहारी मौसम के आम किराये की तुलना में 30-45% तक अधिक हैं। एक तरफ जहां होटल कारोबार मुनाफे में है, वहीं दूसरी तरफ गिग वर्कर्स की 31 दिसंबर को होने वाली हड़ताल ने फूड डिलीवरी सेक्टर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स के काम न करने से कई रेस्तरां और क्विक सर्विस चेन दबाव महसूस कर रही हैं।

गिग वर्कर्स की हड़ताल से स्विगी-जोमैटो अलर्ट मोड में

एक ओर जहां होटल कारोबार को फायदा हो रहा है, वहीं फूड डिलीवरी गिग वर्कर्स की हड़ताल के कारण फूड कारोबार पर असर पड़ा है। स्विगी-जोमैटो अलर्ट मोड में हैं। इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करना कठिन हो गया है। इसके बावजूद वाउ मोमो जैसे स्टोर अपनी टाइमिंग बदलकर 30 मिनट में डिलीवरी का लक्ष्य रख रहे हैं। कोलकाता का फैब्रिका आउटलेट इस दौरान बिक्री 35% बढ़ने की उम्मीद कर रहा है।

एनएफएपी-2025

बदलावों के साथ स्पैक्ट्रम आवंटन योजना लागू हुई

नई दिल्ली | सरकार ने बदलावों के साथ नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान (एनएफएपी) 2025 लागू कर दिया है। मंगलवार से प्रभावी ये प्लान देश में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के आवंटन और उपयोग के लिए रोडमैप की तरह काम करेगा। ये योजना 5जी, 5जी-एडवांस्ड, 6जी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन (सैटकॉम) जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। एनएफएपी के तहत 8.3 किलोहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम बैंड का प्रबंधन किया जाएगा।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

5वें दिन भी गिरावट जारी, सेंसेक्स 20 अंक टूटा

मुंबई | साल के आखिरी दिनों में कम कारोबार और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को पांचवें दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 84,675 पर बंद हुआ। मासिक एक्सपायरी के दिन निफ्टी भी एक सीमित दायरे में घूमता रहा। अंत में 3 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 25,939 पर बंद हुआ। एफआईआई ने भारतीय बाजार से 3,844 करोड़ रुपए निकाले। वहीं, घरेलू फंड्स ने 6,160 करोड़ रुपए लगाए।

एआई सेवा बढ़ाने की कोशिश

मेटा ने एआई स्टार्टअप मैनस का अधिग्रहण किया

डेट्राइट | फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा ने सिंगापुर स्थित एआई स्टार्टअप मैनस का अधिग्रहण किया है। ये अधिग्रहण मेटा का अपने सभी प्लेटफॉर्म पर एआई सेवाओं को बढ़ाने के आक्रामक प्रयासों की कड़ी में है। जानकारों के मुताबिक ये अधिग्रहण करीब 2 अरब डॉलर (करीब 18 हजार करोड़ रुपए) में हुआ है। मैनस ने इस साल अपना पहला सामान्य प्रयोजन वाला एआई एजेंट लॉन्च किया था। प्लेटफॉर्म निर्धारित शुल्क के साथ शोध, कोडिंग और अन्य कार्यों के लिए सदस्यता देता है।

बजट • मोदी की अर्थशास्त्रियों से चर्चा

राजकोषीय जोखिमों पर चिंता, पूंजीगत खर्च में बदलाव की मांग

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व चर्चा में हिस्सा लिया। बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों ने राजकोषीय जोखिमों पर चिंता जताई, पूंजीगत खर्च में बदलाव और घरेलू बचत को फिर से मजबूत करने की मांग की। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी पूंजीगत खर्च को धीरे-धीरे 3% के करीब लाया जाना चाहिए ताकि निजी क्षेत्र के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सीईओ और दिग्गज अर्थशास्त्री शामिल हुए।

अंबानी का एआई विजन

रिलायंस का भारत में किफायती एआई उपलब्ध कराने का लक्ष्य

मुंबई | रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के एआई घोषणापत्र का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे में कंपनी को एआई-आधारित डीप-टेक उद्यम में बदलने की दिशा बताई गई है। इस पहल का उद्देश्य छह लाख से अधिक कर्मचारियों की उत्पादकता में दस गुना बढ़ोतरी और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर दस गुना प्रभाव डालना है। मुकेश अंबानी ने बताया कि एआई को सभी व्यवसायों में एकीकृत किया जाएगा। रिलायंस का लक्ष्य हर भारतीय के लिए किफायती एआई उपलब्ध कराना होगा। अंबानी ने एआई को मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकास बताया।

बिजनेस एंकर केबीसी में कुमार मंगलम बिड़ला ने पत्र को बताया उद्योग घराने का मूलमंत्र

जीडी बिड़ला का 91 साल पुराना पत्र... लक्ष्मी चंचल है, इसका उपयोग विलासिता के लिए न हो, सेहत ही 'सबसे बड़ी पूंजी'

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

'कौन बनेगा करोड़पति' के एक एपिसोड में भारतीय उद्योग जगत से जुड़ा वर्ष 1934 का एक पत्र सामने आया। यह पत्र उद्योगपति घनश्याम दास (जीडी) बिड़ला ने अपने पुत्र बसंत कुमार बिड़ला के नाम लिखा था। पत्र में जी.डी. बिड़ला ने धन, शक्ति और जिम्मेदारी को लेकर अपने विचार साझा किए थे। कार्यक्रम में आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला उपस्थित थे। उन्होंने इस पत्र को अपने 'परिवार का अनमोल खजाना' बताया और अमिताभ बच्चन को इसे पढ़ने के लिए दिया।

पत्र में जीडी बिड़ला ने धन के लिए अपने विचार बताए थे। उन्होंने लिखा कि लक्ष्मी चंचल होती है और धन का टिके रहना अनिश्चित होता है, इसलिए इसका उपयोग कभी भी विलासिता या व्यक्तिगत शौक की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार, धन समाज की एक अमानत है और इसका उपयोग समाज सेवा तथा लोक-कल्याण के कामों में किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी उल्लेख है कि संपन्नता से जुड़े निर्णयों में संयम और विवेक अत्यंत आवश्यक हैं।

जीडी बिड़ला ने पत्र में सत्ता और संपत्ति से पैदा होने वाले अहंकार को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने अगली पीढ़ी से यह अपेक्षा जताई कि सफलता और सामर्थ्य का प्रयोग कभी अन्याय के लिए न हो। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिड़ला समूह की स्थापना का उद्देश्य केवल व्यवसाय विस्तार नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी करना था। इसलिए इस उद्देश्य को आगे भी बनाया रखना चाहिए।

पत्र का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़ा हुआ है। जी.डी. बिड़ला का विश्वास था कि स्वास्थ्य ही 'सबसे बड़ी पूंजी' है, जिसके अभाव में अरबों की संपत्ति का स्वामी भी लाचार और दयनीय हो सकता है। उन्होंने संतुलित आहार, योग और नियमित व्यायाम को आवश्यक बताया। उन्होंने लिखा, 'भोजन को दवा की तरह लें, इसे केवल स्वाद के लालच में न खाएं।' उनके अनुसार, शारीरिक अनुशासन से ही मानसिक सजगता और कार्यक्षमता बनी रहती है।

बेटी ने कहा, पिता अपनी व्यस्तता के बावजूद समय देते हैं

कुमार बिड़ला की बेटी अद्वैतेशा ने बताया कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनके पिता बच्चों के लिए समय निकाल लेते है। जब वे विदेश में पढ़ाई कर रही थीं, तब उनके पिता दिन में कई बार फोन कर उनकी कुशलता पूछते थे। उन्होंने बताया कि वे दोनों अक्सर बैठकर पेंटिंग करते हैं। बेटे आर्यमन ने बताया कि हर शाम पिता ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने समय पर भोजन किया है या नहीं। कार्यक्रम के दौरान नीरजा बिड़ला ने हल्के-फुल्के अंदाज में बताया कि कई बार कुमार बिड़ला उनकी बातों पर तुरंत ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उन्हें बात दोहरानी पड़ती है।

बड़ी छंटनी का साल • एआई, रेगुलेशन और मुनाफे का दबाव

इस साल 257 कंपनियों ने 1.22 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारियों को निकाला

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

एक दशक तक तेज हायरिंग के बाद भारत सहित दुनियाभर के टेक सेक्टर ने इस साल नौकरियों में बड़ी कटौती की है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल, कुछ क्षेत्रों में सख्त नियमों और मुनाफा बढ़ाने पर नए सिरे से ध्यान देने के कारण दुनिया भर में ऐसी छंटनी देखने को मिली। स्वतंत्र ट्रैकर ले-ऑफ्स डॉट एफवाईआई के अनुसार इस साल 257 कंपनियों ने 1,22,549 तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसका असर पारंपरिक आईटी सेवा कंपनियों, उपभोक्ता इंटरनेट स्टार्टअप और भारत में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी पड़ा है। सबसे ज्यादा छंटनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), सेल्सफोर्स, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट में हुई। टीसीएस ने मिड और सीनियर लेवल की भूमिकाओं के 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की। अमेजन ने अक्टूबर में 14,000 वैश्विक पदों में कटौती की और भारत में भी 1,000 पद हटाए। माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 पदों में कटौती की। इंटेल ने अपने कर्मचारियों की संख्या 75,000 तक सीमित की। एप्पल, मेटा, वेरिजोन, सीमेंस, सेल्सफोर्स, एचपी जैसी कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर छंटनी की। भारत में ओला इलेक्ट्रिक ने 1,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की।

गेमिंग उद्योग पर नियामक झटका, असर नौकरियों पर

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत रियल-मनी गेमिंग लगभग प्रतिबंधित हो गया, जिससे 2 लाख करोड़ रुपए का बाजार प्रभावित हुआ। ड्रीम11 ने लगभग 500 इंजीनियरों को एआई और फिनटेक प्रोजेक्ट्स में स्थानांतरित किया। मोबाइल प्रीमियर लीग ने 600 से अधिक पद समाप्त किए। गेम्सक्राफ्ट ने लगभग 400 नौकरियों में कटौती की।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 31-12-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH07 User: sachin.saini Time: 12-30-2025 20:18 Color:

शीतकालीन तीर्थाटन एवं पर्यटन को नई दिशा दे रही देवभूमि उत्तराखंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुखबा यात्रा के बाद शीतकालीन चारधाम सर्किट को मिली नई राष्ट्रीय पहचान। उत्तराखंड सरकार इस विजन को प्रमुखता देते हुए सालभर तीर्थयात्रा कर सकने की सुविधा को सुनिश्चित कर रही है। बर्फ से ढकी चोटियां और प्राचीन पूजा स्थल तीर्थयात्रा के अनुभव को दिव्यता देंगे।

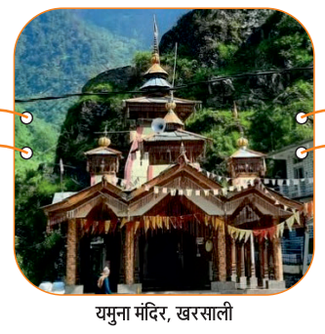

"उत्तराखंड के पास एक प्राकृतिक आध्यात्मिक शक्ति है, जो उसे विशिष्ट बनाती है। देवभूमि की यह शक्ति, विरासत और पवित्रता इसे ऐसी पहचान देती है, जो कहीं और नहीं मिलती। राज्य अब अपार संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर रहा है और यदि यह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो दुनिया के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में अपना स्थान बना सकता है। आध्यात्मिक सामर्थ्य के साथ-साथ उत्तराखंड एक सुंदर विवाह-गंतव्य के रूप में भी उभर रहा है। 'वेड इन इंडिया' दृष्टिकोण का लाभ लेने के लिए राज्य कुछ चुनिंदा स्थानों को विश्व-स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित कर विकसित कर सकता है, ताकि देश भर के लोग उत्तराखंड की शांत और दिव्य वादियों में अपने विशेष अवसरों का उत्सव मना सकें।"

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

"माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व से प्रेरित होकर, हम उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और अपार संभावनाओं के साथ हम दूरदर्शी नीतियों और केंद्रित पहलों के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने, अवसंरचना को उन्नत करने और प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को विकास का एक आदर्श मॉडल बनाना है, जहां विरासत और नवाचार साथ-साथ आगे बढ़ें, और हर व्यक्ति को एक समृद्ध, प्रगतिशील और समावेशी वातावरण में आगे बढ़ने और सफल होने के अवसर मिलें।"

— **पुष्कर सिंह धामी**
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

आस्था, आध्यात्म व रोमांच का केंद्र है देवभूमि उत्तराखण्ड

गंगा मंदिर, उत्तरकाशी

ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ

यमुना मंदिर, खरसाली

योगध्यान बद्री मंदिर, पांडुकेश्वर

उत्तराखंड का शीतकालीन चारधाम सर्किट पारंपरिक ग्रीष्मकालीन तीर्थयात्रा को एक सालभर उपलब्ध आध्यात्मिक और पर्यटन अवसर में परिवर्तित करता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के मुख्य मंदिर जब शीतऋतु के दौरान बंद हो जाते हैं, तो उनके देवताओं की मूर्तियां शीतकालीन गद्दीस्थलों या वैकल्पिक स्थानों पर स्थापित की जाती हैं, जिससे भक्त पूजा-अर्चना जारी रख सकें। हाल के महीनों में, इस सर्किट को नई पहचान तब मिली जब गंगा की शीतकालीन निवासस्थली मुखबा में एक उच्च-स्तरीय यात्रा हुई।

6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर्षिल-मुखबा क्षेत्र में स्थित गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास पर दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। इस यात्रा ने शीतकालीन तीर्थयात्रा के महत्व को रेखांकित किया और यह दर्शाया कि उत्तराखंड में पर्यटन को गर्मियों के मौसम से आगे बढ़ाकर सालभर की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था—शीत ऋतु को 'ऑफ-सीजन' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह यात्रा आस्था और विकास दोनों का प्रतीक बनी, क्योंकि इसने चारधाम की धार्मिक निरंतरता को पुनः स्थापित किया और साथ ही शीतकालीन पर्यटन को मजबूत करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और प्रचार-प्रसार पर ध्यान आकर्षित किया।

मुखबा अपने आप में शांत और मनोहारी हिमालयी सौंदर्य वाला स्थान है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने पर देवी की मूर्ति विधि-विधान के साथ मुखबा लाई जाती है, जिससे भक्त कम ऊंचाई वाले इस स्थान पर भी पूजा कर सकें। बर्फ से ढकी चोटियां और प्राचीन पूजा-पद्धतियों का संगम मुखबा को शीतकालीन तीर्थयात्रा का एक अनोखा और भावपूर्ण प्रारंभिक बिंदु बनाता है।

शीतकालीन चारधाम सर्किट देवप्रतिमाओं को शीतकालीन मंदिरों में स्थापित कर सालभर तीर्थयात्रा को संभव बनाता है, जहां आस्था हिमालयी यात्रा अनुभवों के साथ सुगमता से जुड़ती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुखबा यात्रा ने शीतकालीन पर्यटन की विशाल संभावनाओं को उजागर किया, जिससे अवसंरचना विकास और पर्यटन प्रोत्साहन को नई दिशा मिली। औली, चकराता और दयारा बुग्याल जैसे नज़दीकी गंतव्य आध्यात्मिकता, रोमांच और प्रकृति-आधारित अनुभवों को और समृद्ध बनाते हैं।

टिहरी में पैराग्लाइडिंग

शीतकालीन चारधाम के अनुभव को आस-पास के गंतव्यों से बनाएं बेहतर

दयारा बुग्याल

दयारा बुग्याल : एक विस्तृत अल्पाइन घासभूमि, जो शीतकालीन बर्फीले नजारों और ग्रीष्मकालीन चरागाहों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में इसकी दूर-दूर तक फैली सफ़ेद घाटियां ध्यानपूर्ण सैर के लिए आदर्श हैं और हिमालय के व्यापक दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

चकराता : देवदार के जंगलों, झरनों और आसान ट्रेकिंग मार्गों के लिए जाना जाने वाला शांत पहाड़ी कस्बा। चकराता के सुरम्य वनप्रदेश भीड़भाड़ वाले तीर्थ मार्गों से अलग एक शांत अनुभव प्रदान करते हैं।

लाखामंडल : यह प्राचीन मंदिर परिसर पुरातात्विक अवशेषों और ऐतिहासिक शिव मंदिरों से सम्पन्न है। क्षेत्र की प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य परंपरा और स्थानीय पौराणिक धरोहर में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए यह एक सांस्कृतिक आकर्षण जोड़ता है।

औली : भारत का प्रमुख स्कीइंग गंतव्य, जहां शीतकालीन खेल, रोपवे और नंदा देवी सहित कई हिमालयी चोटियों के दिव्य दृश्य उपलब्ध हैं। तीर्थयात्रा के साथ रोमांचक पर्यटन अनुभव चाहने वाले यात्रियों के लिए औली एक आकर्षक विकल्प है।

काशी विश्वनाथ (उत्तरकाशी) : उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय धाम है और ऊंचाई वाले तीर्थस्थलों की ओर जाते समय एक आध्यात्मिक विराम प्रदान करता है। इसकी उपस्थिति चारधाम यात्रा की धार्मिक निरंतरता को और मजबूत बनाती है।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान : यूनेस्को बायोस्फियर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त यह उद्यान उच्च हिमालयी वाइल्डरनेस, दुर्लभ वनस्पतियों—जीवों और समृद्ध संरक्षण विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहां की यात्रा तीर्थयात्रा अनुभव में पर्यावरणीय जागरूकता और प्रकृति संरक्षण की गहराई जोड़ती है।

औली

विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा उत्तराखंड

उत्तराखंड अपने मंदिर सर्किट, प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाकर खुद को आध्यात्मिकता और कल्याण का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। अपने इस प्रयास से यह विश्व पटल पर नई पहचान भी स्थापित कर रहा है

उत्तराखंड धीरे-धीरे एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो प्राचीन मंदिर सर्किटों को पुनर्जीवित, सशक्त और आधुनिक बनाने के केंद्रित प्रयासों से प्रेरित है। इस दिशा में एक प्रमुख पहल है मानसखंड मंदिर माला मिशन, जिसका उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के महत्वपूर्ण मंदिरों का विकास और आपसी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत पहुंच मार्गों, आगंतुक सुविधाओं और धरोहर अवसंरचना में सुधार कर, राज्य की समृद्ध सभ्यतात्मक विरासत पर आधारित एक सहज तीर्थयात्रा अनुभव तैयार करना लक्ष्य है।

इस आध्यात्मिक परिदृश्य में योगदान देने वाले प्रमुख मंदिरों में रुद्रप्रयाग जिले का कार्तिक स्वामी मंदिर शामिल है। एक ऊंची चट्टानी कगार पर स्थित यह मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और हिमालयी चोटियों के मनोरम दृश्य के साथ शांतिपूर्ण भक्तिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए एक पवित्र स्थल और मनोहारी दृष्टि बिंदु दोनों बनाती है।

इसी तरह, त्रिजुगीनारायण मंदिर, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं में लिप्त यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में लगातार जलती रहने वाली अनंत ज्योति उस दिव्य मिलन का जीवित प्रतीक मानी जाती है, जो पूरे वर्ष भक्तों को आकर्षित करती है।

कार्तिक स्वामी मंदिर, भगवान कार्तिक को समर्पित, जिन्हें देश के कुछ हिस्सों में भगवान मुरुगा / मुरुगन के नाम से जाना जाता है।

जागेश्वर धाम, 125 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह, जो भगवान शिव को समर्पित है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 9 नवंबर 2025 को देहरादून में दिया गया संबोधन राज्य की आध्यात्मिक संभावनाओं को और मजबूत करता है। उन्होंने उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्ति पर बल देते हुए कहा, "यदि उत्तराखंड इसे ठान ले, तो कुछ ही वर्षों में यह विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकता है" उनकी यह टिप्पणी राज्य की बदलती पहचान की संपूर्णता को दर्शाती है, जो आध्यात्मिकता, तीर्थयात्रा और सांस्कृतिक निरंतरता में निहित है।

रणनीतिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और धरोहर आधारित विकास पर नए प्रयास के साथ, उत्तराखंड इस दृष्टि को साकार करने की दिशा में अग्रसर है, खुद को विश्वास, पवित्रता और आध्यात्मिक खोज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए तैयार कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि ग्रामीण इलाके पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। साथ ही हर पर्यटन स्थल अपना खुद का राजस्व मॉडल भी विकसित कर सकता है। हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए होमस्टे और छोटे होटलों जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है

'वेड इन उत्तराखंड' से राज्य में बढ़ रहा वेडिंग पर्यटन का आकर्षण

राज्य की पर्यटन क्षमता की ओर इशारा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय 'वेड इन इंडिया' पहल के तहत उत्तराखंड की क्षमता को एक प्रमुख डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के रूप में उभरने की ओर इंगित किया। यह पहल प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के बाद उत्तराखंड धीरे-धीरे शादी पर्यटन के लिए एक प्रत्याशित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस समारोह, 9 नवंबर 2025 को अपने संबोधन में राज्य के प्राकृतिक दृश्य, आध्यात्मिक वातावरण और बढ़ती पर्यटन अवसंरचना की क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि ये सभी कारक देश और विदेश से वेडिंग पर्यटन को आकर्षित करने में सहायक हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि उत्तराखंड पहले ही एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है, जो अपनी पर्वतीय भव्यता, नदियों और शांत घाटियों के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। उन्होंने 'वेड इन इंडिया' पहल के अंतर्गत राज्य की एक विशिष्ट पहचान बनाने का महत्व रेखांकित किया और सुझाव दिया कि उत्तराखंड 5—7 प्रमुख वेडिंग स्थल विकसित कर सकता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं के साथ राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करें।

उन्होंने यह भी कहा कि पहुंच मार्गों में सुधार, आतिथ्य सेवाओं को बढ़ाना और स्थानीय परंपराओं को समेकित करना न केवल पर्यटन अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित करेगा। रोमांच, ईको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को पहले ही बढ़ावा देने वाली सरकार के लिए, समर्पित वेडिंग डेस्टिनेशन रणनीति राज्य की पेशकशों में और विविधता जोड़ती है।

मजबूत जनसहानुभूति और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के साथ, उत्तराखंड भारत के सबसे आकर्षक वेडिंग गंतव्यों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाने जा रहा है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक गहराई और विश्व-स्तरीय आतिथ्य का अनूठा संयोजन मिलेगा।

प्रसिद्ध त्रिजुगीनारायण मंदिर, भगवान शिव और पार्वती के विवाह के लिए जाना जाता है और अटूट आस्था और आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक है।

होमस्टे नीति से ग्रामीण पर्यटन को मिल रहा विस्तार

5,000 से अधिक पंजीकृत होमस्टे और प्रोत्साहनों के साथ, होमस्टे नीति सामुदायिक पर्यटन और स्थानीय आजीविका को मजबूत बना रही है

उत्तराखंड की होमस्टे नीति तेजी से ग्रामीण पर्यटन और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ बनती जा रही है। वर्तमान में राज्य में 5,000 से अधिक पंजीकृत होमस्टे हैं, जो पहाड़ी जिलों में समुदाय-आधारित आवास के तेज विस्तार को दर्शाते हैं।

योजना के तहत, सामान्य क्षेत्रों में संचालित होमस्टे को अधिकतम ₹7.5 लाख तक की पूंजी अनुदान मिल सकती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह राशि ₹10 लाख तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कई वर्षों के लिए ब्याज अनुदान का भी प्रावधान है। होमस्टे संचालकों का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है और उन्हें स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और अतिथ्य को पर्यटक अनुभव में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना और पर्यटन के माध्यम से पलायन को रोकना है। प्रारंभिक आंकलन बताते हैं कि होमस्टे मॉडल आय बढ़ाने, स्थानीय आजीविकाओं में विविधता लाने और उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में सामुदायिक विकास में योगदान दे रहा है।

आस्था, आध्यात्म व रोमांच का केंद्र है आदि कैलाश

प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद आस्था व साहस का प्रतीक बनकर उभरा है आदि कैलाश

आदि कैलाश, उत्तराखंड के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक स्थलों में से एक, आज तेजी से ऐसे गंतव्य के रूप में उभर रहा है जहां पौराणिक विरासत और ऊंचाई वाले साहसिक अनुभव एक साथ मिलते हैं। अपनी गहरी पौराणिक महत्ता और भव्य हिमालयी आभा के लिए प्रसिद्ध आदि कैलाश राज्य की सांस्कृतिक पहचान में एक विशेष स्थान रखता है। यह क्षेत्र अब तीर्थयात्रियों, प्रकृति प्रेमियों और रोमांच-प्रेमी यात्रियों को आकर्षित कर रहा है, जो आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ निर्मल प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा ने इसकी राष्ट्रीय पहचान को और अधिक सशक्त किया है। 9 नवंबर 2025 को देहरादून में अपने संबोधन के दौरान

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि किस प्रकार यह क्षेत्र उत्तराखंड की बढ़ती पर्यटन अपील का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन रहा है। उन्होंने बढ़ती पर्यटक संख्या की सराहना करते हुए बताया कि तीन वर्ष पहले जहां वर्षभर में 2,000 से भी कम पर्यटक आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 30,000 पहुंच गई है। यह बदलाव बेहतर कनेक्टिविटी और उन्नत अवसंरचना के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। यह क्षेत्र एक ऐतिहासिक खेल आयोजन का भी साक्षी बना, जहां उच्च हिमालयी ऊंचाइयों पर आयोजित अल्ट्रामैराथन और आदि कैलाश परिक्रमा रन सफलतापूर्वक संपन्न हुए। प्रधानमंत्री ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि देश-विदेश के एथलीटों को हिमालय की आध्यात्मिक और पर्यावरणीय समृद्धि से भी परिचित कराते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास राज्य में इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाओं को सामने लाते हैं।

अनदेखे रोमांच का अद्वितीय संगम

उत्तराखंड दुनियाभर के रोमांच खेल प्रेमियों को अनूठा अनुभव प्रदान करता है

देश में जब रोमांच पर्यटन की बात आती है, तो उत्तराखंड अपने विविध परिदृश्यों और रोमांच प्रेमियों का पसंदीदा स्थान बन जाता है। यहां रोमांचक गतिविधियों की कोई कमी नहीं है। आपको यहां जोश से भर देने वाले कई खेल खेलने को मिल जाते हैं और यही कारण है कि दुनियाभर के रोमांच प्रेमियों के लिए यह राज्य असाधारण अनुभव प्रदान करता है।

ट्रैकिंग और हाईकिंग

ट्रैकिंग और हाइकिंग के माध्यम से आप उत्तराखंड की सुदूर जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां पारंपरिक रूपकुंड ट्रैक पर ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है, जहां हरे-भरे जंगल और घास के मैदानों के बीच या फूलों की घाटी के बीच से होकर गुजरना सुखद अहसास दे सकता है। लंबी सैर करने वालों के लिए केदारकांठा और गौमुख तपोवन ट्रैक जीवन भर के लिए यादगार अनुभव दे जाते हैं।

बंजी जंपिंग

विश्व की योग राजधानी के रूप में भी पहचाना जाने वाला ऋषिकेश अपने जोशीले रोमांच के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पूरे देश में सबसे ऊंची बंजी जंपिंग साइट है। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की इच्छा रखने वाले रोमांच प्रेमी शानदार हिमालय पहाड़ियों के बीच बंजी जंपिंग करने के लिए यहां आते हैं।

स्कीइंग

चमोली जिले में स्थित औली को स्कीइंग प्रेमियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। दूर तक बर्फ से ढकी पहाड़ी ढलानों के साथ रोमांच प्रेमी इसके शीतकालीन वंडरलैंड से रास्ता तय करते हुए औली की यात्रा करते हैं। यह शानदार स्थल राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां एथलीटों को अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका मिलता है।

रिवर राफ्टिंग

उत्तराखंड की नदियां केवल राज्य की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि व्हाइट वॉटर राफ्टिंग के प्रेमियों में जोश भर देती हैं, जो यहां रोमांच के लिए आते हैं। जब पर्यटक सफेद पानी में राफ्टिंग के माध्यम से रैपिड्स पर विजय प्राप्त करते हैं या गंगा, टोंस और अलकनंदा नदियों में एक शांत कैनोइंग या कयाकिंग के दौरान पानी पर नौका चलाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अलग रोमांच का अनुभव मिलता है।

पैराग्लाइडिंग

रोमांच प्रेमी यहां आसमान की सैर भी कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग से उत्तराखंड की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। नैनीताल, मुक्तेश्वर, या पिथौरागढ़ के मनोरम स्थानों से वह आसमानी उड़ान भरकर शानदार हिमालयी इलाकों का नजारा भी ले सकते हैं। रोमांच के अलावा, उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र ने स्थानीय निवासियों के लिए समृद्धि भी लाई है।

READER ENGAGEMENT INITIATIVE

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 31-12-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMA14 User: cci Time: 12-30-2025 21:40 Color:

मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता की पहचान की प्रामाणिकता ही चुनावों की विश्वसनीयता के केंद्र में है।

– एस. वाई. क़ुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

समय लेना सही

उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision की तारीखों में फिर बदलाव अपेक्षित था और चुनाव आयोग ने प्रक्रिया के लिए खुद को ज्यादा समय देकर सही किया है। बिहार में हुए पहले चरण के मुकाबले इस दूसरे फेज में SIR के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है। आम लोगों को भी कई तरह की परेशानी आ रही है।

पहले भी बढ़ी तारीख । यूपी में पहले 31 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी किया जाना था। अब यह लिस्ट 6 जनवरी को आएगी और फाइनल रोल 6 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। इस दौरान जनता को दावे, आपत्तियों और उनके निस्तारण का मौका मिलेगा। इससे पहले SIR फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई थी। ऐसा ही एक्सटेंशन तमिलनाडु, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिला था।

SIR की तारीख बदली

विवाद और आरोप । तारीखों में बार-बार बदलाव से पता चलता है कि आयोग को उम्मीद से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के अनुभव से फायदा मिलने की जो उम्मीद थी, लगता नहीं कि वह पूरी हुई। लगभग हर दिन ही प्रक्रिया से जुड़ा कोई विवाद या आरोप सामने आ रहा है।

विपक्ष की शिकायत । एक अनुमान के मुताबिक यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स का नाम ड्राफ्ट रोल से कट सकता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। बिहार में पहले ड्राफ्ट रोल में 65 लाख मतदाता कम थे। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर नागरिकता जांची जा रही है और इससे योग्य मतदाता भी नाम दर्ज नहीं करा पा रहे। इस तरह की शिकायत को केवल राजनीतिक आरोप मानकर टालना सही नहीं होगा। अगर लाखों लोगों ने फॉर्म भरकर नहीं लौटाए हैं, तो उसकी वजह भी पता चलनी चाहिए।

सुधार की जरूरत । SIR इस समय राजनीतिक टकराव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है, खासकर बंगाल में। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि SIR की वजह से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। दो दिन पहले ही एक बुजुर्ग ने आयोग के सामने सुनवाई से पहले आत्महत्या कर ली। BLO की मौत और आत्महत्या के भी कई केस आ चुके हैं। अगर किसी प्रक्रिया की वजह से आम लोगों में इस कदर डर और दबाव है कि वे मौत का रास्ता चुन रहे, तो इसका मतलब सुधार की जरूरत है।

सिस्टम की जिम्मेदारी । SIR का मकसद ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। यह चुनाव आयोग पर है कि लोग मताधिकार से वंचित न हों। इसमें अगर और समय लगता है तो और सही।

नाभि में तीर

नेताजी की करामात

मुंबई में जब से BMC चुनावों की घोषणा हुई है, तब से गिरगिट हैरान है। ज्यूं-ज्यूं चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही है। अब तक तो उसको यही गुमान था कि रंग बदलने के हुनर में उसका कोई मुकाबला नहीं। इस क्षेत्र में उसकी मोनोपोली है। लेकिन अब उसका यह भ्रम टूट चुका है। बड़े नेताओं को छोड़िए, गली-कूचे के छुटभैया नेता तक उसकी रंग बदलने की कला को मात दे रहे हैं। गिरगिट को पहली बार समझ में आया है कि दुनिया में उसके भी बाप मौजूद हैं!

हरि मृदुल

रविवार की सुबह एक छुटभैया नेता जी ने समर्थकों के बीच घोषणा की थी कि उनकी पार्टी अब वैसी नहीं रही, जैसी कि वह थी। इसीलिए अब वह अमुक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समर्थकों का उनको पूरा समर्थन मिला और 'नेता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारों के साथ जुलूस निकाल दिया। लेकिन यह क्या कि सोमवार को नेता जी के हाथों में एक अन्य पार्टी का झंडा दिखाई देने लगा। समर्थकों को लगा कि यह उनके विरोधियों की करामात है। AI के जमाने में कुछ भी किया जा सकता है। परंतु नेता जी के कार्यालय की नई सजावट से स्पष्ट हो गया कि यह AI की नहीं, खुद नेता जी की ही करामात है। उन्होंने फिर बदल लिया है दल। हैरत की बात यह कि मंगलवार की शाम एक बार फिर अलग हवा बह रही थी। नेता जी समर्थकों के बीच थे और खीसें निपोरकर कह रहे थे कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत कदम उठाया। पुरानी पार्टी उनके लिए फिर से वैसी हो गई है, जैसी पहले थी!!

नेता जी के रंग बदलने को लेकर भले ही गिरगिट हैरान हो, लेकिन समर्थक एकदम कूल हैं। उन्हें पहले दिन से पता है कि नेता जी कितने बड़े कलाकार हैं। उनका एकमात्र मिशन माल कमाना है, सो कमा रहे हैं। जब नेता जी अपनी पुरानी पार्टी के प्रति विश्वास जता रहे थे, उसी समय उनका एक समर्थक दूसरे समर्थक के कान में फुसफुसा रहा था, 'इन तीन दिनों में नेता जी ने अपनी तीन पीढ़ियों के लिए माल इकट्ठा कर लिया है...।'

एकदा

संकलन : **रिंकल शर्मा**

मौत के बाद महानता

फ्रांज काफ्का (1883–1924) विश्व साहित्य के उन विरले लेखकों में हैं, जिनका जीवन उनकी ही नजर में प्रश्नचिह्न था। प्राग में जन्मे काफ्का पेशे से बीमा अधिकारी थे। उन्हें लगता था कि उनकी रचनाएं अधूरी, अपरिपक्व और पाठकों के लिए योग्य नहीं है। तपेदिक से जूझते हुए जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र इस्राइली लेखक, संगीतकार और पत्रकार मैक्स ब्रॉड से कहा, 'मेरी मौत के बाद मेरी सारी पांडुलिपियां जला देना। जो कुछ लिखा है, वह प्रकाशित होने योग्य नहीं है।' यह उनकी क्षणिक भावुकता नहीं थी, उन्होंने यह बात कई बार लिखित रूप में दोहराई। उनके पास 'द ट्रायल', 'द कैसल', 'अमेरिका' जैसे उपन्यासों की अधूरी पांडुलिपियां थीं, साथ ही अनेक कहानियां और डायरी अंश भी। 1924 में काफ्का की मृत्यु के बाद मैक्स ब्रॉड एक कठिन नैतिक द्वंद्व में फंस गए कि मित्र की इच्छा मानें या साहित्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं? आखिरकार मैक्स ने काफ्का की पांडुलिपियां नष्ट नहीं कीं, उन्हें संपादित कर प्रकाशित किया। धीरे-धीरे काफ्का का लेखन दुनिया के सामने आया। इस तरह से जिस शख्स को अपने जीवन में बहुत कम पहचान मिली थी, वह 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल हो गया।

Subrata Dhar

इंटरनेट क्रांति के समय देश चूक गया, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में यह ग़लती न हो

AI ने भारत को दिया बड़ा चांस

निमिष दुबे और आकृति राणा

भारतीय टेक इतिहास में 2025 को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) के साल के रूप में याद रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल India AI मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। एक साल बाद ही, 2025 में इस निवेश को दोगुना करने की बात होने लगी।

AI का साल । इस निवेश से देश की यूनिवर्सिटीज, startup ecosystem और अन्य संस्थानों को AI में काम आने वाले हार्डवेयर - जैसे बड़े-बड़े GPU और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। AICTE ने भी 2025 को शिक्षा में AI का साल घोषित किया। इन कदमों का लक्ष्य AI क्रांति के लिए तैयार करना ही नहीं, देश का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) भी तैयार करना है - जैसे OpenAI का ChatGPT और Google का Gemini। यह लक्ष्य तय हुआ तो भारत AI की दुनिया की महाशक्ति बन सकता है।

बढ़ता बाजार । 2025 में हमें इन प्रयासों के परिणाम भी दिखे। देश में AI बाजार 2024 में 9.51 अरब डॉलर था, 2025 में यह 13.03 अरब डॉलर हो गया, जो 2032 तक 130.63 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है यानी आज की तुलना में 10 गुना! एमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी भारत के AI बाजार में अरबों डॉलर का निवेश किया है। गूगल ने AdaniConneX और एयरटेल के साथ विशाखापट्टनम में भारत का पहला बड़ा AI हब बनाना शुरू कर दिया है।

जनता तक पहुंच । 2025 में AI टूल्स न के बराबर कीमत में आम जनता को भी मिलने लगे। एयरटेल ने अपने सब्सक्राइबर्स को Perplexity AI की मुफ्त भेंट दी तो रिलायंस जियो ने सब्सक्राइबर्स को Google Gemini इस्तेमाल करने की खुली छूट। साल खत्म होते-होते बाजार में शायद ही कोई गैजेट AI से लैस होना बचा हो। सरकार, संस्थान, कॉरपोरेट और उपभोक्ता - किसी की भी नजर से देखिए, 2025 के इंडियन टेक वर्ल्ड में AI की धूम दिखाई देगी।

2025 के हीरो

iStock

शुरुआती कदम

- 13.03 अरब डॉलर का हुआ भारत का AI मार्केट
- बड़ी कंपनियां कर रही निवेश, गूगल बना रहा हब
- दिग्गजों से टक्कर लेने के लिए चाहिए भारतीय प्रॉडक्ट

अभी बस शुरुआत । मगर सच यही है कि देश में AI का यह शुरुआती दौर है। भारत में टेक दिग्गज पैसा जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इस समय AI वर्ल्ड में हमारी भूमिका वही है, जो 2000 की शुरुआत में इंटरनेट और डॉटकॉम की लोकप्रियता के समय थी यानी एक बड़े बाजार की, जिसमें काफी संसाधन कम दाम पर मिल सकते हैं।

मौका चूक गए । दो दशक पहले देश और उसके संस्थानों के पास मौका था कि इनोवेशन व खास प्रॉडक्ट्स के जरिये पूरे विश्व पर धाक जमाई जाए। आगे निकलने का वह मौका हाथ से निकल गया। नतीजा, भारत एक बड़ा टेक मार्केट तो है, लेकिन इस मार्केट में उसके अपने प्रॉडक्ट बहुत कम हैं।

भरपूर क्षमता । यही खतरा AI में भी है। भारत में निवेश तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपना कोई बहुत बड़ा उत्पाद नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हममें अपना AI इकोसिस्टम और टूल्स बनाने की क्षमता नहीं। सरकार BharatGen नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम कर रही है। इसे भारतीय संस्कारों, सभ्यता के हिसाब से रचा जा रहा है और 22 भारतीय भाषाओं के साथ काम करेगा। इसी तरह, Krutrim और Sarvam-M जैसे LLM भी भारतीय कंपनियां बना चुकी हैं, लेकिन ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा के प्रॉडक्ट्स को टक्कर नहीं दे सकते।

अपना हो AI । दुनिया के दिग्गजों से होड़ में अभी समय लगेगा। इसके लिए जरूरत होगी दूरदर्शिता, उचित निवेश और सधे नेतृत्व की। फटाफट पैसा कमाने की होड़ में हमारा देश एक बार टेक में लंबे वक्त का घाटा उठा चुका है। ध्यान रखना होगा कि वैसी गलती अब न हो। इस मामले में सरकार के AI सिखाने और पढ़ाने के कार्यक्रम जैसे 'Yuva AI for All' बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत को अपना AI चाहिए, जो उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी भारतीय ने बनाया हो।

पहली सीढ़ी । इसमें दो राय नहीं कि 2025 भारत में AI का साल था, लेकिन यह अभी पहला पायदान है। 2026 में देश को AI बाजार का बादशाह बनने की लंबी यात्रा के पहले कदम उठाने होंगे। राह आसान नहीं, कई चुनौतियां हैं, लेकिन सही निर्णय और धैर्य से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो AI का अगला Generation BharatGen का होगा।

अगर पागे नहीं होते तो G RAM G भी नहीं होता

आज VB-G RAM G पर बहस छिड़ी है। मगर देश में रोजगार की गारंटी नई बात नहीं है। 1780 में अकाल के दौरान जब लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला बड़ा इमामबाड़ा बनवा रहे थे, तब मजदूर दिन में काम करते और नवाब साहब के लोग रात में थोड़ा हिस्सा तोड़ देते थे ताकि अगले दिन भी काम जारी रहे। यह रोजगार देकर उनकी मदद करना ही था।

अभिषेक मिश्र

पागे ने बदला इतिहास । आजाद भारत में रोजगार गारंटी सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुई और इसके दशकों बाद पूरे देश में। इसके पीछे थे 18 साल तक महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रहे विट्ठल सखाराम पागे। 1960 के दशक में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो उन्होंने सांगली के तासगांव तालुका में पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किया। इससे पता चला कि 700 रुपये में 15 मजदूरों को 20 दिनों तक काम दिया जा सकता है। उन्होंने तब के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक को पत्र लिखकर पूछा कि 700 रुपये में 15 मजदूरों की मदद हो सकती है, तो 100 करोड़ में कितनों को फायदा पहुंचेगा!

शुरू हुआ परीक्षण । इसके बाद राज्य के 11 गांवों में ट्रायल हुआ और जुलाई 1969 में महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी स्कीम (EGS) की शुरुआत हुई। इसके नतीजे शानदार रहे। फिर भी केंद्र ने विरोध किया। पर पागे की विश्वसनीयता, नाइक का समर्थन और योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल की सहमति से योजना को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया गया।

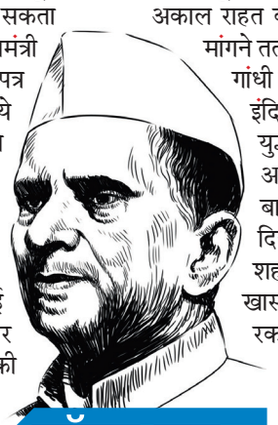

कॉमन रूम

प्रफेशन टैक्स । 1970 के दशक में राज्य में सूखा पड़ा। नाइक और पागे अकाल राहत कार्यों के लिए मदद मांगने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के पास गए। मगर, इंदिरा ने बांग्लादेश युद्ध के बाद खराब आर्थिक स्थिति की बात कहकर मना कर दिया। तब पागे ने उन्हें शहरी वेतनभोगियों पर खास टैक्स लगाकर रकम जुटाने का सुझाव दिया। इसी से EGS के लिए प्रफेशन टैक्स की शुरुआत हुई और राज्य में 1978 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ।

EGS का अध्ययन । महाराष्ट्र में EGS की मजदूरी मार्केट रेट से कम रखी गई, ताकि योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिले, जिनके पास काम नहीं था। इसलिए योजना का लाभ जरूरतमंदों ने ही लिया।

तर्क-वितर्क । मगर योजना के खिलाफ भी तर्क आए। रॉनल्ड हेरिंग्स और रेक्स एडवर्ड्स ने अपनी रिसर्च में दावा किया कि EGS को भले ही गरीबों की योजना बताया गया हो, लेकिन फायदा अमीर किसानों को हो रहा है। जवाब में अर्थशास्त्री वीएम दांडेकर और मधुसूदन साठे ने इसके फायदे गिनाए। कुल मिलाकर, EGS ने दिखाया कि सार्वजनिक कार्यों को सूखे के खिलाफ ढाल बनाया जा सकता है। भले ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) को मनरेगा का श्रेय दिया जाता है, लेकिन सचाई है कि पागे की योजना ही आगे चलकर EGS बनी और 2005 में मजदूरों को अस्थायी रोजगार देने के लिए मनरेगा शुरू किया गया।

कांटे की बात

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर और देश में लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में खालिदा जिया की भूमिका अहम रही। उनका निधन बांग्लादेश की राजनीति और BNP के लिए बड़ी क्षति है।

शेख हसीना, *पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश*

सेहत को रोज़गार से जोड़ा, तो आया बदलाव

तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की सिट्टिलिंगी घाटी में स्वास्थ्य को देखने का नजरिया आम अस्पतालों से बिल्कुल अलग है। यहां इलाज सिर्फ दवा तक सीमित नहीं – यह खेती, खान-पान और रोजगार से जुड़ा है। बदलाव की यह कहानी शुरू हुई थी साल 1993 में।

छोटी बात, बड़ा फ़र्क़

AI Image

ऑर्गेनिक खेती से सुधरा लाइफस्टाइल

डॉ. रेगी जॉर्ज और डॉ. ललिता रेगी लगभग तीन दशक पहले जब इस घाटी में पहुंचे, तो बड़ी आबादी बीमारी की चपेट में थी और वजह थी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते, वहां खराब परिस्थितियों में रहते और बीमारी लेकर लौटते। डॉक्टर दंपती ने स्थानीय लोगों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया।

किसान अपनी कंपनी से हुए आत्मनिर्भर

शुरुआत में केवल 4 किसान आगे आए थे। आज सिट्टिलिंगी की अपनी कंपनी है – SOFA, जिसका टर्नओवर 3 करोड़ है। पैसा आया, पलायन रुका, जीवनस्तर सुधरा और बीमारियां दूर हुईं। पोरगई नाम का समूह महिलाओं को सिलाई-बुनाई की ट्रेनिंग देता है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता आई।

जनता जंक्शन इरफ़ान

हमें कोई कुछ भी बेच सकता है, प्रदूषण भी

कार खरीदने का इससे 'बेहतरीन वक्त' हो सकता है क्या? GST में कटौती है ही, ईयर-एंड डिस्काउंट भी है। ये आकर्षक ऑफर तब हैं, जब प्रदूषण चरम पर है। इससे पहले फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की रेकॉर्ड बिक्री हुई। कार ही क्या, हर ई-कॉमर्स साइट पर सेल चल रही है। दिन-रात हर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है। इस समय कोई हमें कुछ भी बेच सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें असल में चाहिए क्या।

रमेश तिवारी

इंडस्ट्री की क्या गलती?

हम सभी चाहते हैं कि प्रदूषण पर नियंत्रण हो। लेकिन हम अक्सर यही ढूंढ रहे होते हैं कि इसके लिए किसे दोषी ठहराएं। पहले तो पराली पर उंगली उठी। पराली का मौसम खत्म होते ही प्रदूषण में स्पष्ट कमी आ जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी निर्माण कार्य को दोषी ठहराया जाता है, कभी तंदूर को, कभी डीजल जनरेटर को, तो कभी गाड़ियों को। इन सभी कारणों में सच्चाई के अंश हैं, लेकिन कहीं हम एक ज्यादा गहरी और जटिल समस्या को बहुत सतही ढंग से तो नहीं देख रहे।

हमें यह भरोसा दिलाया जाता है कि अब BS-6 वर्जन आ चुका है, जिससे कम प्रदूषण फैलता है। जब सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ही बेतहाशा बढ़ रही हो, तो उत्सर्जन मानकों में मामूली सुधार ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है। यहां सभी को कार के लिए उकसाया जा रहा है, जबकि चीन में कार लॉटरी से मिलती है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मानो किसी चमत्कारी समाधान की तरह पेश किया जा रहा है। तकनीकी प्रगति आवश्यक है, लेकिन ये कभी भी विवेक की जगह नहीं ले सकता। शासन और नीतियों में बदलाव अहम है, लेकिन सरकारें संस्कारों से भी नियंत्रित होती है। इंडस्ट्री को अक्सर जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन मांग तो हम पैदा करते हैं, उपभोक्ता बनकर।

हम उपभोक्तावाद के उस दौर में जी रहे हैं, जहां हम खुद नहीं जानते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। बाजार हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए। एक तरफ अधिक से अधिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अहसास कराया जा रहा है कि ये प्रॉडक्ट हमारे सुख, पहचान और सामाजिक हैसियत के लिए जरूरी हैं। नतीजतन हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनका हम शायद ही कभी उपयोग करते हैं। अपने किचन में झांकिए। वॉर्डरोब में कपड़े देखिए। नया फोन देखिए। यही मानसिकता आगे चलकर जरूरत न होने पर भी एक से ज्यादा घर, गाड़ियां और लगातार अपग्रेड करने की प्रवृत्ति में बदल जाती है। ये सब हमारे भीतर के खालीपन के प्रतीक हैं।

AI Image

जरूरत या चाहत?

कोई कह सकता है कि डिमांड से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। जरा सूक्ष्मता से गहराई से सोचकर देखिएगा, ये लाभ कहीं सिर्फ अरबपतियों को खरबपति तो नहीं बना रहा? बात विकास या सुविधा के खिलाफ नहीं है। असली चुनौती जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझने की है। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? हमारा अस्तित्व, जो अभी दांव पर है। चाहत वह है जो तुलना, ट्रेंड और दिखावे से जन्म ले। जब यह फर्क मिट जाता है, तो उपभोग की कोई सीमा नहीं रहती। किसी बंदिश का विरोध देख राजनीतिक वर्ग और इंडस्ट्री को लगता है कि हमारे लिए उपभोग बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण नहीं। प्रदूषण पर नियंत्रण केवल नियमों, ईंधन या तकनीक से संभव नहीं है। इसके लिए संयम भी चाहिए। हमारी चेतना जागे तो कोई सरकार सो नहीं पाएगी, इंडस्ट्री हमें प्रॉडक्ट की तरह नहीं देख पाएगी।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

नए वर्ष की सुंदरता अपने पवित्र भाव में तलाश कर देखिए

स्वामी सुखबोधानंद

जहां प्रेम, आनंद और सौंदर्य की तरंगें लहराती हैं, वहां पवित्र भाव का अभाव नहीं होता। फिर ये तरंगें ही हमें ईश्वर से जुड़ने में मदद करती हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि नया वर्ष तभी सजीव और अर्थपूर्ण बनेगा, जब हम अपने भीतर इन तरंगों की ऊर्जा को प्रवाहित होने देंगे।

एक सच्चा गुरु या सद्गुरु शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से इन तरंगों का संचार करते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को शब्दों से अधिक अपनी उपस्थिति के माध्यम से ज्ञान दिया। यदि वह कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल शब्दों से अर्जुन को ज्ञान देते तो इसमें घंटों लग जाते। हो सकता है, समझाते-समझाते लंबा वक्त लग जाता है। उस समय वहां दो हृदयों के बीच हुआ संवाद था, शब्दों और समय से परे, जो श्रीकृष्ण की उपस्थिति से निकली ऊर्जा तरंगों से संपन्न हुआ।

AI Image

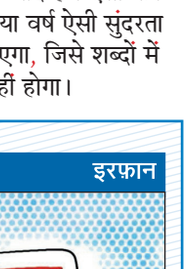

एक सपना शायद केवल दो मिनट का होता है, लेकिन नींद से जागने के बाद उसे बताने में एक घंटा लग सकता है।

किसी गुरु के पास जाने से पहले अपने मन को शांत करें। अपने मन के अंदर प्रेम, आनंद और सौंदर्य का भाव भरने दें। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु और शास्त्र है, इसलिए उसके साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार करें। हम उस कैटरपिलर की तरह हैं, जिसे यह पता नहीं होता कि वह तितली बन सकती है। हमें भी यह बोध नहीं होता कि हम बुद्ध (ज्ञानी) बन सकते हैं।

चीन का एक बढ़ई, जिसने अपनी कला के एक से बढ़कर एक नमूने बनाए थे, उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया। उसने कहा, 'मैं किसी पेड़ के पास गहरे प्रेम और आनंद के साथ जाता हूं, उससे पूछता हूं कि क्या वह कटने के लिए तैयार है। जब मेरी अंतरात्मा किसी विशेष पेड़ के लिए 'हां' कहती है, तभी मैं हृदय में प्रार्थना लिए उस पेड़ को काटता हूं।' इसी भाव से वह अद्भुत कृतियां रच सका।

क्या हम जीवन को दिव्यता की अनुभूति के साथ जी सकते हैं? यदि हम ऐसा कर पाएं, तो हमारे लिए नया वर्ष ऐसी सुंदरता और गहराई से भर जाएगा, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होगा।

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

सराहनीय कदम

30 दिसंबर का संपादकीय 'संतुलन की जरूरत' पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के मामले पर पुनर्विचार की जो पहल की, वह सराहनीय है। दरअसल अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने का प्रश्न पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मसला है। इसे बेहद संवेदनशीलता से बरतने की जरूरत है। हल्की सी चूक का विनाशकारी नतीजा लोगों को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। वैसे भी हम पर्यावरण का बुरा हाल कर बैठे हैं। विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन हो रहा है। उम्मीद है कि अदालत इस मुद्दे पर आखिरकार संतुलित नजरिया अपनाएगी।

पैथर तोमर, किशन गंज

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)